राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

यह देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल और युवा को बेहतर कल मिलेगा। मध्यम वर्ग को प्रगति और विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। गरीब देश के विकास का पावर हाउस बनेंगे।

–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 26

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 6 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

नए भारत की ओर

लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना और अपनी छवि बरकरार रखना शायद इसे ही कहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार-2 के पहले बजट ने बड़ी और नई लोकलुभावन घोषणाओं से बचते हुए केवल उन्ही बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित रखा है जो सरकार का मूल मंत्र है- सशक्त भारत, नया भारत। इस क्रम में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को तरजीह दी गई है, जो मोदी सरकार की दोबारा वापसी के सूत्रधार रहे। वहीं, सुधार के लिए सख्त और मुश्किल कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया है। दरअसल, मोदी सरकार की यही पहचान रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसका इजहार भी करते रहे हैं कि पहले चार साढ़े चार साल केवल शासन और आखिर के कुछ महीनों में राजनीति। मोदी जानते हैं कि जनता ने उनकी इसी कार्यशैली से प्रभावित होकर वोट दिया है और अगली समीक्षा होनी है तो वह भी नए भारत की लक्ष्य प्राप्ति पर ही होनी है, जिसमें अंतिम व्यक्ति भी भारत के गौरव का साधन बनेगा। करदाताओं की साख बढ़ेगी, अमीरों का योगदान बढ़ेगा और भारत विकसित देशों के कई मानकों पर खरा उतरेगा। इस बजट से इतना संकेत जरूर मिलता है कि आने वाले वर्षों में सरकार का पूरा ध्यान शायद इन्हीं बिंदुओं पर रहेगा।

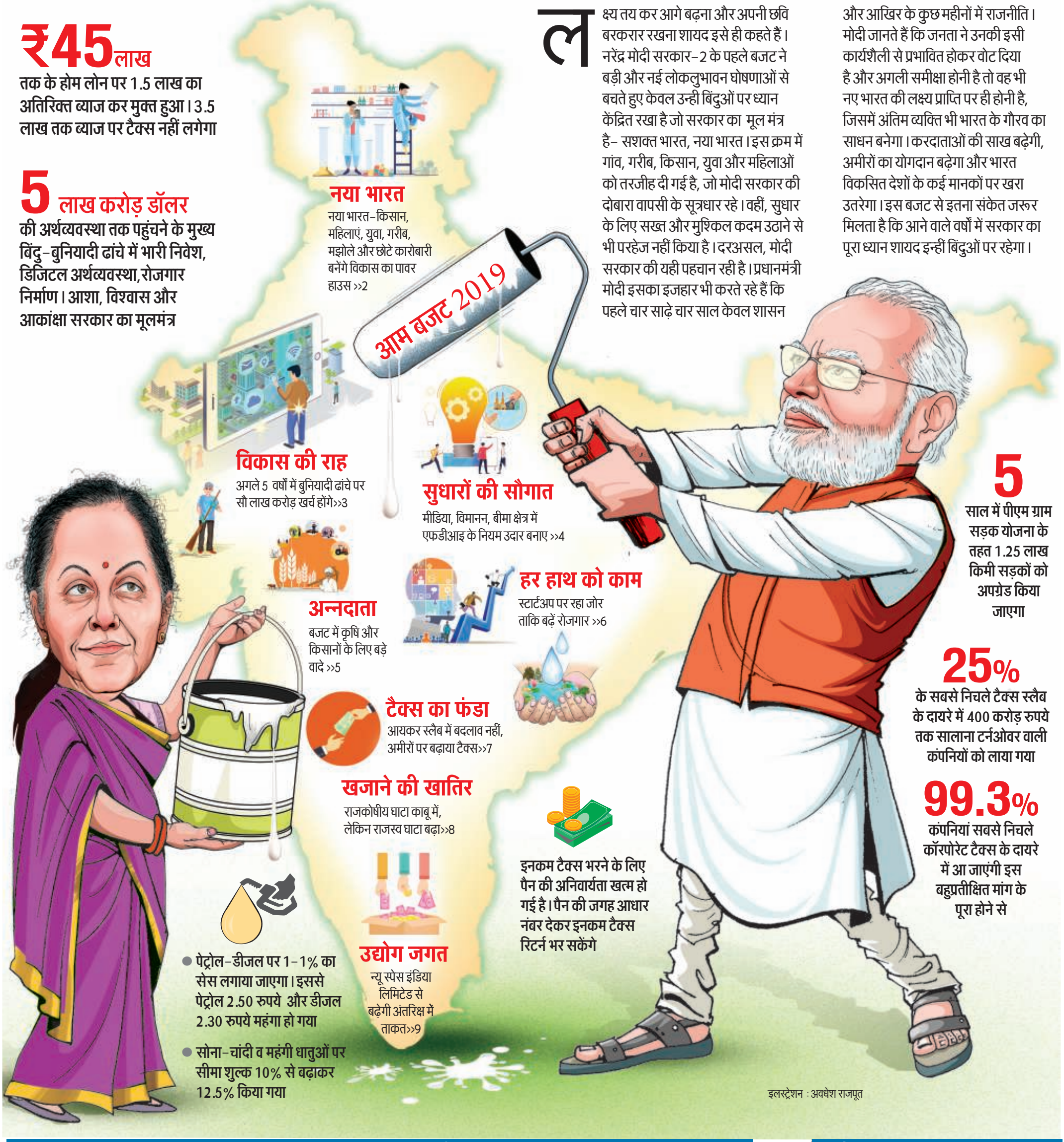

इलस्ट्रेशन : अवधेश राजपूत

बजट और जागरण सरोकार

नारी सशक्तीकरण

- जनधन खाते से पांच हजार रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा
- नारी तू नारायणी योजना लांच करने का एलान
- इसके तहत एक कमेटी देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी पर सुझाव देगी

जल संरक्षण

- 2024 तक हर घर जल योजना को लागू करने की घोषणा
- 256 जिलों में जल प्रबंधन में सुधार किया जाएगा
- इस योजना के तहत इस्तेमाल पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए होगा
- सरकार ने जलशक्ति मंत्रालय के गठन का एलान किया

जनसंख्या नियोजन

- युवाओं को स्टार्ट अप की ओर प्रेरित करने के लिए स्टार्ट अप टीवी चैनल लांच किया जाएगा
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से एक करोड़ युवाओं को जोड़ा जाएगा
- युवाओं को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3डी प्रिंटिंग की ट्रेनिंग मिलेगी

गरीबी उन्मूलन

- छोटे दुकानदारों को तीन हजार पेंशन, तीन करोड़ से ज्यादा को होगा फायदा
- 2022 तक सभी को घर। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा
- 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ अगले पांच साल में बनेंगे, जीरो बजट खेती पर जोर

पर्यावरण संरक्षण

- उज्ज्वला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण
- तीन साल में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार
- ई-वाहनों के लिए लोन लेने पर 1.50 लाख तक के ब्याज पर आयकर छूट

सुशिक्षित समाज

- शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी
- 400 करोड़ रुपये से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव
- स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहन

स्वस्थ समाज

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है
- 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 2022 तक स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों में बदला जाएगा
- जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित होंगे

चुनाव से पहले अंतरिम बजट में लोकलुभावन वादों से किया परहेज और अब पूर्ण बजट में भी ● पिछले बजट में पेश भारत निर्माण योजना पर बढ़ाया कदम

भरोसे की कसौटी पर खरी मोदी सरकार

त्वरित टिप्पणी

प्रशांत मिश्र

एक बजट आज से चार महीने पहले आया था जिसे चुनावी माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि चुनाव जीतने के लिए सरकार ने पासा फेंका है। हालांकि उस वक्त भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस बहुत खुश थी कि उसकी न्यूनतम आय योजना के मुकाबले केंद्र सरकार के बजट में कोई बहुत बड़ा लोकलुभावन वादा नहीं किया गया था। जनता ने लोकलुभावन वादों के ऊपर एक ऐसे बजट को अहमियत दी जो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो।

मोदी सरकार का एक बजट शुक्रवार को आया जिसने पुरानी सोच को और आगे बढ़ाते हुए यह संदेश दिया है कि चार माह पूर्व पेश बजट भी सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि देश की जरूरत को समझते हुए व्यावहारिक बजट था। यह संदेश भी साफ है कि सरकार को जनता पर भी भरोसा है और खुद पर भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहते हुए इसका इजहार भी कर दिया, 'यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।' पांच साल की सत्ता के बाद मोदी सरकार-2 के लिए शायद यही मूल मंत्र है।

वैसे इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता के 70 साल तक भारत की बड़ी आबादी को आवास, शौचालय और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए रोजाना जूझना पड़ता था तो उसका सबसे बड़ा कारण था निष्पादन का न होना। घोषणाएं बड़ी पर क्रियान्वयन नदारद। कांग्रेस से इतर भी लोगों के लिए यह सोचने का वक्त है कि लोकलुभावन 'न्याय' के जरिये हर गरीब को 72 हजार रुपये देने की घोषणा परवान शायद इसीलिए नहीं चढ़ सकी क्योंकि उनकी सरकारों में क्रियान्वयन हमेशा बड़े सवालों के घेरे में रहा था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार की सोच लगातार इससे जुदा रही है। बजट में भी इसी की झलक दिखती है। बड़ी घोषणाओं का न होना कुछ लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह विश्वास भी पैदा करेगा कि जो बातें कही गई हैं वे पूरी होंगी। पिछले बजट में भारत निर्माण की एक तस्वीर पेश की गई थी, सरकार उसी पर ठोस कदम बढ़ाना चाहती है। अगले तीन साल में जब स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होंगे तो नए भारत के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह अगले एक दशक के लिए 10 सूत्र रखे गए हैं और अंतिम व्यक्ति तक विकास की निर्बाध धारा पहुंचाने के लिए आवास, स्वच्छता, पेयजल, बिजली आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ है, उसे देखते हुए मानना पड़ेगा कि एक ईमानदार कोशिश हुई है। सही मायने में यह बजट गांव, शहर, गरीब, अमीर, युवा, महिला सबको अवसर प्रदान करता दिखता है- देश निर्माण में सहभागिता के लिए।

ऐसे माहौल में जब देश की बड़ी आबादी पर्यावरण का दंश झेल रही है तो बजट में सरकार की ओर पर्यावरण स्वच्छता को लेकर दिखता प्रयास सराहनीय भी है और सरकार की इस मंशा को भी उजागर करता है कि वह लंबी सोच के साथ काम करेगी। मोदी सरकार की एक खासियत है और धीरे-धीरे यह स्थापित होता जा रहा है कि वह घिसी पिटी परंपराओं से दूर चलती है। ध्यान रहे कि पहली बार सत्ता में आने के बाद ही सरकार ने रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा को अलविदा कह दिया था। बाद में रेल बजट को भी आम बजट का हिस्सा बना दिया गया। राजनीतिक हथियार बने रेल बजट को मोदी सरकार के इस कदम ने कुंद कर दिया था। शुक्रवार को पेश बजट के जरिये सरकार ने फिर संदेश दिया है कि वक्त सिर्फ घोषणाओं का नहीं, निष्पादन का है। यह वक्त है सही व्यक्ति और समूह पर केंद्रित होकर काम करने का। अंतिम व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने से लेकर देश के गौरव को पुनःस्थापित करने का। इस बजट ने इन्हें साधने का प्रयास किया है। हां, यह जरूर है कि सरकार का कार्यकाल भले ही पांच साल का है, लेकिन इसकी पूरी समीक्षा अगले तीन साल में होगी। आंका जाएगा कि देश की अपेक्षा पर मोदी सरकार कितना खरा उतरी है।

पांच का दम

1. बजट में गरीबों के कल्याण और विकास में संतुलन साधने का प्रयास है। गांव, गरीब, किसानों का ध्यान रखा गया तो आधारभूत ढांचे और उद्योगों के विकास पर भी जोर है।
2. खजाना भरने में उच्च आय वर्ग का सहारा लिया है। दो करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर 3 फीसद और 5 करोड़ से ऊपर आय वालों पर 7 प्रतिशत का सरचार्ज लगाया गया है।
3. केंद्रीय वित्त मंत्री ने एलान किया कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर होगा काम। वहीं, किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट आंत्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा।
4. मोदी सरकार-2 ने अपने पहले बजट का उपयोग समग्र सुधारों की दिशा में कदम उठाने में किया और पूरी बेबाकी से एफडीआइ से लेकर श्रम कानूनों में सुधार का एलान किया।
5. सरकार का जोर भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर दिखा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन पर 1.50 लाख रुपये तक ब्याज पर आयकर में छूट मिलेगी।

दैनिक जागरण
www.jagran.com
06 जुलाई, 2019
आम बजट 2019

डाटागीरी

आंकड़े अहम होते हैं। सब कुछ कह देते हैं। हाल-ए-हकीकत भी बयां करते हैं। आम जीवन में घर खर्च से लेकर बचत तक की कथा-कहानी बगैर आंकड़ों के नहीं गढ़ी जा सकती। ये गोल-मोल नहीं होते, निशाने पर सीधे लगते हैं... तीर की तरह। सच्चे और खरे होते हैं, इसीलिए जिनके मन की बात नहीं पूरी करते, उनको वे बुरे भी लगते हैं।

शेयर बाजार की ठंडी प्रतिक्रिया

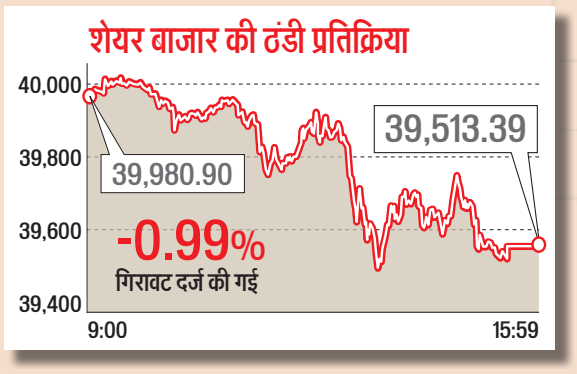

17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय रूप देकर विकसित किया जाएगा

35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए

5:00 बजे शाम की परंपरा को तोड़कर यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू किया

92 साल पुराने रिवाज को पीछे छोड़कर रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने की मंजूरी मोदी सरकार ने 21 सितंबर, 2016 को दी

₹27,86,349 करोड़ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए आम बजट का विशाल आकार

1 लाख करोड़ डॉलर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में देश को 55 साल लगे। पिछले पांच साल में मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ डॉलर इसमें जोड़ा।

बजट बन गया बही-खाता

वाजपेयी कार्यकाल में बदला था समय, मोदी सरकार में तिथि और तस्वीर बदल गई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नई सरकार के पहले बजट में नयेपन के भी कुछ रंग देखने को मिले। वित्त मंत्री का बजट भाषण और वित्त विधेयक की प्रतियां ब्रीफकेस से निकलकर अब पुराने पारंपरिक बही-खाते के दौर में लौट आया है। पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करने लोकसभा में पहुंची तो बजट को ब्रीफकेस की बजाय लाल कपड़े में बंधे बही खाते में लाने की नई परंपरा का आगाज किया। अभी तक वित्त मंत्री ब्रीफकेस में ही बजट लेकर सदन में आते थे। मगर वर्तमान वित्त मंत्री ने इस पुरानी परंपरा को बदल दिया है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने लाल कपड़े सरीखे बही-खाते में बंधे बजट की तस्वीर ट्वीट कर पश्चिम की परंपरा बदलने की बात भी कही है। वैसे एनडीए की अब तक की तीनों सरकारों ने बजट की पुरानी परंपरा में बदलाव करने में हिचक नहीं दिखाई है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सबसे पहले 2000 में शाम पांच बजे बजट पेश करने की चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इसे सुबह ग्यारह बजे पेश करने का सिलसिला शुरू किया। शाम पांच बजे बजट पेश करने का सिलसिला अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था और तब उस समय लंदन की सुबह के समय के हिसाब से भारत में शाम को बजट पेश किया जाता था।

पहले ब्रीफकेस में बजट पेश होता था। निर्मला सीतारमण ने इस बार लाल कपड़े में लिपटा बही खाता पेश किया • प्रेट्र

नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद 2016 में 28 फरवरी को बजट पेश करने की दूसरी परंपरा तोड़ डाली। मोदी सरकार ने 28 की जगह एक फरवरी को बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू की। इसके पीछे तर्क था कि देरी से बजट पारित होने के चलते आवंटित राशि पहुंचने में ही चार-पांच महीने लग जाते हैं। ऐसे में राशि सही तरीके से खर्च करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और मार्च में आपाधापी में इसे खर्च किया जाता है। मोदी सरकार की दूसरी पारी में निर्मला सीतारमण ने अब ब्रीफकेस की जगह बही-खाते के अंदाज में सदन में बजट ले जाने की नई परंपरा शुरू की है।

विल्सन ने रखी थी बजट की नींव

भारत का पहला पहला बजट जेम्स विल्सन ने सात अप्रैल, 1860 को पेश किया था। इन्होंने ही आगे चलकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इकोनॉमिस्ट पत्रिका की स्थापना की। हैट मेकिंग से कमाई कर वित्तीय और अर्थशास्त्र की शिक्षा लेने वाले विल्सन अपनी प्रतिभा के दम पर अविभाजित भारत के वायसराय लार्ड कैनिंग की वित्तीय समिति के सदस्य चुने गए। 1859 में वे पहली बार भारत आए थे।

बजट के बाजीगर

भारत को पांच लाख करोड़ वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी सरकार 2.0 ने प्रतिबद्धता दर्शायी है। यह बजट उस लक्ष्य का वाहक बना है। आइए एक छोटी-सी मुलाकात कराते हैं निर्मला सीतारमण के उन बाजीगरों से, जिनके भरोसे और अनुभव के सहारे इस बजट को तैयार किया गया...

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

1984 में जवाहर लाल नेहरू विवि से अर्थशास्त्र में एमफिल किया। पति पराकला प्रभाकर को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्कॉलरशिप मिली तो उन्हें लंदन जाना पड़ा। लंदन के प्रसिद्ध स्टोर हैबिटेट में सेल्सगर्ल की नौकरी भी की है। इंग्लैंड के एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एसोसिएशन के अर्थशास्त्री की सहायक, प्राइस वाटर कूपर्स जैसी संस्था में सीनियर मैनेजर के साथ ही बीबीसी की वैश्विक सेवा में भी काम किया। शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है। श्रीकृष्ण के भजनों का संग्रह उनके पास है।

अनुराग ठाकुर
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री

24 अक्टूबर, 1974 को जन्मे अनुराग ठाकुर लगातार चौथी बार लोकसभा में पहुंचे हैं। रणजी और एक प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेल चुके अनुराग हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं। वे बीसीसीआइ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे भाजपा के पहले लोकसभा सदस्य हैं जिन्हें टेरीटोरियल आर्मी में स्थायी कमीशन मिला।

कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार

शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में एमबीए और पीएचडी की डिग्री लेने वाले के. सुब्रमणियन रघुराम राजन और लुईगी जिंगालेस के छात्र रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने आइआइटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। सेबी, रिजर्व बैंक सहित कई संस्थानों की एक्सपर्ट कमेटी में भी रहे हैं।

सुभाष गर्ग
वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव

1983 बैच के आइएएस अफसर वैश्विक बैंक के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। एलएलबी की डिग्री के साथ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। 1989 में कंपनी सेक्रेटरी की फाइनल परीक्षा में पहले स्थान पर रहे। विकास दर कम होने, उपभोग घटने, निजी निवेश घटने के हालात में राजकोषीय मजबूती बनाए रखने की दिशा में जुटे हुए हैं।

अजय भूषण पांडेय
राजस्व सचिव

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के सीईओ रहते हुए 1984 बैच के इस आइएएस अफसर ने आधार कार्ड को सिरे चढ़ाया। आधार के खिलाफ 37 याचिकाओं की सुनवाई करने वाली बेंच को दो दिन तक प्रजेंटेशन से बताया कि आधार क्यों लाभदायक है। सब्सिडी को सीधे बैंक खातों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई।

जीसी मुर्मू
व्यय सचिव

1985 बैच के आइएएस गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। उनकी नजदीकी अमित शाह से भी रही है। वे वित्त और राजस्व सेवाओं में भी रह चुके हैं। बर्मिंघम से एमबीए की डिग्री लेने वाले मुर्मू अपने मित्रों के बीच चतुर दिमाग वाले एक ऐसे नौकरशाह के रूप में जाने जाते हैं जिसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है।

राजीव कुमार
वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव

1984 बैच के इस अधिकारी ने उच्च शिक्षा दिल्ली विवि से प्राप्त की। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सीमम गवर्नेंस के मकसद को हासिल करने के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष तथा नीति आयोग पुनर्गठन के लिए कार्यबल के ये सदस्य रह चुके हैं। सार्वजनिक बैंकों के विलय, फंसे कर्जों पर अंकुश आदि पर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्वच्छ भारत मिशन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस से साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करने वाली मोदी सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक 51314.3 करोड़ रुपये आवंटित किए लेकिन 48,909.2 करोड़ रुपये ही इस्तेमाल किए गए। सरकार का दावा है कि इस मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों में से 90 फीसद की जीयो टैगिंग भी कर ली गई है। प्रत्येक शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसका 60 फीसद केंद्र और 40 फीसद राज्य सरकार देती है। पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में केंद्र की हिस्सेदारी 90 फीसद तक होती है। आइए जानते हैं पांच वर्षों में स्वच्छ भरत मिशन पर किस वर्ष में क्या स्थिति रही...

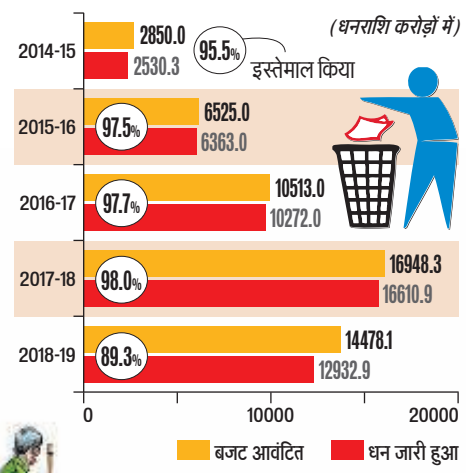

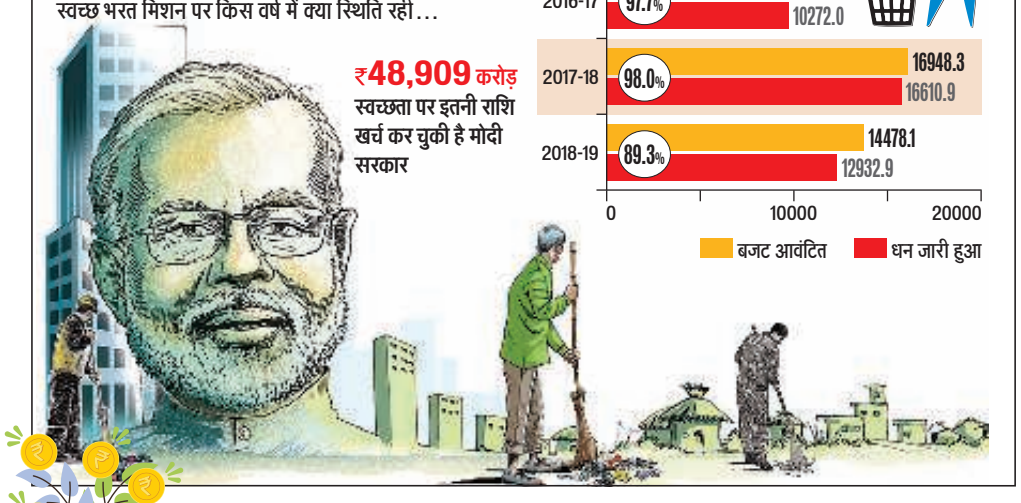

₹48,909 करोड़ स्वच्छता पर इतनी राशि खर्च कर चुकी है मोदी सरकार

बजट एक नजर में

सभी राशि करोड़ रुपये में हैं

विषय	2017-18 वास्तविक	2018-19 अनुमान बजट	2018-19 अनुमान संसाधित	2019-20 बजट अनुमान
1. राजस्व प्राप्तियां	14,35,233	17,25,738	17,29,682	19,62,761
2. कर राजस्व	12,42,488	14,80,649	14,84,406	16,49,582
3. कर भिन्न राजस्व	1,92,745	2,45,089	2,45,276	3,13,179
4. पूंजी प्राप्तियां	7,06,740	7,16,475	7,27,553	8,23,588
5. ऋणों की वसूली	15,633	12,199	13,155	14,828
6. अन्य प्राप्तियां	1,00,045	80,000	80,000	1,05,000
7. उधार और अन्य देयताएं	5,91,062	6,24,276	6,34,398	7,03,760
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	21,41,973	24,42,213	24,57,235	27,86,349
9. कुल व्यय (10+13)	21,41,973	24,42,213	24,57,235	27,86,349
10. चालू खाते पर	18,78,833	21,41,772	21,40,612	24,47,780
11. ब्याज भुगतान	5,28,952	5,75,795	5,87,570	6,60,471
12. पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	1,91,034	1,95,345	2,00,300	2,07,333
13. पूंजी खाते पर	2,63,140	3,00,441	3,16,623	3,38,579
14. राजस्व घाटा (10-1)	4,43,600	4,16,034	4,10,930	4,85,019
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	2,52,566	2,20,689	2,10,630	2,77,626
16. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	5,91,062	6,24,276	6,34,398	7,03,760
17. प्राथमिक घाटा (16-11)	62,110	48,481	46,828	43,289

9.6 करोड़ : शौचालयों का किया गया है निर्माण। 1017 शहरों के 45 हजार सार्वजनिक शौचालयों को गूगल मैप से जोड़ा गया है।

₹18341 करोड़ : कीमत की बिजली एलईडी बल्ब से बचाई गई

30000 किमी : ग्रीन टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है प्लास्टिक से निर्मित सड़क

यह बजट अगले पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहला कदम है।

अरुण जेटली,
पूर्व वित्त मंत्री

समुद्र की तलहटी से अंतरिक्ष के शून्य तक संभावनाएं ढूंढती सरकार

मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ब्लू इकोनॉमी (समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था) और स्पेस इकोनॉमी (अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था) पर विशेष जोर देने की बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि यह सरकार समुद्र की तलहटी से लेकर अंतरिक्ष तक में अपनी ताकत बढ़ाने जा रही है ताकि भविष्य में आर्थिक मोर्चों के लिए भारत कमजोर न पड़े। आने वाले वर्षों में ये दोनों ही क्षेत्र कमाई का बड़ा जरिया बनने जा रहे हैं, लिहाजा यह सरकार भी जोर लगा रही है। आखिर समुद्र की गहराई से अंतरिक्ष के शून्य तक का सफर सरकार क्यों तय करना चाहती है, इसकी कुछ वजहें बता रहे हैं रवि प्रकाश तिवारी...

अंतरिक्ष का बाजार एक लाख करोड़ डॉलर

अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं अपार हैं और बहुत कम देश हैं जो इन संभावनाओं को अवसर बना सकते हैं। भारत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में अंतरिक्ष के जरिए 400 अरब डॉलर का बाजार है और इसमें 43 अरब डॉलर से अधिक हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की है। वर्ष 2040 तक यह बाजार बढ़कर एक लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।

भारत शीर्ष चार शक्तियों में

भारत इसी वर्ष अंतरिक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक कर अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश बन गया है। भारत ने तय किया है कि वह स्पेस स्टेशन भी खोलेगा। खुद को और समृद्ध कर भारत व्यावसायिक संभावनाओं को भी ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में कर सकता है।

ये बनते हैं कमाई का जरिया

अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष खान, दूसरे देशों के लिए सेटेलाइट भेजकर उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना, नए सेटेलाइट ऑपरेटर तैयार करना, सेटेलाइट की स्थायी और अस्थायी सेवा मुहैया कराना, रिमोट सेंसिंग को और समृद्ध करना आदि।

1962 में पहली बार हुआ था व्यावसायिक इस्तेमाल

टेल्सटर-1 सेटेलाइट के जरिए पहली बार अंतरिक्ष का व्यावसायिक इस्तेमाल हुआ था। इसके जरिए ही पहली बार टेलीविजन सिग्नल, टेलीफोन, फैक्स के सिग्नल व अन्य डाटा का प्रसारण संभव हुआ था। यह एक निजी कंपनी का प्रयास था।

समुद्र को मथिए, 3.2 लाख करोड़ की अर्थव्यस्था निकलेगी

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि समुद्र में 2030 तक 3.2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था छिपी है। अगर इसे ठीक से मथा जाए तो इसका बड़ा हिस्सा हमारी झोली में आ सकता है। 2010 में यह महज 1.5 लाख करोड़ तक ही सीमित थी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने इस दिशा में अब ध्यान देना शुरू किया है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ निकलेगा क्योंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और बड़ा हिस्सा इसकी जद में है।

समुद्र की गहराईयों में छिपा है खूब खजाना

भारत अब तक समुद्री तेल और मछली पकड़ने को ही आय का मुख्य जरिया बनाता रहा है, लेकिन अब इस दिशा में और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। खासकर पर्यटन उद्योग, समुद्री ऊर्जा पैदा करने, समुद्री खनन पर भी फोकस किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में समुद्री पर्यटन तेजी से बढ़ा है और क्रूज कंपनियों ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। एशियाई क्रूज को संचालित करने वाले संगठन का आकलन है कि प्रतिवर्ष कम से कम 8 फीसद वृद्धि इस क्षेत्र में होती रहेगी। समुद्री लहरों से पैदा होने वाली ऊर्जा को संरक्षित करने का प्रयोग सफल रहा है। बड़े पैमाने पर इसका लाभ उठाने की योजना है।

सरकार की कमाई और खर्च

सरकार की एक रुपये कमाई किन मदों से आती है और एक रुपया किन मदों में खर्च होता है :

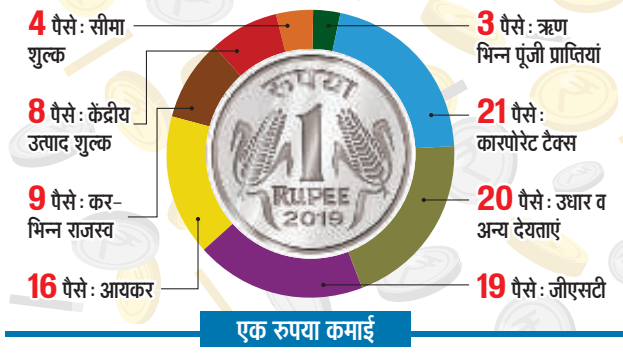

...ताकि हो मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग

1971 के बाद से देश में जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों को आशंका है कि आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत भी कहीं श्रम शक्ति की कमी से न जूझने लगे। ऐसे में समय रहते ही इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसी समस्या से पार पाने के लिए दुनिया के कई देशों ने अपने यहां रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। भारत ने भी इस दिशा में खाका खींचना शुरू कर दिया गया है। इसकी झलक सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में दिखा भी दी है। आइए जानते हैं आखिर कौन वे बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र 70 वर्ष किए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं...

जवान घट जाएंगे, बुजुर्ग बढ़ जाएंगे

उम्र सीमा	वर्ष 2011	वर्ष 2041
0-19 वर्ष	41%	25%
60 से अधिक	8.6%	16%

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2021-31 के बीच प्रजनन दर में एक फीसद जबकि 2031-41 के बीच आधा फीसद की और गिरावट आ सकती है। ऐसे में भारत के सामने भी चीन जैसी चुनौती न खड़ी हो जाए, श्रम शक्ति का अभाव परेशानी का सबब न बने, इसकी खातिर अभी से इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।

13 राज्यों में प्रजनन दर घटी

वर्तमान में देश की प्रतिस्थापन प्रजनन दर प्रत्येक महिला के 2.1 बच्चे तक की आंकी गई है। लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि देश के 13 राज्यों की प्रजनन क्षमता 1.6-1.7 बच्चे प्रति महिला ही रह गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जहां 2.1 से अधिक है वहां भी यह आंकड़ा नीचे ही गिर रहा है।

पेंशन मद पर बढ़ता खर्च

जीवन प्रत्याशा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में समाज का एक बड़ा हिस्सा रिटायरमेंट की दहलीज को पार का चुका होगा। उनके पेंशन फंड का दायरा बढ़ता जाएगा। बगैर किसी काम के पेंशन की जगह उनके अनुभव और समय का इस्तेमाल कर श्रम संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो यह फायदे का सौदा होगा। यही वजह है कि दुनियाभर के कई देश इस राह पर काफी आगे निकल चुके हैं।

70 वर्ष- रिटायरमेंट की उम्र करने की दिशा में जापान बहुत सधे कदम से आगे बढ़ रहा है।

2045 बुढ़ाती आबादी से परेशान चीन एक बच्चा नीति खत्म कर चुका है। अब 2045 तक सेवानिवृत्ति आयु 65 करने पर विचार कर रहा है।

2023 आस्ट्रेलिया में 67 वर्ष हो सकती है रिटायरमेंट की उम्र। अगले चार साल में इस पर ठोस फैसले लिए जा सकते हैं।

2023 जर्मनी रिटायरमेंट की उम्र 66 साल और 2029 में 67 वर्ष करने की ओर बढ़ रहा है

1960 के बाद जन्मे लोगों की रिटायरमेंट की उम्र अमेरिका में 67 वर्ष की जा सकती है

2020 इंग्लैंड 66 जबकि 2026 में 67 और 2041 में रिटायरमेंट की उम्र 68 वर्ष करने का खाका खींच रहा है

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 26

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 6 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

बजट में ग्रामीण इलाकों का खास ध्यान रखा गया है। हमने बजट के जरिये एक बेहतर भारत बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को भी बजट में समाहित किया गया है।

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

394.67

अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 39513.39 जबकि निफ्टी 135.60 अंक की गिरावट के साथ 11,811.15 के स्तर पर बंद हुआ

बजट की खास बातें

- एक राष्ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत किफायती दरों पर राज्यों को बिजली।
- मोटरवाहन के पुर्जे, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटीवी पर सीमा शुल्क कर में वृद्धि।
- भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पांच वर्ष पहले 11 वें स्थान पर था।
- क्रय शक्ति की समानता के रूप में हम चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
- मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में टैक्स स्लैब्स में बदलाव नहीं किया गया।

महंगा हुआ

- पेट्रोल और डीजल
- सिगरेट, हुक्का, तंबाकू
- सोना और चांदी
- लक्जरी कार जैसे, मर्सीडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वोल्वो
- स्पिलिट एसी, लाउडस्पीकर
- डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
- आयातित किताबें, सीसीटीवी
- आयातित प्लास्टिक
- साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल
- ऑप्टिकल फाइबर
- सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स, संगमरमर की पट्टियां
- वाहनों के आयातित कल-पुर्जे

सस्ता हुआ

- बैट्री से चलने वाले वाहनों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर
- सेटअप बॉक्स, आयातित रक्षा उपकरण, जिनका निर्माण भारत में नहीं किया गया हो

27,86,349

करोड़ रुपये का बजट पेश किया देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यह अंतरिम बजट से 2,149 करोड़ रुपये ज्यादा है

₹70

हजार करोड़ रुपये की नई डोज दी गई है बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने को

दूसरी पारी में दमदार आगाज

सरकार ने सुधारों की प्रक्रिया जारी रखी, गरीबों के कल्याण पर पूरी तरह अडिग

बजट में ग्रामीण इलाकों का खास ध्यान रखा गया है। हमने बजट के जरिये एक बेहतर भारत बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को भी बजट में समाहित किया गया है।

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

नितिन प्रधान ● नई दिल्ली

भारी बहुमत से सत्ता में लौटी मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट का अंदाज भी दमदार है। भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की विशालकाय अर्थव्यवस्था बनाने की सारी तरकीबें इसमें हैं तो समाज के हर उस वर्ग की जरूरतों को साधने की कोशिश भी है जिसने भाजपा की ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया था। इसमें गांव, गरीब व वंचित वर्ग को पूरी तरजीह देने के साथ ही आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को सुधारों की पुरजोर डोज भी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में सामाजिक विकास पर अधिक खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नए रास्ते तलाश कर राजकोषीय संतुलन भी बनाए रखा है।

इस बजट में समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और आर्थिक विकास का लक्ष्य पाने के लिए सभी जरूरी सुधार करने की सरकार की सोच को आगे बढ़ाया गया है। इसी के तहत एक तरफ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आवंटन बढ़ा है। दूसरी ओर आर्थिक सुस्ती से परेशान उद्योग जगत को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स की 25 फीसद दर के दायरे में ज्यादा कंपनियों को शामिल किया गया है। अब इस दायरे में 99.7 फीसद कंपनियां शामिल हो जाएंगी। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं है, जिससे मध्यम वर्ग को थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन, सरकार ने अमीरों पर सरचार्ज को बढ़ाकर आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाया है। इसमें देश के बुनियादी ढांचे के लिए अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश की दरकार को पूरा करने का एक रोडमैप भी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बजट पेश करते वक्त ही स्पष्ट कर दिया कि यह बजट उनकी सरकार की सोच की निरंतरता को दर्शाता है। अगले पांच साल में देश को पांच लाख करोड़ डॉलर (वर्तमान मूल्य पर 350 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ-साथ बजट में ग्रामीण भारत के अलावा शहरी गरीबों को भी तवज्जो मिली है। तात्कालिक कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट में पेश विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए सीतारमण ने आम बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर देने के साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास का लक्ष्य 2022 तक पाने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। यही वजह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 45 लाख रुपये तक की कीमत का मकान खरीदने पर डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त छूट की सौगात दी गई है।

सरकार ने सभी श्रम सुधारों को चार श्रम संहिता में समेटने का फैसला किया है। वहीं, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बीमा क्षेत्र में सौ फीसद एफडीआइ के साथ-साथ सिंगल ब्रांड रिटेल में भी विदेशी निवेश लाने के उपाय करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। साथ ही एनबीएफसी को संकट से उबारने और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठा है तो बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने को 70 हजार करोड़ रुपये की नई डोज दी गई है। नकदी के प्रचलन को कम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। अब सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि खातों से निकालने वालों का 2 फीसद टीडीएस कट जाएगा। बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने संसाधन जुटाने के नए रास्ते भी तलाशे हैं।

मसलन, सरकारी उपक्रमों में हिस्सेदारी को 51 फीसद से नीचे लाने पर विचार करने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों से विदेशी मुद्रा में कर्ज जुटाने के उपायों का एलान किया गया है। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी व सोना-चांदी समेत सभी कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि कर 25,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का इंतजाम किया है।

नई उम्मीद

- ग्रामीण भारत के विकास के साथ-साथ शहरी गरीबों को भी बजट में तवज्जो मिली
- एनबीएफसी को मजबूती देने के उपाय, बैंकों को मिला बूस्टर डोज

45 लाख तक की कीमत का मकान पहली बार खरीदने पर डेढ़ लाख तक के ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज छूट

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए बैंक लोन पर खरीदे गए वाहनों पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी माफ किया गया है।

विश्व की छठी अर्थव्यवस्था हुआ भारत

वित्त मंत्री ने कहा, 'चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था तीन लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। बीते वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था का आकार 2.7 लाख करोड़ डॉलर था।' साथ ही भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था हो गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट का आकार 27,86,349 करोड़ का है जो इसी वर्ष पहली फरवरी को पेश अंतरिम बजट से 2,149 करोड़ ज्यादा है। सरकार खर्च बढ़ाने के बावजूद राजकोषीय घाटा 3.3 फीसद पर बनाए रखने में कामयाब रही है। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई तरह के कच्चे माल पर ड्यूटी घटाई गई है। रक्षा क्षेत्र के ऐसे उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता।

न्यूज प्रिंट पर लगाई 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी

जाब्यू, नई दिल्ली : आने वाले दिनों में पत्रिकाएं और समाचार पत्र महंगे हो सकते हैं। सरकार ने अखबार और पत्रिकाओं की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज पर भारी भरकम 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगा दी है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2019-20 पेश करते हुए न्यूज प्रिंट, अखबार की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले अनकोटेड पेपर और पत्रिकाओं की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले लाइटवेट कोटेड पेपर पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। फिलहाल इन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी शून्य थी। न्यूज प्रिंट के दाम बढ़ने से पहले ही पत्रिकाओं और समाचार पत्र के प्रबंधक परेशान थे। सरकार ने उस समय विज्ञापन के रेट बढ़ाकर राहत भी दी थी। अब न्यूज प्रिंट पर कस्टम ड्यूटी लगने से समाचार पत्र-पत्रिकाओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

जागरण विशेष

स्वच्छ भारत का संकल्प दिला रही अमरनाथ यात्रा

जम्मू : बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान उम्दा स्वच्छता प्रबंधन बाबा बर्फानी के हजारों भक्तों को स्वच्छता का संकल्प भी दिला रहा है। यात्रा के पांचवें दिन यात्रियों की संख्या ने 60 हजार का आंकड़ा पार कर लिया। (पेज-12)

शोपियां में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी ढेर

श्रीनगर : सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हिजुबल मुजाहिदीन के एक आतंकी समीर अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि उसके दो अन्य साथी बच निकले। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। (पेज-12)

क्रिकेट महाकुंभ

भारत vs श्रीलंका — दोपहर 3:00 बजे से — स्थान : लीड्स

ऑस्ट्रेलिया vs द. अफ्रीका — शाम 6:00 बजे से — स्थान : मैनचेस्टर

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट और परिवहन को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली के लिए कोई नई योजना नहीं है। केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी भी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन कई अहम परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन कर उन्हें गति देने की कोशिश जरूर की गई है। दिल्ली-एनसीआर की परिवहन परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खास जोर रहा है। 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने पर ब्याज में साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट की घोषणा से रियल एस्टेट बाजार के भी गति पकड़ने की संभावना है।

दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-अलवर रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए करीब 974 करोड़ का बजट आवंटित कर इस परियोजना को गति दी गई है। चंद्रावल जलशोधन संयंत्र फेज-2 के लिए तीन सौ करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस संयंत्र का शिलान्यास हाल ही में हुआ था, अब इसका निर्माण कार्य जोर पकड़ेगा।

दिल्ली के चार प्रमुख अस्पतालों के लिए 6,161.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन अस्पतालों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के सुचेता कृपलानी व कलावती शरण अस्पताल शामिल हैं।

फेज चार में केंद्र से स्वीकृत तीन प्रमुख कॉरिडोर

कॉरिडोर	लंबाई (किमी)	स्टेशन
तुगलकाबाद-एरोसिटी	20.21	15
जनकपुरी-आरके आश्रम	28.92	25
मजलिस पार्क-मौजपुर	12.54	6

आरएमएल और सफदरजंग में सांध्यकालीन ओपीडी भी अब जल्द शुरू होने की संभावना नजर आ रही है।

मेट्रो फेज चार की परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार : दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए बजट में 414.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे लंबे समय से अधर में लटकी फेज-4 की परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार अनुदान के रूप में यह रकम दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को देगी। फेज-4 में दिल्ली में छह मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे, जिनकी कुल लंबाई 103.93 किलोमीटर होगी। इस बार बजट में देश की मेट्रो परियोजनाओं के लिए 17 हजार 715 करोड़ 93 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से 414.70 करोड़ रुपये दिल्ली मेट्रो फेज-4 की परियोजनाओं के लिए निर्धारित हैं। दिल्ली सरकार भी मौजूदा वित्त वर्ष में दिल्ली मेट्रो के लिए करीब 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था। इस तरह मौजूदा वित्त वर्ष में मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 914 करोड़ 70 लाख की राशि का प्रावधान हो चुका है।

7892.86 करोड़ से मजबूत होगी दिल्ली की सुरक्षा : आम बजट में दिल्ली पुलिस के लिए 7892 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 465.88 करोड़ रुपये अधिक है। उक्त बजट दिल्ली की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने सहित पुलिस को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस करने पर खर्च होगा। बजट को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें प्रशासनिक कार्य, दिल्ली पुलिस की योजनाएं और महिला सुरक्षा निर्भया फंड प्रमुख हैं। बजट में बढ़ोतरी के बावजूद कुछ योजनाओं और निर्भया फंड के बजट में कुछ कमी की गई है। गत वर्ष यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) को लागू कराने के लिए दी गई राशि और निर्भया फंड का पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया था। इस बार बजट में अधिकारियों-कर्मियों का वेतन, कार्यालय खर्च, वाहन, वर्दी, विज्ञापन, प्रचार, स्वास्थ्य, किराया और हथियार की खरीद पर जोर दिया गया है। बजट कई उपकरणों और यातायात सिग्नल की खरीद के साथ ही आवासीय भवनों और कार्यालय के निर्माण पर खर्च होगा।

गुजरात के पूर्व गृहमंत्री पांड्या की हत्या में 12 लोग दोषी करार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या में 12 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। पांड्या की 2003 में अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआइ और गुजरात सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया। गुजरात हाई कोर्ट ने 29 अगस्त, 2011 को सुनाए अपने फैसले में इन सभी दोषियों को हत्या के आरोपों से मुक्त कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन सभी 12 व्यक्तियों को आपराधिक साजिश रचने, हत्या का प्रयास करने और आतंकवाद रोकथाम कानून (पोटा) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

निचली अदालत ने इन सभी व्यक्तियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस बीच, शीर्ष अदालत ने इस हत्याकांड की अदालत की निगरानी में नए सिरे से जांच कराने के लिए गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की याचिका खारिज करते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में मुख्य आरोपित असगर अली के अलावा मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद परवेज, अब्दुल कयूम शेख, परवेज खान पठान, मोहम्मद फारूक उर्फ हाजी फारूक आदि शामिल हैं।

गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार

जागरण ब्यूरो, गांधीनगर

- विदेश मंत्री एस जयशंकर और जुगलजी ठाकोर राज्यसभा के लिए निर्वाचित
- कांग्रेस के अल्पेश ठाकोर और धवलसिंह झाला ने की क्रॉस वोटिंग

गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीट पर भाजपा ने फिर से कब्जा जमा लिया है। भाजपा प्रत्याशी और विदेश मंत्री एस जयशंकर व जुगलजी ठाकोर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वहीं राकांपा व बीटीपी ने भी भाजपा का साथ दिया।

राज्यसभा की दो सीट के लिए शुक्रवार को हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार एस जयशंकर व जुगलजी ठाकोर की जीत पहले से तय थी, लेकिन कांग्रेस ने हार तय होने पर भी गौरव पंड्या व पूर्व मंत्री चंद्रिका बेन चूडास्मा को मैदान में उतारा। भाजपा प्रत्याशियों को 104-104 मत मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों को 70-70 मत मिले। कांग्रेस के बागी विधायक अल्पेश ठाकोर व धवलसिंह झाला ने पार्टी व्हीप का उल्लंघन करके भाजपा के पक्ष में मतदान किया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के छोटू वसावा सहित दो विधायकों ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया। राकांपा विधायक कांधल जडेजा ने भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन सरकार के कृषि मंत्री आर सी फलदू का ही मत रद हो गया।

चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग के भय से कांग्रेस अपने सभी विधायकों को पालनपुर के बालाराम पैलेस ले गई थी। अल्पेश व धवलसिंह के क्रॉस वोटिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की गई लेकिन आयोग ने कांग्रेस की मतगणना रोकने की मांग के साथ अर्जी भी ठुकरा दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद जगदीश ठाकोर ने कहा कि जनता व कांग्रेस को धोखा देने वाले दोनों विधायक गद्दार हैं, इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए सबके साथ धोखा किया है, जनता इनको सबक सिखाएगी। अल्पेश ठाकोर व झाला ने क्रॉस वोटिंग के तुरंत बाद विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा भी दे दिया। झाला ने कांग्रेस के सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया। ठाकोर ने इसी साल अप्रैल में कांग्रेस के सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया था।

सुनहरे भविष्य की तस्वीर | भविष्य मे भी पचास फीसद से ज्यादा की लड़ाई की कोशिश

सशक्त भारत के जरिये मजबूत भाजपा

गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, राष्ट्रीय समाज और आर्थिक विकास की बात बार-बार दोहराई गई है और यही वह मंत्र है जिसके सहारे हाल के आम चुनाव में भाजपा कई राज्यों में पचास फीसद से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही थी।

आशुतोष झा ● नई दिल्ली

पहली नजर में मोदी सरकार का बजट बहुत सादा दिख सकता है। ऐसा बजट जिसमें राजनीति की कोई परवाह नहीं हो, जिसमें इसकी फिक्र न हो कि अगले दो तीन महीनों में भाजपा शासित तीन राज्यों में चुनाव होना है। लेकिन, तथ्य यह भी है कि जितना ध्यान सशक्त भारत और नया भारत का रखा गया है, उतना ही ध्यान मजबूत भाजपा पर भी है। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, राष्ट्रीय समाज और आर्थिक विकास की बात बार-बार दोहराई गई है और यही वह मंत्र है जिसके सहारे हाल के आम चुनाव में भाजपा कई राज्यों में पचास फीसद से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही थी।

चार महीने पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था तो उसमें किसानों और मछुआरों से लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा हुई थी। चुनावी माहौल में इन तीन वर्गों के जरिये भाजपा ने लगभग 20 करोड़ लोगों को साधा था। उस पर क्रियान्वयन शुरू भी हो चुका है। इस साल के बजट में क्रियान्वयन में तेजी लाने का संकेत है। साथ ही छोटे व्यापारियों को उस पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा कर दी गई है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने चुनाव से कुछ पहले की थी। महिलाओं ने इस बार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई है। यही वजह है कि बजट में इसका उल्लेख करते हुए नारी से नारायणी बनाने का खाका पेश किया गया है।

मोदी सरकार-2 ने आम बजट में देश की जनता की अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने की मंशा दिखाई है

रोजगार सरकार के लिए चिंता का सबब रहा है और इस बार एमएसएमई और स्टार्ट अप के जरिये सुनहरे भविष्य की तस्वीर भी दिखाई गई है। मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत अंतरिम बजट में ही दे दी गई थी। इस बार अमीरों पर थोड़ा बोझ बढ़ाकर यह संकेत भी दे दिया गया है कि सरकार पर अमीरों के साथ दरियादिली दिखाने का आरोप चस्पा नहीं हो सकता है। इन सारी कवायदों के जरिये सरकार जनता की अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने की मंशा दिखा रही है। आने वाले वर्षों में इसका लाभ भाजपा को मिलेगा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

आने वाले महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भी मुख्यतया कांग्रेस के साथ ही लड़ाई होनी है। जाहिर है कि इन राज्यों में भी घोषणा बनाम क्रियान्वयन बड़ा मुद्दा बनेगा। आम चुनाव के बाद भाजपा ने अब हर राज्य में पचास फीसद की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। ऐसे में गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं की आकांक्षा पूरी हुई तो भाजपा की जड़ों को और पानी मिलेगा। यही मंत्र है जिसके जरिये भाजपा पंचायत से लेकर सभी राज्यों में सत्ता की राह बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।

धोती-चप्पल पहने बुजुर्ग को शताब्दी में नहीं चढ़ने दिया, रेलवे ने जांच बैठाई पर गलती नहीं मानी

हेमकुमार राज शर्मा, इटावा

एक तरफ सरकार की मंशा है कि चप्पल पहनने वाला भी शान से हवाई यात्रा करे, वहीं रेलवे के कर्मचारी चप्पल पहने बुजुर्ग को ट्रेन में चढ़ने तक नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन पर 72 वर्षीय बाबा रामअवध दास को कंफर्म टिकट होने के बाद भी शताब्दी एक्सप्रेस (कानपुर-नई दिल्ली 12033) में इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया क्योंकि उनके तन पर सिर्फ धोती और पैरों में चप्पल थी। कोच अटेंडेंट और आरपीएफ सिपाही ने उनका उपहास कर अंग्रेजी हुकूमत का तीखा दर्द दोहरा दिया, जो रंग और पहनावे के आधार पर भारतीयों का दमन करता था। बाबा इस अपमान को रेलवे की शिकायत पुस्तिका में दर्ज कराकर बस से गंतव्य को रवाना हुए। वहीं मामला तूल पकड़ने पर रेलवे ने आनन-फानन जांच तो बैठा दी, लेकिन गलती मानने को अब भी तैयार नहीं है। लीपापोती में जुटे अधिकारी अपने स्टाफ के बचाव में सफाई दे रहे हैं कि वेशभूषा-पहनावे के आधार पर भेदभाव नहीं करते। बुजुर्ग गलत कोच में चढ़ रहे थे। उन्हें सही कोच में भेजा गया था।

कोच एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो फिर क्यों रोका : शुक्रवार को उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सफाई देते हुए उन्होंने घटना को नकारने की कोशिश की। बोले, पहनावे के आधार पर भेदभाव की बात गलत है। उनका कोच सी-2 और सीट नंबर 72 थी। वह जेनरेटर यान में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ऑन ड्यूटी आरपीएफ स्टाफ ने उन्हें जेनरेटर यान होने की जानकारी देकर निर्धारित कोच में जाने को कहा था। चूंकि स्टॉपेज महज दो मिनट का है, इसलिए बुजुर्ग व शारीरिक रूप से कमजोर रामअवध दास जब तक सी-2 कोच तक पहुंचते, गाड़ी चल दी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अटेंडेंट व जवान ने उनकी मदद क्यों नहीं की। उन्हें जनरेटर यान के बगल वाले कोच में भी चढ़ाया जा सकता था, क्योंकि ट्रेन के सभी कोच एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। चार जुलाई को शताब्दी एक्सप्रेस के सी-2 कोच में तैनात आरपीएफ जवान, कोच कंडक्टर व कोच अटेंडेंट से उच्च अधिकारी पूछताछ करेंगे।

बाबा रामअवध दास। सौजन्य-सुधी पाठक

बदला-बदला सा नजारा : बुजुर्ग के अपमान का समाचार प्रकाश में आने के बाद शुक्रवार को ट्रेनों की व्यवस्था बदली दिखी। शताब्दी, नॉर्थईस्ट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में टीटीई दरवाजों पर खड़े रहे। यात्रियों को चढ़ने में असुविधा न हो इसका ख्याल रखा गया।

कहा, सिपाही को मिले सद्बुद्धि : बाबा राम अवधदास बस से गाजियाबाद पहुंचने के बाद इंदिरापुरम स्थित मकनपुर में अपने शिष्य सत्यदेव दुबे के घर ठहरे हैं। उन्होंने जागरण को बताया कि वह किसी की शिकायत नहीं करना चाहते बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सिपाही और कोच अटेंडेंट को सदबुद्धि दे, ताकि वे इंसान की उसके कपड़ों से पहचान न करें।

नया भारत

- शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने पर खर्च होंगे 400 करोड़
- स्टडी इन इंडिया के तहत लुभाए जाएंगे विदेशी छात्र
- उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बजट में भारी बढ़ोत्तरी

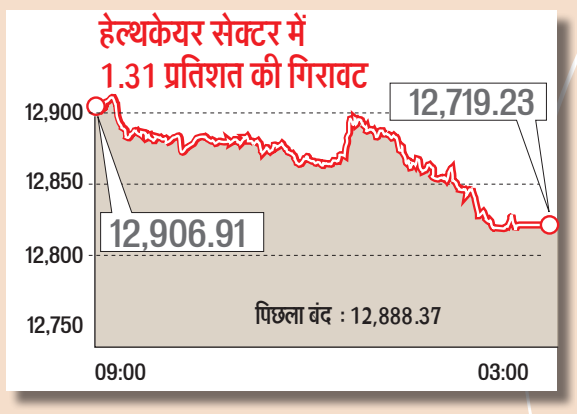

उच्च शिक्षा में फिर हासिल करेंगे गौरव

इस बार बजट में सरकार ने फिर संकेत दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत को अपना गौरव दिलाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। एक बार फिर देश के शिक्षण संस्थानों को इस योग्य बनाया जाएगा कि यहां दुनियाभर के छात्र आएं और शिक्षा ग्रहण करें।

अरविंद पांडेय • नई दिल्ली

उच्च शिक्षा के जरिये दुनिया में भारत के गौरव को फिर से हासिल करने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। यही वजह है भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को नालंदा और तक्षशिला जैसा विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में इस पर अकेले 400 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। जो पिछले साल के मुकाबले करीब तीन गुना ज्यादा होगा। यह सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के इरादे को मजबूत करता है। हालांकि इसके पीछे सरकार का नजरिया ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों की ओर आकर्षित करना भी है। इसके तहत स्टडी इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को और तेज करने जैसी घोषणाएं भी की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए भारत को लेकर अपने इरादे को भी सामने रखा है। इसमें दुनिया में भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भारत के पास इसकी क्षमता है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। नालंदा और तक्षशिला के समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का सिरमौर रहा है। जहां दुनियाभर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। सरकार ने पिछले वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में कई जरूरी कदम भी बढ़ाए हैं। इसका असर भी दिखा है। 2014 के बाद भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों का दुनिया में दबदबा बढ़ रहा है। हाल की विश्वस्तरीय रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में तीन भारतीय संस्थानों ने भी जगह बनाई है।

33000 करोड़ था 2018-19 में उच्च शिक्षा का कुल बजट, जो 2019-20 में बढ़कर 38 हजार करोड़ से ज्यादा हो गया

50000 करोड़ था 2018-19 में स्कूली शिक्षा का कुल बजट, जो 2019-20 में बढ़कर 56 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है

उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की सरकार की पहल का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले सरकार ने इस बार उच्च शिक्षा के बजट में करीब पांच हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उच्च शिक्षा का बजट जहां करीब 33 हजार करोड़ रुपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 को लेकर शुक्रवार को घोषित किए गए बजट में उच्च शिक्षा में 38 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं उच्च शिक्षा को मजबूती देने और विश्वस्तरीय बनाने में जुटी सरकार के इसके पीछे भी कई लक्ष्य हैं। इनमें पहला विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों के पलायन को रोकना है। पिछले कुछ सालों में इनमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका में हर साल करीब दो लाख भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। जो वहां पढाई पर हर साल करीब 44 हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं।

उच्च शिक्षा के नाम पर देश से हर साल करीब 66 हजार करोड़ रुपया विदेशों में चला जाता है। यह राशि उच्च शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि की तुलना में काफी ज्यादा है। इस पूरी कवायद के पीछे सरकार की कोशिश इस पलायन को ही रोकना है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करना भी है। इसे लेकर सरकार ने स्टडी इन इंडिया नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रखा है। जिसका उद्देश्य दुनियाभर के छात्रों को भारतीय उच्च संस्थानों को ओर आकर्षित करना है। अगले तीन सालों में एक लाख से ज्यादा विदेशी छात्रों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में यह संख्या सिर्फ 30 से 40 हजार के बीच ही है। सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षण संस्थानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस प्रतिबद्धता की झलक बजट में देखने को मिली।

नई शिक्षा नीति को मिलेगी मंजूरी इसी साल से शुरू होगा अमल

शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर भी अपनी मंशा साफ की है। जिसमें नीति को मंजूरी देकर इसी साल से लागू करने की बात कही है। इससे साफ है कि सरकार आने वाले दिनों में शिक्षा में बड़े बदलाव के फैसले लेगी। इससे उच्च शिक्षा के साथ स्कूल शिक्षा को मजबूती मिलेगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलावों की सिफारिशें की गई हैं। फिलहाल सरकार अभी इस प्रस्तावित नीति को लेकर लोगों की राय ले रही है। बजट में सरकार के रुख से साफ है कि नई शिक्षा नीति को शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर देगी। फिलहाल अभी 31 जुलाई तक इसे लेकर लोगों की राय ली जा रही है। इसके बाद सुझावों के आधार पर नीति की नए सिरे से समीक्षा होगी। इसे लेकर राज्यों से भी चर्चा प्रस्तावित है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन

61,398 करोड़ रुपये का आवंटन है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए

2.2 फीसद स्वास्थ्य पर आवंटन किया गया है इस बार बजट में

621 रुपये था 2009-10 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खर्च

1112 रुपये तक पहुंच गया था 2015-16 में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खर्च

1500 रुपये 2018 में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खर्च (अनुमानित)

7 लाख रुपये स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पर खर्च करता है अमेरिका (2017)

23.5 फीसद आवंटन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में करता है अमेरिका

1.04 लाख करोड़ डॉलर (करीब 70 लाख करोड़ रुपये) का कुल आवंटन है अमेरिका का

250 करोड़ का आवंटन शहरी स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए

1.5 लाख नए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोलने की योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत

1350 करोड़ रुपये का आवंटन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत

नारी की भागीदारी बढ़ाकर होगी प्रगति

माला दीक्षित • नई दिल्ली

नारी तू नारायणी की अवधारणा से महिला सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाने वाली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे न सिर्फ महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी बल्कि देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर भी बढ़कर दहाई को छूने की उम्मीद जगेगी। नीति आयोग और विश्व बैंक के अध्ययनों में पहले ही कहा जा चुका है कि जीडीपी को दहाई पर पहुंचाने के लिए रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। यह सोच पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में दिखाई देती है। सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कर्ज देने और ब्याज पर छूट की योजनाएं घोषित की हैं।

5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी एसएचजी की सदस्य को

बजट में दिखा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने पर जोर

वित्त मंत्री ने बजट में दिखाई नारी तू नारायणी के ध्येय वाक्य की झलक

प्रतीकात्मक तस्वीर

पिछले कार्यकाल तक मोदी सरकार का जोर बालिकाओं को बचाने उन्हें पढ़ाने लिखाने और उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम करने पर ज्यादा था वैसे तो पिछली बार भी सरकार ने महिलाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन इस बात स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के जरिये आगे बढ़ने का प्रयास कर रही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर बढ़ाने पर सरकार का खासा जोर है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण देब को लिखे पत्र का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया था कि नारी की स्थिति सुधारे बिना संसार में कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। किसी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सरकार मानती है कि महिलाओं की भागीदारी से ही प्रगति की जा सकती है।

सरकार ने बजट में देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और निजी स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर मूल्यांकन एवं कार्ययोजना सुझाने वाली एक समिति बनाने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने पिछली योजनाओं में भी मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और एसएचजी के जरिये विभिन्न स्कीमों में महिला उद्यमियों को सहायता और महिला उद्यम को बढ़ावा दिया था और इस बजट में उसे और आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण पेश किया है। सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि सभी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के हितकारी कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जनधन खाताधारक प्रत्येक एसएचजी सदस्य को 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा होगी। इतना ही नहीं प्रत्येक एसएचजी में एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक 78 महिला सांसद चुन कर संसद पहुंची हैं।

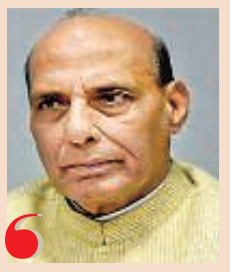
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित बजट में नए भारत की सोच तो है ही, यह लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने पर भी केंद्रित है।
राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

मध्यम वर्ग को कर में पहले ही राहत मिल चुकी है और अब आवास में राहत के साथ नई शिक्षा नीति से बजट में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात कही गई है।
स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री

पीएम आवास योजना होगी और समृद्ध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में 2019-20 के बजट ने एक और नगीना जोड़ दिया है। इसके तहत ऐसे मकान बनाए जाएंगे जिनमें साथ में बिजली और गैस के कनेक्शन भी होंगे। इसके अलावा आयकर छूट बढ़ाकर किफायती मकानों की खरीद को इस बजट में और बढ़ावा दिया गया है।

बजट में किफायती मकानों की खरीद को और प्रोत्साहन दिया गया है। इसके के लिए 45 लाख रुपये मूल्य तक के मकान की खरीद की खातिर लिए गए कर्ज पर अदा ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये तक के अतिरिक्त डिडक्शन का प्रस्ताव किया गया है। सस्ते मकानों के लिए कर्ज के ब्याज पर दो लाख रुपये के डिडक्शन की सुविधा पहले से मिल रही है। इस तरह कुल डिडक्शन छूट 3.5 लाख रुपये की हो गई है। यही नहीं, जीएसटी अधिनियम के साथ आयकर अधिनियम में किफायती मकान की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए महानगरीय क्षेत्रों में 45 लाख रुपये तक के मकान में कारपेट एरिया की सीमा को 30 वर्गमीटर से बढ़ाकर 60 वर्गमीटर तथा गैर-महानगरीय क्षेत्रों में 60 वर्गमीटर से 90 वर्गमीटर तक करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

26 लाख मकान तैयार, जिनमें से 24 लाख का आवंटन भी हुआ

छूट के लिए कारपेट एरिया की सीमा भी बढ़ाई गई

45 लाख रुपये तक के मकान के कर्ज के ब्याज पर डिडक्शन डेढ़ लाख बढ़ा

नए प्रावधान के बाद इस मद में डिडक्शन के जरिये मिलने वाली छूट 3.5 लाख रुपये हो गई

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 4.83 लाख करोड़ के निवेश से 81 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 47 लाख मकानों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। 26 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 24 लाख मकान लाभार्थियों को आवंटित भी कर दिए गए हैं। मकानों के निर्माण में बड़े पैमाने पर नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 13 लाख से ज्यादा मकानों में इन्हीं तकनीकों का प्रयोग किया गया है।' बजट में शहरी विकास मंत्रालय को 48000 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव किया गया है, जो पिछले बजट से 12 प्रतिशत अधिक है।

तैयार हो रहा है गांधीपीडिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश की आजादी से लेकर समग्र विकास की हर सोच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और सकारात्मक जीवन मूल्य समाहित हैं। इन्हीं उच्च जीवन मूल्यों के चलते अहिंसा के इस पुजारी को देश ही नहीं दुनिया ने महात्मा का दर्जा दिया। मोदी सरकार का 2019-20 का बजट भी महात्मा गांधी की स्वच्छता, गरीब, किसान गांव के उत्थान की सोच से प्रभावित नजर आता है। वित्तमंत्री ने एलान किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सकारात्मक मूल्यों के बारे में युवाओं और समाज को व्यापक रूप से जागरूक बनाने के लिए गांधी पीडिया यानी गांधी विश्वकोश तैयार किया जा रहा है। गांधी विश्वकोष तैयार करने का काम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कर रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में गरीबोन्मुख विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कई बार महात्मा गांधी की सोच, उच्च जीवनमूल्य और विचारों का जिक्र किया।

समावेशी विकास और सुशासन को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। यह बजट देश के अभूतपूर्व विकास, महिला सशक्तीकरण और युवाओं के स्वरोजगार में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

विशेषज्ञ टिप्पणी

बजट में प्रगतिशीलता की झलक

अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट अगले पांच-छह साल में देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 में संकेत दिया गया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अगले पांच साल तक आठ प्रतिशत की औसत विकास दर कायम रखनी होंगी। जैसा कि चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के उदाहरण से स्पष्ट है कि आठ-नौ फीसद की विकास दर हासिल करने में निवेश, बचत और निर्यात की अहम भूमिका होती है। निर्यात के लिए मैन्यूफैक्चरिंग महत्वपूर्ण है। बजट स्पष्ट रूप से निवेश, मैन्यूफैक्चरिंग एवं निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निवेश और घरेलू बचत कड़ी चुनौती बनकर सामने आया है और इस दिशा में प्रस्तावित कदम इसे गति देने में सहायक सिद्ध होंगे। बजट में वित्तीय सेक्टर को भी गति देने की कोशिश की गई, जिसकी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी। क्रेडिट हमारे जीडीपी के 70 फीसद के बराबर है और कर्ज बंटवारे पर लगी पाबंदिया दूर करने से विकास के पहियों को ईंधन मिलेगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। इससे सरकार को खर्च के लिए ज्यादा पूंजी मिल सकेगी। सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन पर भी ध्यान दिया है। इससे मोबाइल टावर/पाइपलाइन, पावरग्रिड जैसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खुलेगा। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में शुमार है और पिछले पांच साल में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है। कॉरपोरेट इनकम टैक्स का दायरा 400 करोड़ रुपये तक करना इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे कॉरपोरेट सेक्टर की ओर से पूंजी व्यय बढ़ेगा। जीडीपी की तुलना में निवेश कम होने का एक कारण यह भी था कि आवास क्षेत्र की ओर से पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा था। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में कर छूट में वृद्धि के प्रावधान से सेक्टर को गति मिलेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

भारत इस समय नए स्टार्ट-अप्स के लिए लॉन्चपैड की भूमिका में है। ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें मिली राहत भी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देगी। एंजल टैक्स का मुद्दा भी सुलझ चुका है। खुशी की बात यह भी है कि एआइएफ-2 फंड को एंजल टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है।

बजट में स्पष्ट संदेश है कि बड़े मैन्यूफैक्चरिंग के जरिये भारत को निर्यात का हब बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने संदेश दे दिया है कि गीगा-बैट्री, सेमी कंडक्टर जैसे नए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी साबित हो सकता है। इसी तरह डिजिटल इंडिया हमेशा से सरकार की प्राथमिकता में रही है और इस बजट में भी इसी झलक देखने को मिली।

यह बजट उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं के बीच शानदार संतुलन दिखाता है।

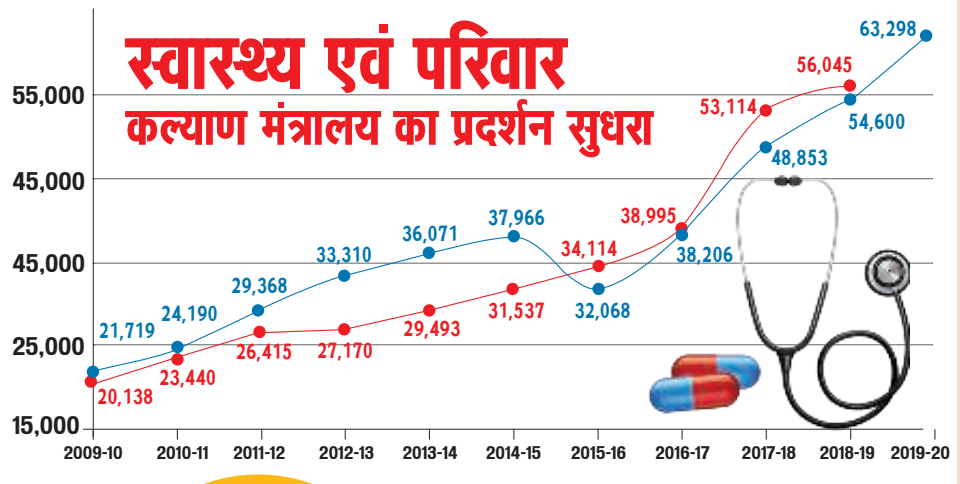

राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति पर ध्यान देकर सभी का भरोसा हासिल करने की कोशिश की गई है।
वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान व भाजपा नेता

बात पते की

स्वास्थ्य, शिक्षा नए भारत की नींव हैं। बजट में इसकी झलक दिखी है। शिक्षा पर सरकार का जोर इससे भी दिखाई देता है कि बजट में केवल आवंटन बढ़ाने ही नहीं, शिक्षा का स्तर सुधारने और विदेश से छात्रों को आकर्षित करने पर भी जोर दिया गया है।

नारी ही नारायणी

- मुद्रा योजना की 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं
- उज्ज्वला योजना में अब तक सात करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिला कनेक्शन
- इस योजना के तहत कुल आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य
- महिला स्वयंसेवा समूहों को ब्याज में मिलने वाली छूट का दायरा सभी जिलों तक बढ़ाया गया
- हर समूह की एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा

समन्वित बाल विकास योजना में आवंटन

23,357 करोड़ रुपये 2018-19 (संशोधित अनुमान)

27,584 करोड़ रुपये 2019-20 (बजट अनुमान)

पांच साल में सौ लाख करोड़ जुटाने के होंगे उपाय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बजट 2019-20 में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास एवं विस्तार पर अगले पांच वर्षों में सौ लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता को देखते हुए इसके लिए बजटीय प्रावधानों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने की मंशा जताई गई है।

बजट में रेलवे, सड़क और विमानन क्षेत्र के विकास के माध्यम से भौतिक कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए कर एवं अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा पेट्रोल व डीजल पर सेस में प्रति लीटर 1 रुपये की बढ़ोतरी का एलान किया गया है। सबसे ज्यादा निवेश की जरूरत रेलवे में है, जहां 2030 तक पचास लाख करोड़ के निवेश की जरूरत होगी, इसलिए रेलवे में नए ट्रैक, रोलिंग स्टॉक और यात्री व माल सेवाओं में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे में अब उपनगरीय एवं मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनाई जाएगी। सड़कों के जरिए भौतिक कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजमार्गों का राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत जहां एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का पुनर्गठन किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ 'भारतमाला' के दूसरे चरण में स्टेट हाईवे के निर्माण को वरीयता दी जाएगी। राजमार्ग ग्रिड की तरह सरकार की देश में गैस, पानी, इंटरनेट तथा क्षेत्रीय हवाई अड्डों के ग्रिड बनाने की भी मंशा है। शहरों को नेशनल एवं स्टेट हाईवे से जोड़ने के अलावा गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 30 हजार ग्रामीण सड़कों का निर्माण बेकार प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स जैसी हरित प्रौद्योगिकी के जरिए किया गया है। सभी ग्रामीण सड़कें बना लेने के बाद अब सरकार ने पीएमजीएसवाई-3 के तहत अगले पांच वर्षों में सवा लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उच्चीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इस पर 80,250 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का होगा कायाकल्प

- रेलवे में उपनगरीय एवं मेट्रो सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
- राजमार्ग, एयरपोर्ट, गैस, पानी के लिए बनेंगे राष्ट्रीय ग्रिड

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किए जाएंगे कई उपाय : प्रदूषण मुक्त परिवहन तंत्र विकसित करने के लिए सरकार ने पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की 'फेम' योजना चला रखी है जिसके दूसरे चरण के तहत तीन वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए विशाल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कर रियायत के अलावा अन्य वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को होंगे नीतिगत बदलाव : 'उड़ान' स्कीम के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के बाद अब सरकार का इरादा विमानों की मरम्मत, रखरखाव एवं ओवरहॉलिंग को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वित्तमंत्री ने भारत को एअरक्रॉफ्ट फाइनेंसिंग व लीजिंग गतिविधियों का केंद्र बनाने की बात भी कही है। वित्तमंत्री ने देश में 17 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने की सरकार की मंशा का भी एलान किया है। ये पर्यटन केंद्र बाकी छोटे पर्यटन स्थलों के लिए मॉडल के तौर पर काम करेंगे।

दीर्घकालिक कर्ज का इंतजाम करने को विशेषज्ञ समिति : इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के महती लक्ष्य को हासिल करने के लिए दीर्घकालिक कर्ज का इंतजाम करने के उपायों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की बात कही है जो विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के काम में जुटी संस्थाओं के साथ सरकार के पिछले अनुभव के आधार पर नई नीतियां बनाने का सुझाव देगी।

> हमारी सरकार के विकास का नजरिया है मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक, यह आगे भी रहेगा। छोटे और मध्यम उद्यमों में ढांचागत (इन्फ्रा), डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में निवेश करने की आवश्यकता है। भारतमाला, सागरमाला जैसी योजनाएं ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रही हैं और हमारे परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं।
>
> –**निर्मला सीतारमण**, केंद्रीय वित्त मंत्री

इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2.61 प्रतिशत की गिरावट

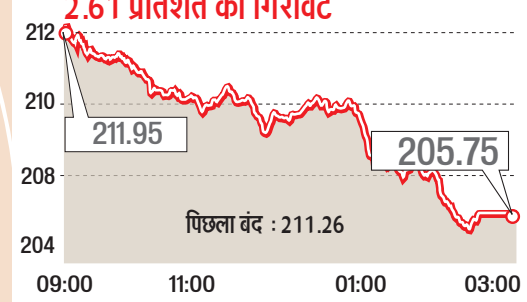

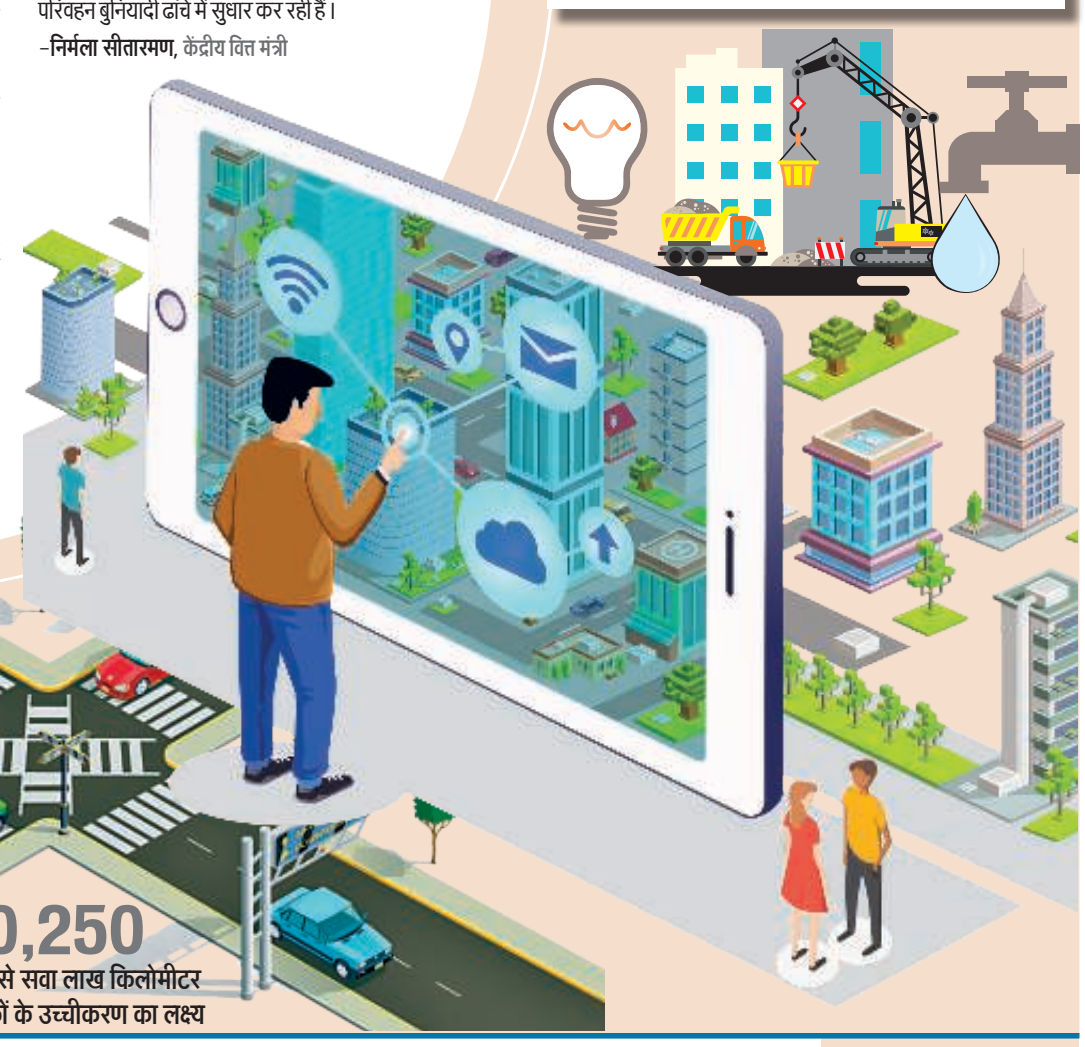

इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ा सेस : गडकरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पेट्रोल व डीजल पर सेस 1 रुपये बढ़ने से इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बढ़ेगा। आयात व प्रदूषण को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर मात्र 5 प्रतिशत रखी है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ेगा। हमारा विश्वास है कि ऑटोमोबाइल के साथ हम इलेक्ट्रिक वेहिकल उत्पादन में भी विश्व में नंबर-1 बनेंगे। इससे नए रोजगार पैदा होंगे। बजट में भारतमाला चरण-2 के तहत राज्यों के सहयोग की बात कही गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर डेढ़ लाख तक लोन ब्याज रहित रहेगा। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

नितिन गडकरी (फाइल)

12 से पांच फीसद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रस्ताव है इलेक्ट्रिक वाहनों पर

1.5 लाख रुपये तक के देय ब्याज पर आय कर छूट देगी सरकार बिजली से चलने वाले वाहन की खरीद पर

1000 दिनों में 130 से 135 किलोमीटर लंबी सड़कें रोज बनाई गई हैं। इसी का नतीजा है कि 97 फीसद लक्ष्य पूरा हो चुका है।

80,250 करोड़ रुपये से सवा लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के उच्चीकरण का लक्ष्य

सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के लिए खोलना होगा खजाने का मुंह

मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए तमाम उपाय किए हैं, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। भारत को बुनियादी ढांचे पर सुदृढ़ करने के लिए खजाने का मुंह खोलना होगा। सशक्त और सबल राष्ट्र की राह में निजी निवेश का अधिक से अधिक और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है।

उपलब्धियां

30 किलोमीटर रोजाना की दर से सड़कों का निर्माण हुआ 2018-19 में। 2014-15 में यह आंकड़ा 12 किलोमीटर का था

ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में 190 देशों की रैंकिंग में 77वां स्थान

118.34 करोड़ लोगों के पास पहुंच चुकी है टेलीफोन (मोबाइल) की सुविधा

3,56,100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता, जो 2018 में 3,44,002 मेगावाट थी

सड़क क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां

ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, कश्मीर में चेनानी-नशरी सुरंग, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर धौला-सदिया पुल का निर्माण

ग्रामीण आवास

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य है।

चुनौतियां

2032 तक भारत को 10,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत एवं लचीला बुनियादी ढांचा जरूरी है।

100 से 110 अरब डॉलर खर्च किए जा रहे सरकार की ओर से हर वर्ष बुनियादी ढांचा के विकास पर।

90 अरब डॉलर का अंतर है निवेश के मामले में, जिसे नये तरीको से पाटा जा सकता है।

7 से आठ फीसद जीडीपी को हर साल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्चने होंगे

रेलवे में सुधार के लिए निजी भागीदारी का सहारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: रेलवे के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सालाना पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता को देखते हुए मौजूदा बजटीय प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र की मदद लेना जरूरी है। अन्यथा चालू परियोजनाओं को पूरा करने में कई दशक लग जाएंगे। बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के उद्धार का यही मंत्र दिया है।

सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि 'रेलवे में 2030 तक पचास लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है, जबकि मौजूदा समय में हम सालाना केवल 1.5-1.6 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय की व्यवस्था कर पा रहे हैं। इस तरह तो सभी मंजूर परियोजनाओं को पूरा करने में कई दशक लग जाएंगे। इसलिए बजट में ट्रैक, रोलिंग स्टॉक के निर्माण और यात्री व माल सेवाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया जा रहा है।'

उन्होंने कहा, 'रेलवे को उपनगरीय रेलों में निवेश बढ़ाने के लिए एसपीवी बनाने तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना भी प्रारंभ की जाएगी।' रेलवे के मामले में यात्री सुविधाओं के विकास पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए 3423 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जो पिछले बजट के मुकाबले तकरीबन 1000 करोड़ रुपये अधिक है। रेल यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर बजट में 'निर्भया' फंड के तहत लगभग 268 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसमें से 250 करोड़ रुपये का उपयोग वीडियो निगरानी से संबंधित एकीकृत आपात प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम-आईईआरएम) को लागू करने में होगा। जबकि बाकी करीब 18 करोड़ की राशि कोंकण रेलवे के काम आएगी।

बजट में रेलवे के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 65,837 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के समेत कुल 1.60 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च के साथ निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से विकास एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में रेलवे के लिए कुल 1.48 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया था। जिसमें बजटीय आवंटन के तौर पर 55,088 करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई थी। वित्तमंत्री ने इस वर्ष रेलवे को आवंटित बजट में नई लाइनों के निर्माण के लिए 7255 करोड़, आमान परिवर्तन के लिए 2200 करोड़, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया है। जबकि रोलिंग स्टॉक के लिए 6115 करोड़ तथा सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम के लिए 1750 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ये राशियां लगभग वही हैं जो फरवरी में वित्तमंत्री के रूप में अंतरिम बजट पेश करते वक्त पीयूष गोयल ने वक्त रखीं थीं।

बजट में 2019-20 के दौरान रेलवे को यात्री एवं माल यातायात से कुल 2,16,675 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है। पीपीपी मॉडल के जरिए देश में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की मंशा जताते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक देश में 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित और चालू हो चुका है। कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के बारे में उनका कहना था कि ये शीघ्र पूरा होने वाला है।

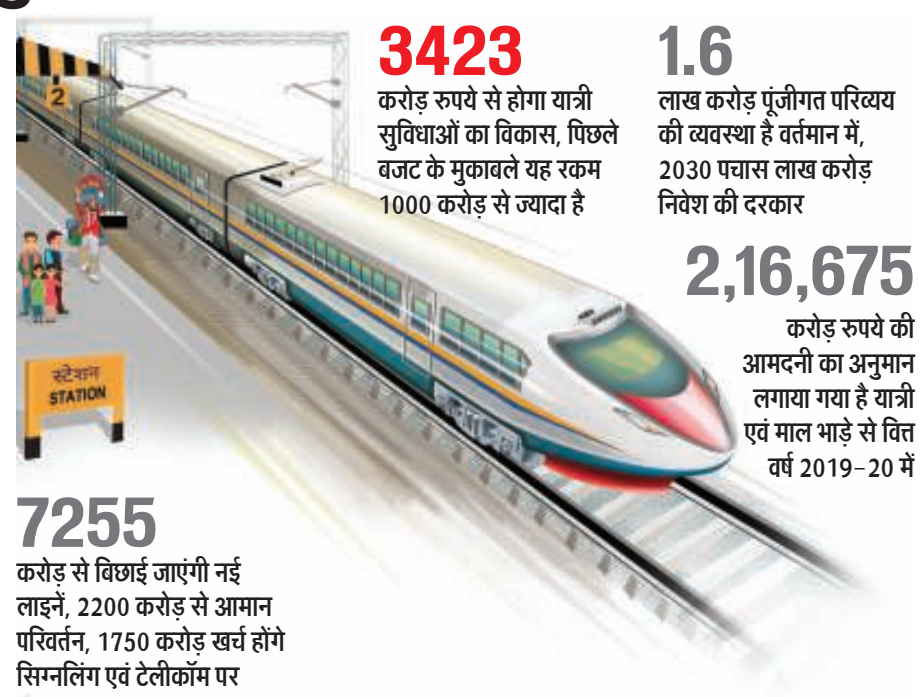

3423 करोड़ रुपये से होगा यात्री सुविधाओं का विकास, पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 1000 करोड़ से ज्यादा है

1.6 लाख करोड़ पूंजीगत परिव्यय की व्यवस्था है वर्तमान में, 2030 पचास लाख करोड़ निवेश की दरकार

2,16,675 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया है यात्री एवं माल भाड़े से वित्त वर्ष 2019-20 में

7255 करोड़ से बिछाई जाएंगी नई लाइनें, 2200 करोड़ से आमान परिवर्तन, 1750 करोड़ खर्च होंगे सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम पर

> इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। अगले पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
>
> –**बालकृष्ण गोयनका**, प्रेसिडेंट, एसोचैम

> मोदी 1.0 ने डीजल पर 443 व पेट्रोल पर 211 फीसद एक्साइज बढ़ाया और 13,00,000 करोड़ की कमाई की। अब मोदी 2.0 ने छिड़का 'जले पर नमक'। पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी के बजट की कमर तोड़ी। क्या ये है 'न्यू इंडिया'?
>
> –**रणदीप सुरजेवाला**, कांग्रेस प्रवक्ता

क्रियान्वयन आयोग के गठन की जरूरत

विशेषज्ञ टिप्पणी

विकास सिंह, वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आम बजट में देश भर में बुनियादी ढांचे के व्यापक निर्माण पर जोर दिया गया है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के आखिरी दौर में देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया था, अब हर गांव के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें खर्च की राशि ज्यादा है, लेकिन अब इस कार्य को हर हाल में पूरा किया जा सकता है इसकी पूरी उम्मीद है। हर घर तक बिजली पहुंचने से ग्रामीण जीवन उन्नत होगा, लिहाजा ग्रामीण विकास के साथ अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों में तेजी आने की पूरी उम्मीद है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वाधिक अहम स्तंभ रेलवे के विकास पर जोर देने की बात बजट में की गई है। हालांकि माल ढुलाई और यात्री परिवहन में सड़क मार्ग की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। इसका बड़ा कारण रेलवे की लचर कार्य-संस्कृति भी है, क्योंकि उद्यमी किराया कम चुकाने से ज्यादा प्राथमिकता सामान को शीघ्र गंतव्य तक पहुंचाने को देते हैं। देखा जाए तो गत चार-पांच वर्षों में रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए निवेश बहुत कम किया गया है। वैसे भारतीय रेलवे द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बड़े हिस्से का निर्माण एक-दो वर्षों में पूरा होने के बाद माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। इससे माल ढुलाई का समय भी कम होगा। देश भर में सड़कों का तेजी से विकास तो हो रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण बड़ी चुनौती है।

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन में नया नजरिया अपनाना होगा। सरकारी रवैया अब तक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का रहा है जिसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग तमाम सरकारी कार्यों पर निगाह रखता है। अब हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना होगा। इंप्लीमेंटेशन कमीशन यानी ऐसे आयोग का गठन करना होगा जो बजट में घोषित योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के कार्यान्वयन पर निगाह रखे। इससे कामकाज का मूल्यांकन भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसका बड़ा फायदा यह भी होगा कि बुनियादी ढांचों के निर्माण में होने वाली देरी से उसकी लागत को बढ़ने से बचाया जा सकता है।

भारतमाला-2 में प्रादेशिक राजमार्गों के विकास को मिलेगा बढ़ावा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अभी तक केंद्र सरकार का सारा ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर रहा है। परंतु अब वो राष्ट्रीय के साथ-साथ प्रादेशिक राजमार्गों अर्थात स्टेट हाईवे के विकास पर भी ध्यान देगी। इसके अलावा आंतरिक व वैदेशिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले ढांचे के विकास के लिए समुद्री व अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि परिवहन लागत में कमी के जरिए भारतीय उत्पादों की लागत को कम किया जा सके।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में सरकार की इस मंशा का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि भौतिक ढांचे के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार रेलवे, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन के अलावा हर तरह की सड़कों का राष्ट्रीय ग्रिड बनाना चाहती है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को भी नए ढंग से तैयार किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित मालगाड़ी गलियारों, भारतमाला तथा सागरमाला परियोजनाओं के माध्यम से भौतिक कनेक्टिविटी के सभी प्रारूपों को जबरदस्त ढंग से आगे बढ़ाया है। जहां औद्योगिक गलियारों से संबंधित क्षेत्रों में अधिक निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा मिलेगा।

वहीं, मालगाड़ियों के लिए विशेष रूप से बनाए जा रहे गलियारों (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स) से रेल तथा भारतमाला के तहत बनाए जा रहे राजमार्गों से देश में सड़क नेटवर्क का विकास होगा और यातायात जाम की समस्या समाप्त होगी। इसके लिए भारतमाला के दूसरे चरण में प्रादेशिक राजमार्गों के विकास को तरजीह दी जाएगी। इससे आम आदमी को फायदा होगा।

सागरमाला के तहत प्रमुख राजमार्ग बंदरगाह से जुड़ जाएंगे। वहीं बंदरगाहों का आधुनिकीकरण होगा तथा उनसे संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सागरमाला का मकसद विदेश जल परिवहन के जरिए विदेश व्यापार के ढांचे में सुधार लाना है। जल परिवहन गरीब आदमी के परिवहन का साधन भी है। जल परिवहन को यातायात का सबसे सस्ता साधन पाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्गों को परिवहन योग्य बनाने के लिए चलाई गई जलमार्ग विकास परियोजना से अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सस्ता और सुगम हो जाएगा जिससे अंततः हमारे यहां उत्पादित सामानों की लागत घटेगी और निर्यात बढ़ेगा।

- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के प्रारूप में होगा संशोधन, सड़कों का ग्रिड बनेगा
- जलमार्गों के विकास से परिवहन लागत घटाकर उत्पादों को बनाया जाएगा प्रतिस्पर्द्धी

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला बजट : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के बजट को भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक और कदम बताया है। कहा कि यह बजट देश के समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के साथ नए और शक्तिशाली भारत का निर्माण करेगा।

इस बजट में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर गरीब को शौचालय, मुफ्त विद्युत कनेक्शन और एलपीजी कनेक्शन के साथ 1.95 करोड़ परिवारों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभिनंदनीय है। पूरे देश के लिए वन पॉवर वन ग्रिड की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य है। देश के तीन करोड़ उद्यमियों के लिए पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे को बढ़ाना और 2024 तक हर घर नल की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करना सराहनीय है। योगी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था शीघ्र ही तीन ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि बजट में तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ देकर नवयुवकों को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त्र किया है। बजट से रोजगार सृजन होगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर परिवार को छत, शौचालय, बिजली, गैस सिलिंडर, स्वास्थ्य बीमा देने के बाद अब हर घर को नल देने की पहल इस बजट की खासियत है। उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने केन्द्र सरकार के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नये भारत के सपने को साकार करने वाला बताया है। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति लाने और उच्च शिक्षा आयोग बनाने की सराहना की। नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बजट में 45 लाख रुपये तक के आवास पर ब्याज में 3.5 लाख रुपये छूट से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

बाजार में जल्द आएगा 20 रुपये का सिक्का

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एक तरफ जहां सिक्का प्रबंधन बैंकों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, वहीं सरकार जल्द ही 20 रुपये का सिक्का जारी करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि नई श्रृंखला के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे। जल्द ही नई श्रृंखला के सिक्के जनता के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे। इन सिक्कों को इस तरह बनाया गया है कि दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से इनकी पहचान कर सकेंगे।

हालांकि जिस तरह सिक्कों को लेकर आमजनता में अरुचि बढ़ती जा रही है और बैंक बड़ी संख्या में सिक्कों को स्वीकार करने में असमर्थता जताते हैं, उसे देखते हुए नए सिक्कों को बाजार में लाने पर सवाल उठ सकता है। छोटे-बड़े व्यापारियों के पास सिक्कों की भारी रेजगारी एकत्र हो गई है। ना तो ग्राहक खुले सिक्के लेना चाहते हैं और ना ही बैंक खुली रेजगारी को जमा करता है। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं जिसमें लाखों रुपये के सिक्के लेने से बैंक मना करते हैं। उनकी परेशानी यह होती है कि उसके पास इतना स्थान नहीं होता है।

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश का हवाला देकर बैंक सिक्कों को जमा करने से मना कर देते हैं। खुद बैंक भी इन सिक्कों को रखने की समस्या से जूझ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जारी हो रहे इन नए सिक्कों को बाजार कितना स्वीकार करता है यह समय तय करेगा।

- इसकी व्यावहारिकता को लेकर उठ रहे सवाल, बैंक भी सिक्के लेने से हैं कतराते

नीतीश ने कहा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य प्रशंसनीय

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट को सराहनीय बताया है। नीतीश ने इस बात पर प्रशंसा व्यक्त की कि पूरे देश के लिए हर घर नल जल योजना की घोषणा की गई है। सबसे पहले बिहार में इस योजना को लागू किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेरे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है कि बिहार में पूर्व से ही सात निश्चय के अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने का निर्णय पर्यावरण के हित में है। स्वच्छ भारत मिशन का विस्तारीकरण करते हुए गांव में ठोस कचरा प्रबंधन लागू करने की व्यवस्था आम लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के बारे में बजट का दृष्टिकोण स्वागत योग्य एवं प्रशंसनीय है।

सुधारों की सौगात

- मीडिया, बीमा व उड्डयन क्षेत्र में बढ़ेगी एफडीआइ
- सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों की राह आसान
- बीमा सेक्टर में सौ फीसद एफडीआइ की मंजूरी

भारी बहुमत तो ज्यादा साहसिक फैसले

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

भारी बहुमत से सत्ता में दोबारा आई मोदी सरकार के लिए आर्थिक सुधार के मोर्चे पर साहसिक फैसला करना अब और आसान हो गया है। वैसे वर्ष 2014 में भी पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के तमाम सेक्टर को विदेशी निवेशकों के लिए काफी उदार बना दिया गया था, अब नई सरकार ने इस बारे में और ज्यादा उदारवादी फैसले करने का जज्बा दिखाया है। आम बजट 2019-20 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा, उड्डयन और मीडिया सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में विदेशी कंपनियों के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पाद लेने की बाध्यता संबंधी मौजूदा नियमों को भी उदार बनाने के संकेत दिए गए हैं। ये फैसले ना सिर्फ देश में नए रोजगार के अवसर बनाने और औद्योगिक विकास को तेज गति देने के लिए आवश्यक है बल्कि जिस 'नये भारत' की परिकल्पना भाजपा सरकार करती है उसे देखते हुए भी यह जरुरी है।

बीमा सेक्टर की मध्यवर्ती कंपनियों के लिए एफडीआइ की सीमा बढ़ा कर 100 फीसद करने का ऐलान करने के साथ ही वित्त मंत्री ने यह संकेत दिए हैं कि समूचे बीमा सेक्टर में यह समान तौर पर 100 फीसद हो सकती है। अभी बीमा सेक्टर में एफडीआइ सीमा 49 फीसद है जिसे मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में लागू किया था। उसके पहले बीमा सेक्टर में विदेशी कंपनियों को 26 फीसद तक ही इक्विटी रखने की इजाजत थी। अभी देश में तकरीबन दो दर्जन विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं और उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि यहां विस्तार के लिए जितनी राशि की जरूरत है उनकी भारतीय सहयोगी कंपनियां उसे नहीं दे पा रही हैं। वर्ष 2001 में बीमा सेक्टर को एफडीआइ को खोलने के बावजूद देश के महज तीन फीसद जनता के पास ही यह बीमा उपलब्ध है।

एफडीआइ सीमा

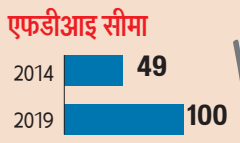

आकड़े फीसद में

24 विदेशी कंपनियां बीमा क्षेत्र में कर रही हैं काम

2001 में बीमा सेक्टर को खोला गया एफडीआइ के लिए

26 फीसद तक ही इक्विटी रखने की इजाजत थी विदेशी बीमा कंपनियों को 2014 से पहले

रिटेल सेक्टर में दिखेगा खासा बदलाव

सरकार की तरफ से सिंगल रिटेल में स्थानीय स्रोत के नियमों को बदलने की बात कही गई है जो खास तौर पर अमेरिकी व चीन की कंपनियों को पंसद आएगी। सनद रहे कि इस बारे में आम चुनाव से पहले ही नियमों को सख्त बनाया गया था और सबसे ज्यादा इस पर नाराजगी अमेरिकी कंपनियों ने और अमेरिकी सरकार ने दिखाया था। अमेरिका की रिटेल कंपनी वालमार्ट स्थानीय स्रोत संबंधी बाध्यता की वजह से वह ज्यादा निवेश नहीं कर पा रही है। वैसे अभी यह देखना है कि सरकार की तरफ से अंतिम तौर पर किस तरह की राहत दी जाती है लेकिन यह तय है कि इससे रिटेल सेक्टर में खासा बदलाव दिखेगा।

घरेलू एयरलाइन कंपनियों को बचाने वाला कदम

इसी तरह से उड्डयन सेक्टर में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 100 फीसद करने का ऐलान है। अब भी इस सेक्टर में 100 फीसद एफडीआइ की अनुमति है लेकिन इसमें से 49 फीसद आटोमेटिक रूट से लाने का प्रावधान है और इससे ज्यादा की यानी शेष 51 फीसद के लिए सरकार की अनुमति जरुरी है। माना जा रहा है कि सरकारी अनुमति की बाध्यता खत्म की जाएगी। साथ ही विदेशी एयरलाइनों को भी निवेश करने की इजाजत सरकार दे सकती है। हाल ही में जेट एयरलाइंस के बंद होने के पीछे एक वजह यह बताया गया था कि उसकी विदेशी साझेदार कंपनी एतिहाद को एफडीआइ बढ़ाने की इजाजत नहीं मिली। बहरहाल, कई घरेलू एयरलाइन कंपनियों को विदेशी निवेश का इंतजार है। यह कदम उन्हें बचाने वाला साबित होगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र की एयर इंडिया के विनिवेश की योजना भी नए नियम से परवान चढ़ सकती है।

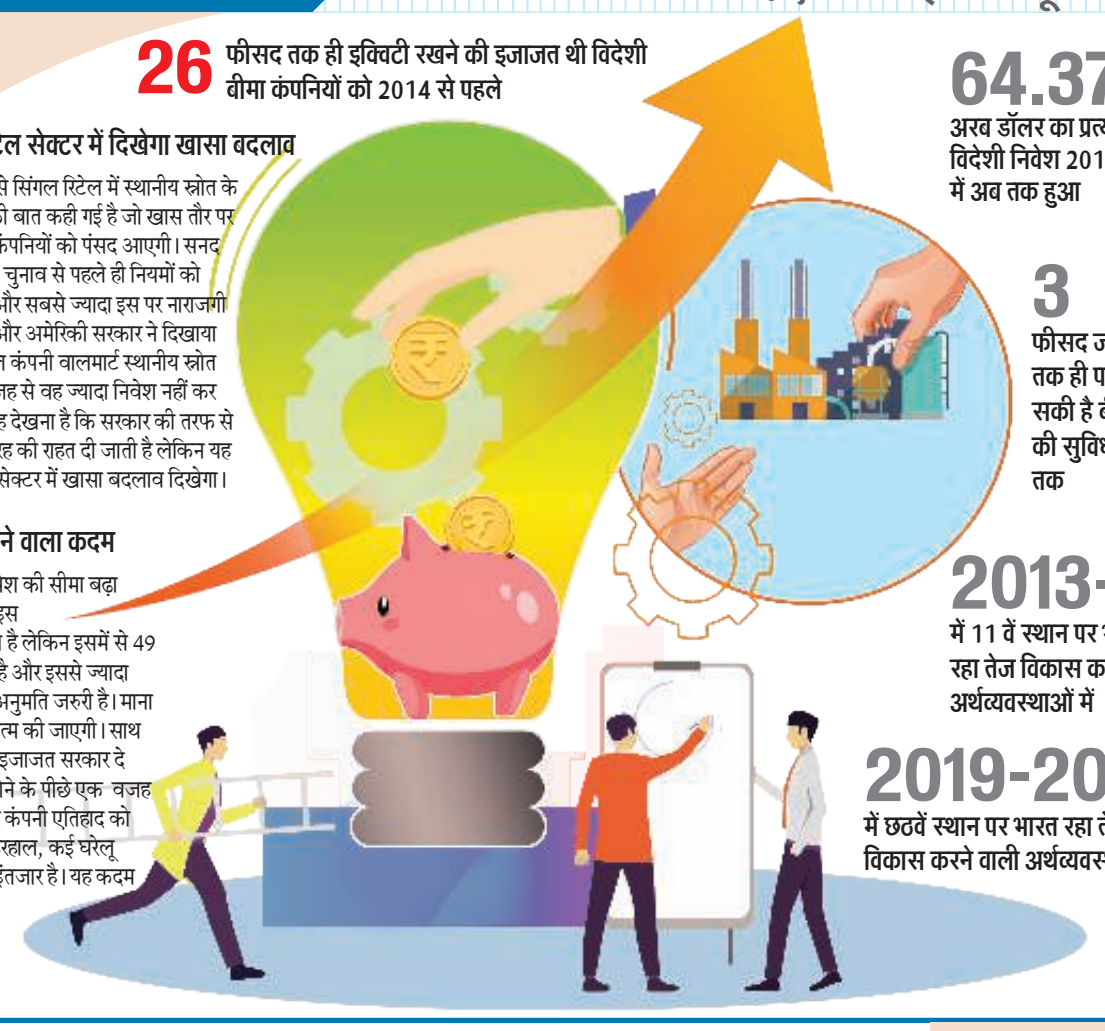

64.375 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2018-19 में अब तक हुआ

3 फीसद जनता तक ही पहुंच सकी है बीमा की सुविधा अब तक

2013-14 में 11 वें स्थान पर भारत रहा तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में

2019-20 में छठवें स्थान पर भारत रहा तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में

रियल एस्टेट में 3.60 प्रतिशत की गिरावट

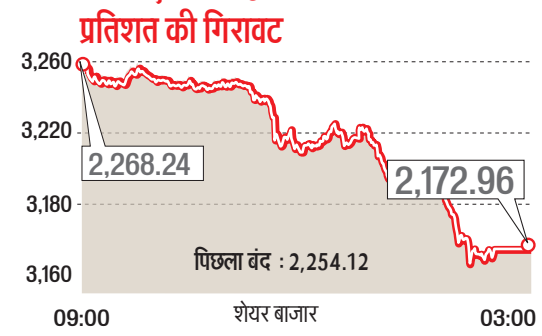

देश में बढ़ी विदेशी निवेश की मात्र

बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अड़चनों के बावजूद भारत में एफडीआइ में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक निवेश वर्ष 2017 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर के करीब था जो वर्ष 2018 में 13 फीसद घट कर 1.3 ट्रिलियन अमेरिका डालर रह गया था। उसके बावजूद भारत में यह 6 फीसद के इजाफा के साथ 64.375 अरब डॉलर रहा। सरकार भारत में निवेश की संभावनाओं और इसके आकर्षण पर एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन भी करवाने जा रही है। इसमें दुनिया के दिग्गज उद्योगपति व कारपोरेट घराने के मुखिया, दुनिया के बड़े बड़े निवेश, पेंशन, बीमा फंड और तकनीक व वेंचर फंड भी शामिल होंगे।

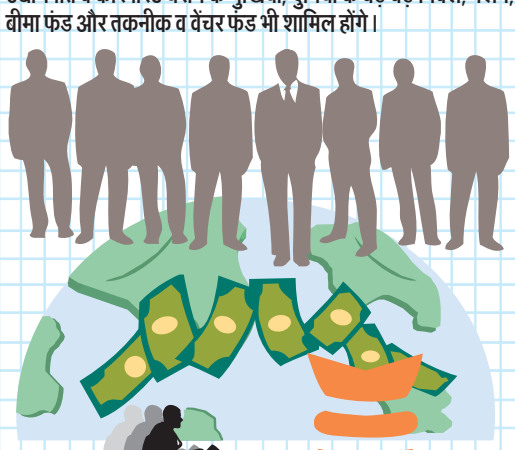

14 जून तक देश में कुल 42220 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार

इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।

इन वाहनों को किफायती बनाने के लिए सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण की ब्याज अदायगी में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट देगी। करदाताओं को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लगभग 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

ऋण क्षेत्र में सुधार और प्रोत्साहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस बजट में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी जाएगी।

किरायेदारी का झगड़ा निपटाएगी सरकार

माला दीक्षित • नई दिल्ली

देश की अदालतों में लंबित 3.5 करोड़ मुकदमों पर अगर निगाह डाली जाए तो दीवानी विवादों में बहुत बड़ा हिस्सा किरायेदारी के मुकदमों का देखने को मिलेगा। किराएदारी के ये मुकदमें तीन - चार पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। पुराना पड़ चुका रेन्ट कंट्रोल एक्ट बदलते युग में किराएदारी के झगड़ों से निपटने में सक्षम नहीं है। हर राज्य का अलग अलग किराया कानून इन झगड़ों में और इजाफा करता नजर आता है। इससे निपटने के लिए वित्तमंत्री ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए नया आदर्श किराया कानून लाने की घोषणा की है ताकि मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और दायित्व स्पष्ट हों और किराएदारी के कानूनी विवादों पर लगाम लगे। इससे किराएदारी कानून की विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने नया आदर्श किराया कानून लाने की घोषणा करते हुए साफ कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किये जाएंगे। यानि कुल मिलाकर किरायेदारी को आसान और विवाद रहित बनाने के प्रयास होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि,

''वर्तमान किराया कानून दकियानूसी और पुराना है क्योंकि इसमें किरायेदार और मकान मालिक के बीच के संबंधों पर वास्तविक और न्यायसंगत विचार नहीं किया जाता। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को भेजा जाएगा। इसका मतलब है केन्द्रीय कानून की तर्ज पर राज्य अपने यहां के कानूनों में सुधार करेंगे या केन्द्रीय कानून ही अपना लेंगे।''

गैर वाजिब, मनमाने और अनुचित तरीके से किराएदार को कभी भी घर या दुकान से निकालने से बचाने और किराएदार व मकान मालिक के हित संरक्षित करने के लिए रेन्ट कंट्रोल एक्ट (किराया नियंत्रण कानून) लाया गया था। हर राज्य का अपना किराया नियंत्रण कानून है। दिल्ली में 1958 का कानून है, तो तमिलनाडु में बिल्डिंग (लीज एंड रेंट कंट्रोल) एक्ट 1960 है। महाराष्ट्र में 1999 का कानून है। इन कानूनों की आढ़ में पीढ़ियों पहले औने पौने किराये पर ली गई दुकान या मकान पर किरायेदार इस तरह काबिज रहता है जैसे कि वह उस संपत्ति का मालिक हो।

मूल कानून पुराने किरायेदार को संरक्षित करता है। अर्थ युग में अचल संपत्ति की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मकान मालिक चाहता है कि या तो किराएदार नये मार्केट रेट से किराया दे या फिर वह परिसर खाली कर दे। हालांकि कानून में मकान मालिक के भी हितों का ध्यान रखा गया है लेकिन कानून का झुकाव ज्यादातर किराएदार के पक्ष में है जिससे झगड़े और मुकदमेबाजी का जन्म होता है।

ई-वाहन और सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रदूषण घटाने और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ने के लिए यह एक सबसे बड़ा कदम है।

– **नितिन गडकरी**, परिवहन और एमएसएमई मंत्री

बजट दिशाहीन है। इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। यह निराश करने वाला है। इसमें विकास तेज करने, रोजगार बढ़ाने या निवेश लाने के लिए कोई ठोस योजना या समाधान नहीं है।

– **अशोक गहलोत**, मुख्यमंत्री, राजस्थान

स्टार्ट-अप्स के लिए टीवी कार्यक्रम, डिजिटल भुगतान परितंत्र का विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन आइटी से जुड़े स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे और उन्हें नवाचार और शोध एवं विकास में जाने के लिए प्रेरित करेंगे।

–**डॉ. ओंकार राय**, महानिदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

पुराने किराया कानून से किराएदार और मकान मालिक दोनों को नुकसान हो रहा था। नए किराया कानून से सांस्थानिक ढांचे का विकास होगा और इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों को लाभ होगा।

– **रमेश नायर**, सीईओ एवं कंट्री हेड, जेएलएल इंडिया

इलेक्ट्रिक कार पर चलेगा इंडिया!

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की बात बार बार करने वाली राजग सरकार ने बजट पेश करते हुए यह साबित किया है कि वह मंसूबा बनाने के साथ ही उसे लागू करने को लेकर भी गंभीर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 फीसद से घटा कर पांच फीसद करने के प्रस्ताव का खुलासा किया तो साथ ही यह भी कहा कि बिजली से चलने वाले वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को देय 1.5 लाख रुपये तक के देय ब्याज पर आय कर छूट भी दिया जाएगा। यह पहला मौका है जब देश में कार खरीदने पर आय कर प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि, इस प्रावधान के जरिए ग्राहक अपनी कार के पूरे जीवन काल में 2.5 लाख रुपये तक का छूट हासिल कर सकेगा।

बजट में कहा गया है कि, देश में ग्राहकों का एक बड़े आधार को देखते हुए हम इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। हम भारत को इन वाहनों का एक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की योजना रखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को कम करने के लिए सरकार की तरफ से पहले ही जीएसटी परिषद से इस पर जीएसटी की दर घटा कर 5 फीसद करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके इसके लिए हम वाहनों की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज को आय कर की छूट देंगे।

इसके अलावा इन वाहनों के कुछ पुर्जों को सीमा शुल्क से भी मुक्त किया जा रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक, सरकार पहले ही इन वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि सिर्फ बेहद उन्नत गुणवत्ता वाली बैट्रियों और वाहनों को ही देश में बढ़ावा मिले।

वित्त मंत्री की तरफ से यह ऐलान तब हुआ है जब नीति आयोग देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नई नीति को अंतिम रूप दे रहा है। नीति आयोग अपनी मंशा पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वर्ष 2022 के बाद से देश में 150 सीसी क्षमता तक के सिर्फ बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों और वर्ष 2023 के बाद सिर्फ तिपहिया वाहनों को निर्माण हो सकेगा। सरकार की मंशा पैसेंजर कारों के लिए यह समय सीमा वर्ष 2030 तय करने की है। हालांकि इस बारे में सरकार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले है। माना जाता है कि कार कंपनियां बिजली कारों को लेकर किस तरह की प्रगति कर रही हैं, इस पर सरकार की पैनी नजर है।

इन कंपनियों की तरफ से भावी कदमों का ऐलान होने के बाद ही सरकार अपने पत्ते खोलेगी। देश की कई दिग्गज कार कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा ने कहा है कि वह भारतीय बाजार में वर्ष 2020 में अपना पहला इलेक्ट्रिक कार उतार देंगी। वैसे सिर्फ कारों के आने से ही बात नहीं बनेगी बल्कि यह देखना होगा कि देश में इन कारों को चार्ज करने की ढांचागत सुविधा भी उपलब्ध हो। इसके लिए नीति आयोग की तरफ से अलग से रणनीति बनाई जा रही है। हाल ही में देश की सरकारी तेल कंपनियों को मौजूदा पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा लगाने की अनुमति भी दी गई है। एनटीपीसी, ओएनजीसी कंपनियां इस बाजार में संभावनाएं तलाश रही हैं।

2.5 लाख रुपये तक का ग्राहक अपनी कार के पूरे जीवन काल में छूट हासिल कर सकेगा

2020 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार उतार देंगी मारुति समेत देश की कई दिग्गज कार कंपनियां

2022 के बाद से देश में 150 सीसी तक के बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों का निर्माण होगा

बात पते की

देश के विकास के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने में संकोच नहीं किया। इससे विदेशों में भारत की साख मजबूत हुई। इसी का नतीजा है कि पांच साल में सरकार ने विनिवेश से 2,09,896 .11 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं।

आटोमोबाइल उद्योग बेहद खुश है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। हालांकि देश का आटोमोबाइल उद्योग जो भारी मंदी से गुजर रहा है उसे इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वित्त मंत्री को मौजूदा आटोमोबाइल कंपनियों की दशा पर भी ध्यान देना चाहिए था। साथ ही पेट्रोल व डीजल पर जिस तरह से टैक्स बढ़ाया गया है उसका आटोमोबाइल उद्योग पर उल्टा ही असर होगा

राजन बढेरा, प्रेसिडेंट, सियाम (सोसायटी फॉर इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स)

नई योजना नहीं, पुरानी की मजबूती पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए किसी नई योजना की घोषणा से परहेज किया है। इसकी जगह पुरानी योजनाओं को लागू करने और उन्हें और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया है। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस साल बजटीय आंवटन में पिछले साल की तुलना में 18.67 फीसद की बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं देश के लगभग 50 करोड़ गरीबों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना आयुष्मान भारत के लिए 155 फीसद अधिक धनराशि आवंटित की गई है।

ध्यान देने की बात है कि पिछले साल के बजट में मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की घोषणा की थी और इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। पिछले साल सितंबर में इस योजना को शुरू भी कर दिया गया। इसके तहत 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा के साथ-साथ पूरे देश में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर भी खोले जाने है। सरकार ने 2022 तक सभी वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है इस बार निर्मला सीतारमण ने इस योजना के बजट में155 फीसद बढ़ोत्तरी करते हुए 4,956 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसी तरह महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए बजट में 94 फीसद बढ़ोत्तरी की गई है।

निर्मला सीतारमण ने इस बार आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़े तेवर के संकेत दिए हैं। इस सिलसिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने वाली भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण (एफएसएसएआइ) के बजट में 154 फीसद की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे एफएसएसएआइ अपने मौजूदा जांच प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के साथ-साथ मोबाइल प्रयोगशालाएं भी तैयार करेगी। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की मदद से एफएसएसएआइ की टीम अब मौके पर जाकर खाने के सामान की गुणवत्ता की जांच कर सकेगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए धन का ख्याल रखा गया है। वैसे तो इस इस योजना के बजटीय आवंटन में केवल 4.58 फीसद की बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन हायर एजुकेशन फाइनैंसिंग एजेंसी के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रावधान किया गया है। इससे इस वित्तीय वर्ष में जरूरी धन की व्यवस्था हो सकेगी। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय के पूरे बजट में पिछली बार की तुलना में 18.67 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 52,800 करोड़ रुपये का था। इस बार इसे बढ़ाकर 62,659 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

स्वस्थ भारत

- आयुष्मान भारत के लिए आवंटन में 155 फीसद की बढ़ोत्तरी
- खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खुलेंगे मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब

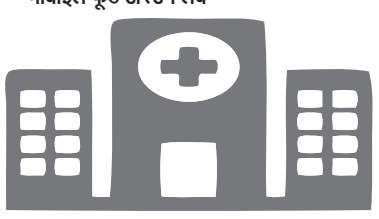

विशेषज्ञ टिप्पणी

मोतीलाल ओसवाल, एमओएफएसएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक

बजट ने सुधारों की जमीन तैयार की

बजट में यह अपेक्षा की गई थी कि विकास समावेशी विकास के सिद्धांत पर आधारित होगा और अपने पिछले कार्यकाल में सरकार द्वारा निर्धारित मध्यम और दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करेगा। बजट इन उम्मीदों को पूरा करता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बजट में कृषि, एमएसएमई, एनबीएफसी, बुनियादी ढांचे और सस्ते आवास को प्राथमिकता दी गई है। व्यवसायिक भरोसे को पुनर्जीवित करने, निजी कैपेक्स रिकवरी, विनिर्माण पर कम ध्यान दिया गया है।

बजट ने वित्तीय बाजार की चिंताओं को कम किया है। बजट में सरकारी बैंकों में डालने के लिए अतिरिक्त 70,000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। सरकार सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की मजबूत एनबीएफसी की पूलित संपत्ति खरीदने के लिए एक बार छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी (10 फीसद तक का पहला नुकसान) प्रदान करेगी। इससे पारंपरिक रूप से मजबूत एनबीएफसी को बैंकों से वित्तपोषण में मदद मिलेगी।

शेयर बाजार को भरोसा था कि सरकार विकास को गति देने के उपाय करेगी, लेकिन इसके दो तरीके थे। पहला तरीका था कि अतिरिक्त टैक्स के जरिए सरकार के पास अधिक धन आए और फिर सरकार उस धन को अर्थव्यवस्था में खर्च करे और दूसरा तरीका था कि उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों के हाथों में अधिक पैसा छोड़ा जाए; सरकार ने पहले तरीके को चुना।

निकट भविष्य में बाजार में थोड़ा कम कारोबार होगा, सरकार ने विकास और उसके निष्पादन का रोडमैप नहीं दिखाया है। यदि निकट भविष्य में बाजार कमजोर हो जाते हैं तो यह इक्विटी बढ़ाने का बेहतर अवसर होगा, क्योंकि बजट दीर्घकालिक स्तर पर आशाजनक लग रहा है।

राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी), पुनर्वित्तपोषक और ऋणदाता होने के साथ ही साथ आवास वित्त क्षेत्र का नियामक भी था जो कुछ हद तक परस्पर विरोधी था। इसलिए, एनएचबी से एचएफसी पर नियामक अधिकार को वापस लेकर उसे आरबीआइ को सौंपने के फैसले से इस क्षेत्र को मजबूत बनाने और वित्तीय उद्योग में इसे दूसरों के बराबर लाने में मदद मिलेगी।

बजट ने सरकार के लिए अगले पांच वर्षों में अपने सुधारों को पूरा करने के लिए जमीन तैयार कर दी है। हालांकि, घोषणाएं अति सूक्ष्म स्तर पर की गई हैं, आने वाले दिनों में इन्हें किस तरह से लागू किया जाएगा और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझने के लिए हमें इन प्रस्तावों को विस्तार से देखना होगा। कुल मिलाकर, हमारा मानना है कि बजट से अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलेगी।

बजट ने वित्तीय बाजार की चिंताओं को कम किया है और सरकार के लिए सुधारों को पूरा करने की जमीन तैयार कर दी है

गांवों की बदलेगी तस्वीर, सुविधाओं से होंगे लैस

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

- ग्रामीण बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी होगी मजबूत
- बिजली, रसोई गैस और शौचालय के साथ नल से जल युक्त आवास सबको मिलेगा

गांव, गरीब और किसानों के जीवन में सुधार लाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार न्यू इंडिया में गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। उसका मानना है कि सशक्त गांवों से ही देश की दशा और दिशा तय होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रावधानों का एलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का हर काम व प्रत्येक योजना के केंद्र में गांव, गरीब और किसान होता है।

बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80 हजार करोड़ से अधिक के प्रावधान से 1.25 लाख किमी लंबी सड़कें अपग्रेड की जाएंगी। गांवों को चौतरफा जोड़ देने का लक्ष्य 2022 तक पूरा होना था, जिसे 2019 के अंत तक ही पूरा कर लिया जाएगा। देश के 97 फीसद गांवों को इस तरह जोड़ दिया गया है। ग्रामीण सड़कें हरित प्रौद्योगिकी से बनाई जा रही हैं। इसमें प्लास्टिक और कोल मिक्स प्रौद्योगिक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हुआ।

गांवों में गरीबी का सबसे बड़ा संकेतक घर का अभाव है। सरकार सबको आवास देने की योजना चला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1.54 करोड़ मकान बना दिए गए हैं, जबकि वर्ष 2022 तक बाकी बचे 1.95 करोड़ और मकान बनाने की तैयारी है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकानों की रफ्तार पिछले सालों के मुकाबले दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि इन मकानों में नल से पेयजल की आपूर्ति, शौचालय, रसोई घर, बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन भी उपलब्ध होंगे। सात करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दे दिए गए हैं। सभी परिवारों और घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। वर्ष 2022 तक देश का कोई घर बिना बिजली और रसोई गैस कनेक्शन के नहीं रहेगा।

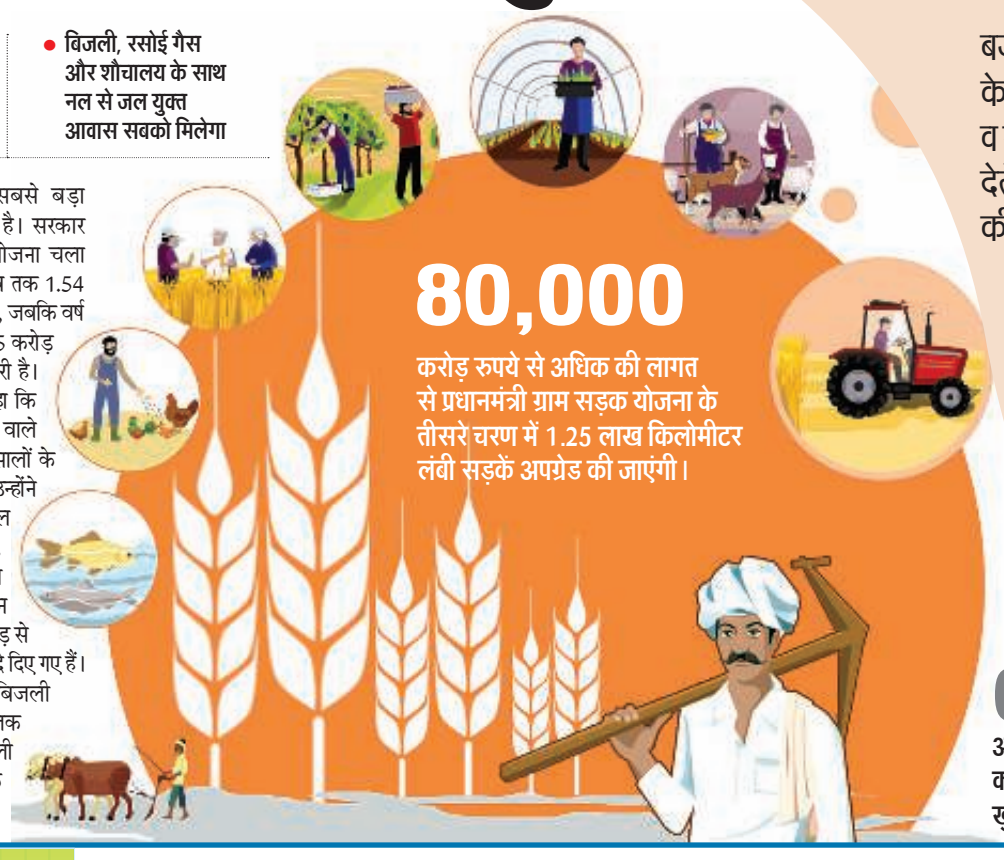

02
अक्टूबर 2019 को देश हो जाएगा खुले में शौचमुक्त

बजट में गांव, गरीब व किसानों के लिए कई प्रावधान हैं। खेती व मछलीपालन को नया आयाम देते हुए इसे व्यावसायिक बनाने की पहल है।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बड़ी पहल

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण स्वच्छता पर बल देते हुए अपने बजट भाषण में कहा कि दो अक्टूबर 2019 को सारा देश खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के प्रयोग पर पूरा जोर दिया जा रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और किसान को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी दोहराया है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजी रोजगार बढ़ाने की दिशा में भी सरकार ने पहल की है। बजट में ग्रामीण उद्योगों को स्थापित करने के प्रावधान किये गये हैं। इसमें किसानों को अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। सौर ऊर्जा से लेकर कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा के लिए करने को प्रोत्साहित किया गया है।

गांवों की सबसे बड़ी कमजोरी कनेक्टिविटी का अभाव है, जिसे बजट में प्राथमिकता दी गई है। सड़क के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डिजीटल साक्षर बनाने की योजना को विस्तार दिया गया है। पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना के चालू वित्त वर्ष के आखिर तक पूरा हो जाने का अनुमान है। जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए भी बजट में गांव के साथ किसानों को जागरूक बनाने पर जोर दिया गया है।

जल संरक्षण और जल के उचित उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। कम पानी वाले सिंचाई के तरीकों को अपना और जल संरक्षण को अपनाने की बात कही गई है। इसके लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई है। बजट में जलवायु परिवर्तन की मुश्किलों का सामना करने के लिए पेड़ लगाने और कचरा प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है।

किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करेगी जीरो बजट फार्मिंग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकार द्वारा जीरो बजट फार्मिंग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किए जाने की घोषणा की। सीतारमण का मानना है कि इस तकनीक से जहां कृषि लागत कम होगी, वहीं किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी।

खेती की बेहतरीन तकनीक

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) खेती की एक तकनीक है। यह नाम इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने दिया है। दरअसल, जेडबीएनएफ में खेती की कई प्रणालियों को शामिल किया गया है। इस कृषि पद्धति को अपनाने से खेती की लागत और जोखिमों को कम करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से बचाने में मदद मिलती है।

40
लाख से ज्यादा किसान अब तक देश भर में खेती की इस तकनीक से जुड़ चुके हैं। कई प्रदेशों की सरकारें भी किसानों को इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

2016
में जीरो बजट फार्मिंग पर काम करने व इससे संबंधित कई किताबें लिखने वाले सुभाष पालेकर को देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया।

उद्देश्य

इस खेती का उद्देश्य किसानों को कर्ज के जाल से बाहर निकालना है। यह छोटे पैमाने की खेती को व्यावसायिक रूप देने का प्रयास भी है। जेडबीएनएफ खेती के खर्च में भारी कटौती करती है और किसानों की कर्ज पर निर्भरता को भी समाप्त करने में मदद करती है।

ऐसी है तकनीक

यह तकनीक किसान सुभाष पालेकर और कर्नाटक किसान संघ के सहयोग से कर्नाटक राज्य में एक आंदोलन के रूप में विकसित हुई। कर्नाटक में इस तकनीक को काफी सफलता मिली। इसके बाद इस तकनीक को देश के कई अन्य राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में किसानों ने अपनाया।

ऐसे होती है बचत

जेडबीएनएफ में खेतों की जुताई और फसल की मढ़ाई आदि का काम बैलों के सहारे किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के डीजल या ईंधन से चलने वाले संसाधनों का प्रयोग नहीं होता है, जिससे काफी बचत होती है।

01
नंबर पर आने वाले राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पांच लाख किसान जीरो बजट फार्मिंग को अपनाए हुए हैं।

बात पते की
गांव, गरीब व किसान को केंद्रबिंदु बताने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में इस क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए हैं। सड़कों को दुरुस्त करने, विपणन सुविधा आदि की घोषणाएं बेहतर हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर कर की वृद्धि बड़ा झटका है।

मछली बढ़ाएगी कृषि क्षेत्र की रफ्तार, शुरू होगी नई योजना

- बजट में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' की घोषणा
- जल कृषि का होगा ढांचागत विकास, वैश्विक बाजार में जमेगी धाक
- देश के करीब डेढ़ करोड़ मछुआरों की बदल सकती है जिंदगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि की विकास दर को और गति देने की जरूरत है, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य क्षेत्र पर भरोसा जताया है। संसद में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने मत्स्य (मछली) पालन और मछुआरों को कृषि क्षेत्र का हिस्सा मान लिया है। इस क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मत्स्य क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, उसके दोहन से देश के लगभग डेढ़ करोड़ मछुआरों की जिंदगी बदल सकती है।

सीतारमण ने बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एलान करते हुए कहा कि इससे मत्स्य विभाग में एक सुदृढ़ ढांचे की स्थापना की जा सकेगी। मूल्य शृंखला (वैल्यू चेन) की खामियों को दूर करते हुए इसे मजबूत करने में मदद मिलेगी। मत्स्य पालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने, इसके आधुनिकीकरण और उत्पादन के साथ उत्पादकता बढ़ाने और मछली पालन प्रबंधन में गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष जोर दिया जा सकेगा।

देश में मीठे जल और समुद्री जल दोनों में मछली उत्पादन की संभावनाओं के दोहन की रणनीति पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछली के प्रसंस्करण पर जोर दिया जाएगा। मछली के संपूर्ण प्रबंधन में यह योजना कारगर साबित होगी। इस जल कृषि के लिए ढांचागत विकास निधि का गठन भी किया गया है, जिसके लिए 7500 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया गया है।

सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फाइल

मालूम हो कि मछली पालन उद्योग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश के लगभग 1.5 करोड़ मछुआरों के रोजगार का यह बड़ा साधन और बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा का साधन है। वर्ष 2018-19 में यहां 1.37 करोड़ टन मछली का उत्पादन हुआ था। इसमें भी 65 फीसद मछली का उत्पादन स्थलीय सेक्टर का था। मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6.5 फीसद योगदान करता है। सकल घरेलू मूल्य वृद्धि में भी इस सेक्टर की वृद्धि दर तेज है।

कृषि उत्पादों के निर्यात में मछली और मछली उत्पादों का निर्यात उल्लेखनीय है। वर्ष 2018-19 में मत्स्य उत्पादों का निर्यात लगभग 48 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया।

यह क्षेत्र विशाल संसाधनों और क्षमताओं वाला है। इसका पूर्वानुमान लगाकर ही सरकार ने फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में अलग मत्स्य विभाग का गठन किया था। 'नीली क्रांति' को साकार करने के लिए मत्स्य पालन एकीकृत विकास और प्रबंधन की वृहद योजना का विलय कर दिया गया है।

दलहन के बाद अब तिलहन की खेती पर रहेगा जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रसोईघर को विलायती खाद्य तेलों से छुटकारा दिलाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश के किसानों से तिलहन खेती पर जोर देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना देने से आयात बिल में कमी आएगी। यह केवल किसानों के पुरुषार्थ से ही संभव है। वित्त मंत्री ने बजट में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद जताई है।

दलहन के बाद अब तिलहन की खेती पर सरकार का जोर है। वित्त मंत्री सीतारमण ने किसानों की सराहना करते हुए अपने बजट भाषण में कहा कि किसानों ने दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। वह भी केवल डेढ़ दो सालों में संभव हो सका है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता जरूर मिलेगी।

देश में तिलहन फसलों की खेती से किसानों के मुंह मोड़ने से लगातार पैदावार घटती जा रही है। नतीजा यह हुआ है कि पिछले तीन दशकों में खाद्य तेलों की कुल घरेलू जरूरत के मुकाबले 60 फीसद आयात से पूरा किया जाता है। इस पर तकरीबन 75 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इसे लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिलहन की कमी पर चिंता जताते हुए इसकी खेती पर जोर देने की बात कही थी। बजट में इस दिशा में कुछ कारगर पहल की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन शुक्रवार को संसद में पेश बजट में इस दिशा में कोई बहुत अहम कदम नहीं उठाया गया है। तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए इसी सप्ताह सरकार ने खरीफ सीजन की तिलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से अच्छी वृद्धि की है।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन से तिलहन खेती की उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन इसके लिए अलग से बजट आवंटन नहीं किया गया है। 10 हजार एफपीओ के गठन कर देने पर कम से कम पांच लाख ऐसे किसानों का संगठन तैयार हो जाएगा, जो तिलहन खेती के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इस तरह के संगठनों को सरकार की ओर से रियायती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। तिलहन फसलों की उपज की खरीद गारंटी मिल जाएगी।

सरकार की तैयारी

- विलायती खाद्य तेलों से छुटकारा पाने की तैयारी, आत्मनिर्भरता पर जोर
- दस हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, सरकार देगी मदद

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के बाद अब तिलहन की बारी। फाइल

बजट में ऐसे भारत को पेश किया गया है, जो सबके लिए हसीन ख्वाब जैसा है। हकीकत में कृषि तथा दूसरे क्षेत्रों को लेकर जो पहले वादे किए गए थे, उनमें कुछ भी नया नहीं है।
- अधीर रंजन चौधरी, नेता कांग्रेस, लोकसभा

वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के संशोधित अनुमानों को ही 2018-19 के पूरे वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के रूप में ले लिया है। चुनाव से पहले खर्च में हुई कमी का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है।
-सीताराम येचुरी, महासचिव, माकपा

गांव, गरीब और किसानों पर ध्यान देने, गांव की समस्याओं का निदान करने और ग्रामीणों की परेशानियों को दूर करने के लिहाज से बजट शुभ है।
-एचके भानवाला, चेयरमैन, नाबार्ड

अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की पहल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कृषि के ढांचागत विकास में सरकार भारी निवेश करने की तैयारी में है। अन्नदाता सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि ऊर्जा भी पैदा करेगा जो देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को पूरा करने वाली इस योजना का जिक्र किया है। इसके लिए किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में किसान सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा कर सकता है। खेतों में फसलों की खेती के साथ किसान अपने ग्रामीण संसाधनों से अन्य ऊर्जा का उत्पादन करने में भी सक्षम होगा। किसान ऊर्जा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद बची ऊर्जा को ग्रिड में भेज सकता है, जिससे उसे अतिरिक्त आमदनी होगी। वैसे भी किसान की गन्ने की फसल से अब सीधे एथनॉल का उत्पादन हो रहा है। चीनी मिलें अब चीनी के साथ एथनॉल का भी उत्पादन करेंगी। सीतारमण ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए बांस और टिंबर जैसे अन्य क्रियाकलापों की उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। फसलों के मूल्यवर्धन की उद्यमशीलता को सरकार मदद देगी।

प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बातें कई मंचों से बोल चुके हैं, जिसमें उन्होंने किसानों को ऊर्जा उद्यमी बनाने की बात कही थी। इस दिशा में सरकार के भीतर कार्य प्रगति पर है, लेकिन इसके लिए जरूरी सरकारी निवेश की जरूरत पड़ेगी, जिसका उल्लेख वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया है।

गौरतलब है कि 2018 के बजट में किसानों के हित में धान जैसी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन लागत के मुकाबले कम से कम 50 फीसद बढ़ाने की घोषणा की गई थी। अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज के लक्ष्य को 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था।

बड़ी बात

- ऊर्जा की अपनी जरूरतें पूरी कर ग्रिड में बेच भी सकता है किसान
- कृषि के ढांचागत विकास में सरकार करेगी भारी निवेश

बजट नीरस और दिशाहीन : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट को नीरस और दिशाहीन करार देते हुए कहा है कि वित्त मंत्री ने किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी है। बजट में पेट्रोल-डीजल पर सेस बढ़ाकर सरकार ने उलटे आम आदमी की जेब लूटने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बजट में सरंचनात्मक आर्थिक सुधार के कदम नहीं उठाए जाने को लेकर भी निराशा जाहिर की है।

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रेस कांफ्रेंस में बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सब लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर वर्ग को राहत देंगी, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर सेस और आयकर कानून में संशोधन प्रस्ताव ला करदाताओं पर कर नियमों के पालन का बोझ बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट भाषण में कुल राजस्व, कुल खर्च, वित्तीय घाटे से लेकर अहम स्कीमों मनरेगा, मिड डे मिल, स्वास्थ्य स्कीम, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक व महिलाओं की योजनाओं के बजट को उजागर नहीं किया गया है। सेना की बढ़ चढ़कर बात करने वाली सरकार ने भाषण में रक्षा बजट का जिक्र नहीं किया।

चिदंबरम ने कहा कि इससे यह भी जाहिर होता है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तरह पीएम मोदी आक्रामक सुधारवादी नहीं बल्कि एक धीमे सुधारवादी हैं। अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डालर पहुंचाने के लक्ष्य की बातें खूब कही गई हैं मगर बजट में ऐसी कोई झलक नहीं कि निजी निवेश को कैसे आकर्षित किया जाएगा। इस दिशा में एकमात्र प्रस्ताव एफपीआइ को 24 फीसद से बढ़ाकर उस क्षेत्र की अधिकतम सीमा तक करने का है। मगर यह ध्यान रखना होगा कि एफपीआइ किसी सूरत में एफडीआइ नहीं है।

चिदंबरम ने कहा कि यह साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार पूरे भारत को एक बड़े राज्य के रूप में देखती है और वह सब कुछ करना चाहती है जो कि राज्यों के अधिकार और कर्त्तव्य हैं। यह रवैया सहकारी-संघवाद नहीं बल्कि गैर बराबरी की साझेदारी है जो केंद्र राज्यों पर थोप रहा है। उन्होंने कहा कि गैस ग्रिड और क्रेडिट गारंटी इनहांसमेंट कारपोरेशन का विचार दिलचस्प है मगर इनके विस्तृत विवरण का खुलासा नहीं किया गया है और इसीलिए इन पर प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं।

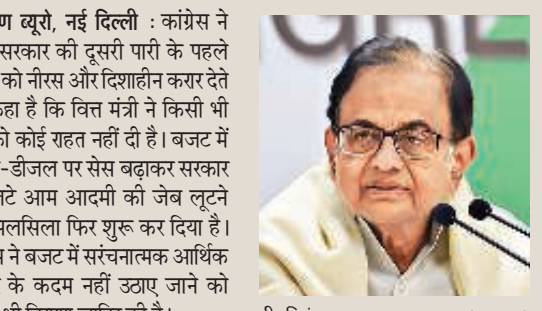
पी. चिदंबरम (फाइल)

- आर्थिक सुधारों का जोखिम न लेकर दिया संदेश मनमोहन जैसे आक्रामक सुधारवादी नहीं पीएम मोदी : चिदंबरम
- पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने और रक्षा समेत अहम बजट आवंटनों को स्पष्ट नहीं करने की आलोचना

बहुरेंगे पुरानी सड़कों के दिन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भूमिका अहम रही है। इसके खास महत्व को देखते हुए ही इस योजना के तीसरे अवतार की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसकी महत्ता का बखान करते हुए इसके तीसरे चरण में सवा लाख किमी लंबी सड़कें बनाने का एलान किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के बदलते परिदृश्य के साथ गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करना बेहद जरूरी हो गया है। इससे जहां किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए ले जाने में सुविधा होती है, वहीं आम ग्रामीणों को भी आवागमन में सहूलियत होती है। इसके लिए सरकार ने बजट में 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पीएमजीएसवाई 3.0 में अब पहले की बनी पुरानी सड़कों के दिन बहुर जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस समय रोजाना 130-135 किमी लंबाई की सड़कें बन रही हैं। सड़क बनाने की इस उच्च गति को प्राप्त करने को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास किया था। पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में अब आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते इन सड़कों के खराब होने की शिकायतें बहुत कम मिल रही हैं। गांवों को जोड़ने वाली इन सड़कों के निर्माण को लेकर समय-समय पर जरूरतों के हिसाब से नियमों को शिथिल भी किया गया है।

- ग्रामीण कनेक्टिविटी पर दिल खोलकर होगा खर्च
- इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ जाएगी प्रत्येक पंचायत

विशेषज्ञ टिप्पणी

टी. हक
(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन)

किसानों के कल्याण के लिए दिखी गंभीरता

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 2018-19 में बजट अनुमान 63836 करोड़ था, जबकि संशोधित अनुमान 86602 करोड़ था। 2019-20 में इसे बढ़ाकर 1,51,518 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह किसानों के जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रामीण विकास के लिए 2018-19 में बजट अनुमान 138097 करोड़ था, जबकि संशोधित बजट अनुमान 135109 करोड़ था। 2019-20 में इसे बढ़ाकर 140762 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2018-19 में संशोधित बजट अनुमान जहां 8251 करोड़ था वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे 9682 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि इस मद में की गई बढ़ोतरी 2022 तक 53 फीसद फसलों को सिंचाई के दायरे में लाने और इस साल के अंत तक सभी बाकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के सरकारी दावे के मुकाबले काफी कम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2018-19 में 13,976 करोड़ (संशोधित अनुमान) रुपये का प्रावधान किया गया था। 2019-20 में इसमें मामूली बढ़ोतरी करते हुए 14,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि इस साल देश के बड़े भूभाग में कम बारिश और सूखे को ध्यान में रखें तो यह आवंटन काफी कम है। खास बात यह है कि फसल बीमा योजना के दायरे में 28 फीसद क्षेत्र और 27 फीसद किसान आते हैं। पीएम किसान योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बजटीय आवंटन से यह नहीं पता चलता है कि इसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा। मेरे विचार से बढ़ी हुई राशि को छोटे और सीमांत किसानों को आवंटित किया जा सकता है। बढ़ाई गई राशि का लाभ बटाई किसानों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि लिखित पट्टे के अभाव में उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

बजट से इस बात का भी पता नहीं चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण, फसल कटाई के बाद उसे बिक्री केंद्र तक पहुंचाने के साधन और कृषि अनुसंधान की निवेश आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाएगा। ब्याज अदा करने में मदद के रूप में भी आवंटन को बढ़ाया गया है। 2018-19 में यह 14987 करोड़ रुपये था, जबकि 2019-20 में इसे बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि विभिन्न कृषि सब्सिडी को मिलाने के संबंध में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। बजट के सकारात्मक पहलू को देखें तो पीएम किसान योजना किसानों को बहुत राहत प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन की प्रगति में बहुत काम आएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे में व्यापक रूप से निवेश करेगी। किसानों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,000 नए एफपीओ को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार किसानों को ई-नैम से लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।

पीएम किसान योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन स्वागत योग्य कदम

हर हाथ को काम

- नई शिक्षा नीति से रोजगार के अवसर पैदा होंगे
- स्टार्ट-अप योजना को मजबूत करने के लिए प्रावधान
- एमएसएमई के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म बनेगा

एमएसएमई से ही निकलेगा बेरोजगारी का समाधान

छोटे व मझोले उद्योगों के लिए बनेगा भुगतान का विशेष प्लेटफार्म, सरकारी भुगतान में होने वाली देरी होगी खत्म

'अभी देश की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी 29 फीसद है, लेकिन हमारे विभाग ने इसे 50 फीसद करने का लक्ष्य रखा है।'
नितिन गडकरी, एमएसएमई मंत्री

29 फीसद से बढ़कर 50 फीसद होगी जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी

05 वर्षों में पांच करोड़ नए रोजगार के अवसर देंगे छोटे उद्यम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एक दिन पहले वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में अगले 20 वर्षों तक 97 लाख रोजगार के अवसर हर वर्ष बनाने होंगे। दुनिया में किसी भी देश के लिए रोजगार का इतना बड़ा अवसर बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। आम बजट 2019-2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार बढ़ाने के जो प्रावधान किए हैं उसे देख कर लगता है कि सरकार अपना दांव सीमांत, छोटे और मझोले उद्योगों पर ज्यादा लगा रही है। इन उद्योगों के लिए ज्यादा कर्ज उपलब्ध करा और इन्हें बेहतर माहौल देकर सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने लायक बनाने की मंशा रखती है। बजट पेश करने के तुरंत बाद इस सेक्टर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भी कि, एमएसएमई क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50 फीसद योगदान देने के लायक बनने जा रहा है। यही नहीं इससे पांच वर्षों में 15 करोड़ रोजगार के अवसर भी बनेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि सरकार के पास बढ़ती बेरोजगारी का जवाब है, लेकिन देखना होगा कि जमीन पर ये घोषणाएं कितना असर दिखा पाती हैं।

एमएसएमई के लिए जो सबसे अहम एलान आम बजट में किया गया है वह है इनके भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का निर्माण करना। इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल छोटी और मझोली कंपनियां करेंगी और इससे उनके लिए सरकारी भुगतान हासिल करना आसान हो जाएगा। सीतारमण के मुताबिक, एमएसएमई से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं को सरकार से मिलने वाला भुगतान उनकी समूचे ढांचे में काफी अहम होता है। इसमें होने वाली देरी से उनका ढांचा चरमरा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नेटवर्क के बनने से इस देरी को दूर किया जा सकेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी का भी एलान किया है। इसका फायदा यह होगा कि इन एमएसएमई को अब बैंकों से ज्यादा कर्ज मिल सकेगा। माना जा रहा है कि जिस तरह से एक मिनट के भीतर छोटे व मझोले उद्यमों को कर्ज देने की नीति ने सफलता हासिल की है उसी तर्ज पर ब्याज सब्सिडी देने की स्कीम का भी फायदा होगा।

इन बजटीय प्रावधानों पर एमएसएमई मंत्री गडकरी ने विस्तार से बताया कि, ''अभी देश की जीडीपी में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 29 फीसद है, लेकिन हमारे विभाग ने इसे 50 फीसद करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं इस सेक्टर से अभी तक 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है लेकिन हम अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ नए रोजगार के अवसर और जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से एमएसएमई सेक्टर में वर्ष 2024 तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।'' वित्त मंत्री और एमएसएमई मंत्री के इस दावे के बावजूद देश के इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र की मौजूदा दिक्कतों का समाधान होना संभव नहीं दिखता है। खास तौर पर तब जब एक दिन पहले ही पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इस सेक्टर को लेकर कई तरह की उम्मीदें दिखाई गई थी। वर्ष 2016 में लागू नोटबंदी से सबसे ज्यादा झटका छोटे व मझोले उद्यमियों को ही लगा था। यह बात इस तथ्य से समझा जा सकता है कि पहली बार वर्ष 2017 में बैंकों की तरफ से एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज की रफ्तार नकारात्मक हो गई थी। कुल बैंकिंग कर्ज में एसएमएमई की हिस्सेदारी 17 फीसद थी जो घट कर 14 फीसद रह गई थी।

हाल ही में सरकार ने रोजगार पर जो डाटा जारी किया है, उसमें बेरोजगारी की दर के 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर माना गया है और इसके लिए विशेषज्ञ एमएसएमई की खस्ताहाल स्थिति को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। पिछले एक वर्ष में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की जो दुर्दशा हुई है उसकी वजह से एमएसएमई को कर्ज मिलना और मुहाल हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट में एनबीएफसी में सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसका भी असर लघु व मझोले उद्योगों को देखने को मिलेगा। देश में बेरोजगारी के राक्षस पर लगाम लगाने के लिए इस सेक्टर को फलना फूलना बेहद जरूरी है।

350 करोड़ की ब्याज सब्सिडी का भी एलान किया है वित्त मंत्री ने जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई के लिए। इससे एमएसएमई को अब बैंकों से ज्यादा कर्ज मिल सकेगा।

2016 में नोटबंदी से सबसे ज्यादा झटका छोटे व मझोले उद्यमियों को लगा था। 2017 में बैंकों की तरफ से एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज की रफ्तार नकारात्मक हो गई थी

रोजगार की दिशा में चलने हैं कुछ और कदम

स्किल इंडिया नाम है उस महत्वाकांक्षी योजना का जिसे पिछली मोदी सरकार ने 15 जुलाई, 2015 को शुरू किया। योजना का लक्ष्य देश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बना कर उनके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसके तहत ही 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। हालांकि, इन क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण सफलता अभी हासिल नहीं हो सकी है। युवा शक्ति को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में कुछ कदम और चलना अभी बाकी है।

40 सेक्टरों में कोर्सेज का संचालन किया जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। इसका उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास कर रोजगार अवसर बढ़ाना है।

2022 तक 40 करोड़ लोगों को रोजगार पाने लायक स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है समूचे स्किल इंडिया मिशन के तहत।

57% का ही प्लेसमेंट हो पाया इन सेंटरों से कौशल हासिल करने वाले युवाओं का

04 साल (2016-20) में एक करोड़ युवाओं को दक्ष बनाने का लक्ष्य है, अभी तक 50 लाख युवाओं को ही कुशल बनाया जा सका है।

2500 से भी ज्यादा सेंटर खोले गए इस योजना के तहत पूरे देश में। कई लोगों ने अपनी नौकरी छोड़कर सेंटर खोलने में पैसा लगाया, लेकिन कई सेंटर बंद हो गए हैं। इसकी वजह स्किल इंडिया की पॉलिसी में बार-बार बदलाव रहा।

देश के डिग्री धारी युवाओं का बड़ा हिस्सा वास्तव में नौकरी लायक ही नहीं होता। एसोचैम के एक अध्ययन मुताबिक 94 फीसद एमबीए ग्रेजुएट नौकरी के लायक नहीं हैं। इसलिए स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और मजबूती देने की जरूरत है। इसके लिए इस योजना की सभी तरह की खामियों को दूर करना होगा।

बुजुर्ग होते धनी देशों में भारतीय युवाओं को अवसर

ऐसे देश जहां युवाओं की संख्या कम है, वहां भारतीयों को मिलेगा मौका

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बिगड़ रहा है जनसंख्या का अनुपात

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नए अवसर के लिए प्रावधान

दूसरे देशों की भाषा समेत जरूरी कौशल से किया जाएगा लैस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बूढ़ी होती दुनिया के लिए भारत एक नई उम्मीद साबित हो सकता है। खासकर विकसित देशों में जहां युवाओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और उसी अनुपात में बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, कामकाजी युवाओं की कमी को भारतीय युवा दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले इन युवाओं को तैयार करने जरूरत है। बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को इस नए अवसर के तैयार करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को उद्योग की जरूरतों के मुताबिक कौशल का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है।

सीतारमण ने पूरी दुनिया में जनसंख्या में हो रहे बदलावों का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले सालों में दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मानव श्रम की भारी कमी से जूझ रहे होंगे। ऐसे में भारतीय युवाओं के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण यह संभव नहीं है। इसके लिए युवाओं को संबंधित देशों की भाषा समेत जरूरी कौशल से लैस करना होगा। वित्तमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अगले चरण में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि जापान पहले ही तीन लाख भारतीय युवाओं को अपने यहां प्रशिक्षित करने और रोजगार देने के लिए भारत सरकार से समझौता कर चुका है।

सीतारमण ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में युवाओं को भी ऐसे ही अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में युवाओं को अब कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, एआइ) का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कंप्यूटर व इंटरनेट से संबंधित सभी उपकरणों को चलाने व ठीक करने, बड़े-बड़े डाटा के विश्लेषण का प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स में प्रशिक्षित युवाओं की भी भारी मांग होगी। सीतारमण ने कहा कि इन क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उन्हें देश और विदेश में रोजगार मिल सके। इनमें प्रशिक्षित युवाओं को देशी-विदेशी कंपनियां हाथों-हाथ लेती हैं। जाहिर है विदेशी भाषा का प्रशिक्षण मिलने के बाद भारतीय युवाओं के लिए विदेशों में नौकरियों के नए आयाम खुल जाएंगे।

यह आजादी के बाद पहली बार है कि किसी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। बजट देश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करता है।
-योगी आदित्यनाथ,
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

व्यापक आर्थिक स्तर पर यह एक दूरदर्शी बजट है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर बनाने की दिशा में ले जाकर प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करेगा।
-देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

स्टार्ट-अप को नहीं सताएगा एंजेल टैक्स का डर

निवेशकों के प्रीमियम शेयर और धन के स्रोत की नहीं होगी जांच

स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा नया चैनल

चैनल की रूपरेखा भी स्टार्ट-अप ही बनाएंगे और वही उसे चलाएंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बजट में देश के युवाओं को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बनाने लिए शुरू की गई स्टार्ट-अप योजना को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजेट टैक्स की मार झेल रहे स्टार्ट-अप को इससे मुक्त करने का भरोसा दिया है। इसके तहत अब उनके प्रीमियम पर बेचे जाने वाले शेयरों के मूल्यांकन के लिए किसी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। यही नहीं, स्टार्ट-अप के विकास, उनकी समस्याओं और जरूरतों पर बहस के लिए एक विशेष चैनल खोला जाएगा, जिसे स्टार्ट-अप ही चलाएंगे।

दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमता पर आधारित खुलने वाली नई कंपनियां चौथी औद्योगिक क्रांति का आधार मानी जाती हैं। चंद साल पहले स्टार्ट-अप के रूप में शुरू हुई कई ऐसी कंपनियां आज दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील हो चुकी हैं। जाहिर है युवाओं को रोजगार देने में ऐसी कंपनियां काफी आगे रहती हैं। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे हैं। स्टार्ट-अप की अहमियत को देखते हुए मोदी सरकार ने देश में स्टार्ट-अप योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत हजारों कंपनियां खोली भी गईं, लेकिन एंजेल टैक्स समेत कई मुद्दे उसकी राह में बड़ी बाधा बनकर सामने आए।

स्टार्ट-अप कंपनियां लगातार इन मुद्दों को सुलझाने की मांग करती रही थीं। बजट में स्टार्ट-अप की राह की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। सीतारमण ने माना कि युवाओं को नई कंपनियां खोलने के लिए शुरू की गई स्टार्ट-अप योजना अब अपनी जड़े जमाने लगी है। इसे और प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

वित्तमंत्री ने इसके लिए कई घोषणाएं कीं। इनमें सबसे अहम है एंजेल टैक्स के भय से मुक्ति देना। सीतारमण ने एंजेल टैक्स के विवाद के स्थायी समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब स्टार्ट-अप में निवेशकों के शेयरों के मूल्यांकन की जांच नहीं की जाएगी। इन निवेशकों की पहचान और उनके धन के स्रोत का सत्यापन भी ई-वेरीफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी भी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इससे स्टार्ट-अप द्वारा जुटाया गया धन आयकर विभाग जांच से बाहर हो जाएगा।

इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि सीबीडीटी ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे स्टार्ट-अप के खिलाफ पुरानी जांच में जांच अधिकारी अपने आप आगे की कार्रवाई नहीं कर सकेगा, बल्कि इसके लिए उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अपने आवासीय संपत्ति को बेचकर स्टार्ट-अप में निवेश करने वालों को करों में मिलने वाली छूट को अगले दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

सबसे बड़ी बात यह है कि सीतारमण ने पहली बार स्टार्ट-अप के लिए नया चैनल शुरू करने का एलान किया है। इससे स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही उनके विकास को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार-विमर्श करने और उद्यमियों के बीच तालमेल बिठाने का नया मंच तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इस चैनल की रूपरेखा भी स्टार्ट-अप ही बनाएंगे और वही उसे चलाएंगे भी। इसके साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के युवाओं के लिए शुरू किए स्टैंड-अप योजना को 2024-25 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

यह देखकर अच्छा लगा कि एक महिला सांसद बजट पेश कर रही थीं। नारी नारायणी है। अगर देश के लोग यह समझ लें तो महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है वो रुक जाएगी।
-हेमा मालिनी
सांसद, मथुरा

जब विश्व में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हैं, तो उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचाने के बजाय सरकार एक रुपये का उत्पाद शुल्क व उपकार लगाने जा रही है। यह निंदनीय है।
-ज्योतिरादित्य सिंधिया
कांग्रेस महासचिव

विशेषज्ञ टिप्पणी

नए निवेश से पैदा होंगे रोजगार

मनीषा प्रियम
लेखिका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से डॉक्टरेट हैं

यहआम बजट सिर्फ आय-व्यय का ब्यौरा भर नहीं है। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और विजन का दस्तावेज है। मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में यानी 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर पांच लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जाहिर है अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान के मुकाबले दोगुना करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में भारी निवेश की दरकार होगी तथा बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास पर जोर देना होगा। साथ ही इस लक्ष्य को एक तय समय सीमा में हासिल करने के लिए कुशल मानव संसाधन की भी आवश्यकता होगी।

गत दिनों देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को दर्शाने वाले आंकड़े आए थे। जिसमें कहा गया था कि देश में बेरोजगारी की दर बीते चार दशकों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी देश में जितने युवा रोजगार के मैदान में आ रहे हैं उसके मुकाबले रोजगार के अवसर नहीं बन पा रहे हैं। देश में ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए, क्योंकि लंबे समय तक ढांचागत विकास, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। इन्हीं बाधाओं को दूर करने और नए अवसरों को पैदा करने के लिए आम बजट में कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि सीधे-सीधे रोजगार पर बजट में कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ढांचागत विकास पर जोर देने, स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया और छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने, पारंपरिक उत्पादों और कारीगरों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने, 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाने और नई शिक्षा नीति को लागू करने से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

मोदी सरकार ने सिर्फ ढांचागत विकास पर ही अगले पांच साल में सौ लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे सड़क, बिजली, पानी, घर आदि आम लोगों के जीवन और उद्योग क्षेत्र से जुड़े आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलेगा। वहीं देश में नए उद्यमी पैदा हों और वे दूसरे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकें इसके लिए स्टार्ट अप इंडिया योजना को लोकप्रिय बनाने की भी योजना है। इसके लिए एक नया चैनल शुरू किया जाएगा। इसके जरिये सरकार युवाओं को नए स्टार्ट अप का आगाज करने के लिए जागरूक करेगी। यह कदम रोजगार सृजन के लिए अहम साबित हो सकता है।

इसके साथ ही स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया पर सरकार का ध्यान बढ़ा है। वहीं ग्रामीण जगत में कृषि आधारित रोजगार के अवसर बनाने के लिए बजट में स्फूर्ति योजना के तहत सुविधा केंद्र स्थापित करने और कृषि आधारित 75 हजार हुनरमंद उद्यमी तैयार करने की बात कही गई है। इसके जरिये कृषि उत्पादों को परिष्कृत कर बाजार से जोड़ा जाएगा।

देश की अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान के मुकाबले दोगुना करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में भारी निवेश की दरकार होगी...

शोध के लिए खुलेगा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शोध को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने अब इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास तेज करने पर जोर दिया है। देश में इसके लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाने की घोषणा की है। जहां राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र और विषयों को पहचान कर शोध को गति दी जाएगी। मौजूदा समय में शोध से जुड़ी गतिविधियों का संचालन अलग-अलग मंत्रालयों के जरिये हो रहा है। इसके चलते दोहराव और गैर-जरूरी शोध जैसे विषय भी सामने रहे है। सरकार का मानना है कि इस कदम से इससे बचा जा सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए देश की प्रगति के लिए शोध को जरूरी बताया है। हालांकि उनका इस बात पर भी जोर दिया है, कि ऐसे अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो देश के विकास में मदद कर सके और जरूरी हो। सरकार ने इसके साथ ही अलग-अलग मंत्रालयों में शोध पर खर्च होने वाली राशि को गठित होने वाले अनुसंधान प्रतिष्ठान में शामिल करने की भी बात कही है। खास बात यह है कि शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाने का यह सुझाव प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में भी दिया गया है। हालांकि इस पर अभी राय ली जा रही है, लेकिन सरकार ने इससे पहले ही बजट में इसे बनाने का ऐलान कर दिया है। नीति में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाने की यह सिफारिश इसलिए की गई थी, क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए शोध कार्यों को बढ़ावा देना जरूरी है। यही वजह है कि यूजीसी ने हाल ही में शोध को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड नाम की एक नई योजना भी शुरू की है। जिसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध से जुड़े प्रस्ताव मांगे गए है। शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार की रुचि का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शोध और नवाचार के बजट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 में जहां इसके लिए करीब तीन सौ करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, वहीं 2019-20 के बजट में इसे छह सौ करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है।

बात पते की

मोदी सरकार ने सिर्फ ढांचागत विकास पर ही अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे सड़क, बिजली, पानी, घर आदि आम लोगों के जीवन और उद्योग क्षेत्र से जुड़े आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा।

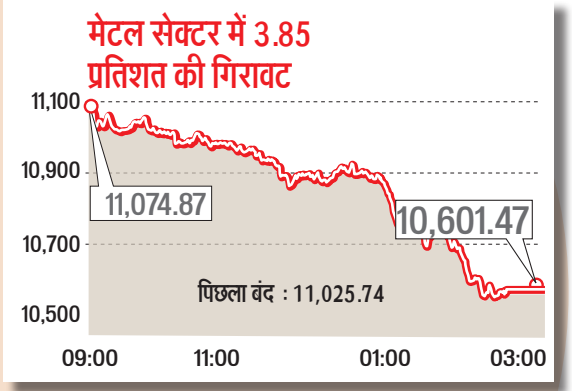

कंपनियों के कारपोरेट टैक्स में कटौती

- बड़ी राहत : 99 .3 प्रतिशत कंपनियों पर अब सिर्फ 25 प्रतिशत टैक्स
- बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में नहीं दी राहत
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया करदाताओं का धन्यवाद

400
करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां दायरे में

0.7
प्रतिशत कंपनियों पर लगेगा 25 फीसद से अधिक कारपोरेट टैक्स

हरिकिशन शर्मा ● नई दिल्ली

कारपोरेट टैक्स की दर चरणबद्ध ढंग से घटाने की प्रतिबद्धता को निभाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने आम बजट 2019-20 में मझोली कंपनियों को टैक्स में बड़ी राहत दी है। अब 400 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली घरेलू कंपनियों पर 25 प्रतिशत कारपोरेट टैक्स ही लगेगा। अब तक यह सुविधा 250 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को ही प्राप्त थी। केंद्र के इस कदम के बाद अब 99.3 प्रतिशत कंपनियां कारपोरेट टैक्स के 25 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। इस तरह मात्र 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी होंगी जिन पर 25 प्रतिशत से अधिक कारपोरेट टैक्स लगेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार-2 का पहला आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। सीतारमण ने कहा, 'जहां तक कारपोरेट टैक्स का संबंध है, हम दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते रहेंगे।' जिन घरेलू कंपनियों का वित्त वर्ष 2017-18 में सालाना टर्नओवर 400 करोड़ रुपये तक था, वे कारपोरेट टैक्स के 25 प्रतिशत वाले स्लैब के दायरे में आ जाएंगी। हालांकि किसी कंपनी की सालाना आय अगर एक करोड़ रुपये से अधिक है तो उस पर सात प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगता रहेगा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 का आम बजट पेश करते हुए कारपोरेट टैक्स में चरणबद्ध ढंग से कटौती कर चार साल में 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत पर लाने और कंपनियों को मिल रही विभिन्न प्रकार की टैक्स छूट समाप्त करने का एलान किया था। इसके बाद उन्होंने 2017 के बजट में इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए उन कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का फैसला किया जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से कम था। इसके बाद सरकार ने 2018-19 के बजट में सालाना 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी कारपोरेट टैक्स की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर दी थी।

लंबित टैक्स विवाद निपटाने के लिए नई स्कीम का एलान

मोदी सरकार उद्योग जगत को कारपोरेट टैक्स में सीधे राहत देने के साथ ही परोक्ष टैक्स से संबंधित लंबित विवादों को निपटाने का मौका भी देने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले आम बजट में लंबित टैक्स विवादों को निपटाने के लिए एक नई योजना 'लीगेसी डिस्प्यूट रिसोल्यूशन स्कीम' लाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पूर्व की व्यवस्था के बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। सेवा कर और उत्पाद शुल्क संबंधी मुकदमों में 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक फंसा हुआ है। इस भार को कम करने और कारोबार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने व्यापारियों और व्यवसायियों को इस अवसर का लाभ उठाने और मुकदमेबाजी से मुक्त होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद 17 टैक्स और 13 सैस इस एक टैक्स में समाहित हो गए हैं। सरकार ने अब तक जीएसटी के तहत कारोबारियों को प्रति वर्ष 92,000 करोड़ रुपये की राहत दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई रिटर्न प्रणाली एक जनवरी, 2020 से लागू हो जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंवॉइस सिस्टम की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी जिसके बाद ई-वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

करोड़पतियों से अब ज्यादा टैक्स वसूली

हरिकिशन शर्मा ● नई दिल्ली

आम बजट 2019-20 से राहत की आस लगाए बैठे मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में राहत नहीं दी है। सरकार ने राष्ट्र निर्माण में करदाताओं के योगदान के लिए उनका धन्यवाद करते हुए खजाना भरने के लिए करोड़पतियों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। अब दो करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज अधिक लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019-20 पेश करते हुए बजट भाषण में कहा कि जिनकी सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है, उन पर टैक्स बोझ कम करने के उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। पांच लाख रुपये तक सालाना आय वालों को आयकर भुगतान करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में करदाताओं के योगदान के लिए धन्यवाद किया।

वित्त मंत्री ने कहा, 'जिनकी आय अधिक है, उन्हें राष्ट्र निर्माण में अधिक योगदान करने की आवश्यकता है। इसलिए जिन व्यक्तियों की आय दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक और पांच करोड़ रुपये से अधिक है उन पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव करती हैं।' वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव के बाद दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक सालाना आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज बढ़कर 25 प्रतिशत तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज बढ़कर 37 प्रतिशत हो जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इस कदम के बाद दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स की प्रभावी दर तीन प्रतिशत तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स की प्रभावी दर सात प्रतिशत बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद आयकर से छूट की सालाना आय की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी थी। तब से लेकर अब तक सरकार ने यह सीमा नहीं बढ़ाई है। हालांकि मोदी सरकार ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक के स्लैब पर आयकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करके करदाताओं को छूट दी थी। इसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को रिझाने के लिए सरकार ने अंतरिम बजट 2019-20 में उन व्यक्तिगत करदाताओं को राहत दी थी जिनकी सालाना कर-योग्य आय पांच लाख रुपये है। ऐसे करदाताओं को टैक्स में छूट के रूप में राहत दी थी।

400
करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनी पर 25 प्रतिशत टैक्स, पहले यह 250 करोड़ की कंपनी पर लगाया जाता था।

05
लाख तक सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं।

01
साल में 1 करोड़ से ज्यादा बैंक से राशि निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

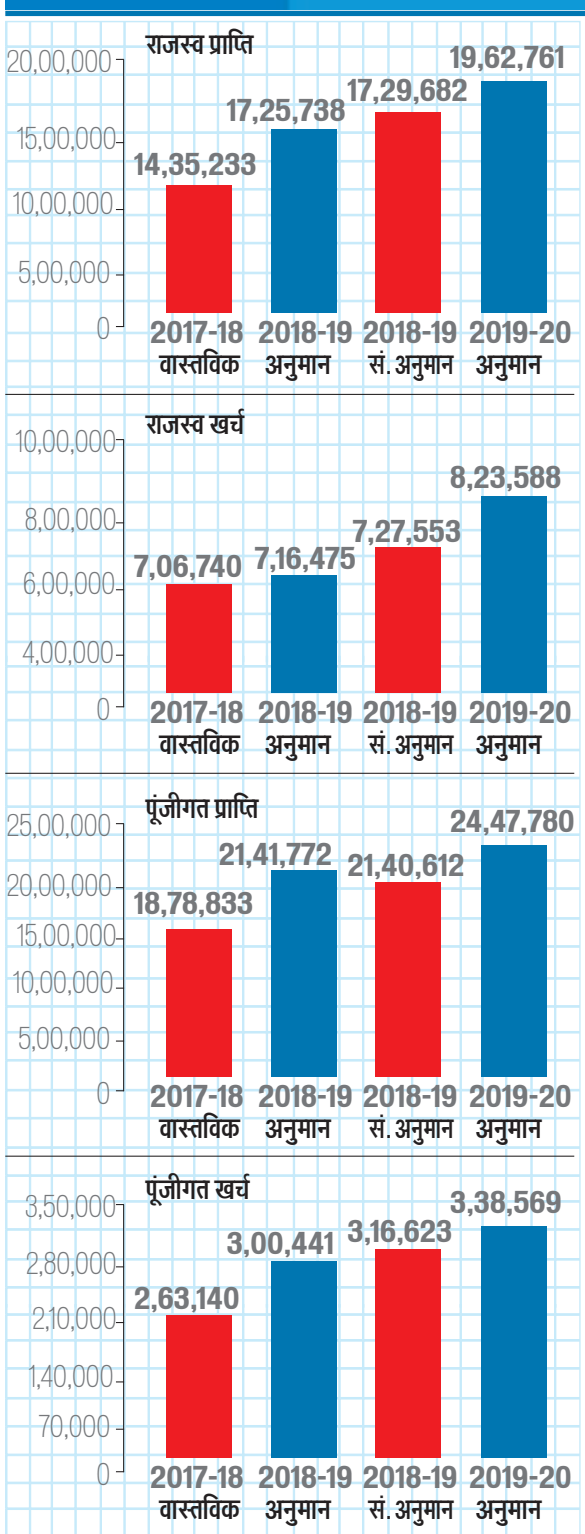

बाजार से 3,900 अरब रुपये जुटाने का दांव

जागरण ब्यूरो ● नई दिल्ली

पूंजी बाजार में नए निर्गमों से नई जान फूंकने की कोशिश करते हुए वित्त मंत्री ने न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम के जरिए शेयर जारी करने की मौजूदा सीमा 25 फीसद को बढ़ा कर 35 फीसद कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पूंजी बाजार में उतरने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों को कुल शेयर में कम से कम 35 फीसद हिस्सेदारी बाजार के जरिए हस्तांतरित करनी होगी। वैसे 25 फीसद की मौजूदा सीमा का पालन करने के लिए सरकार व बाजार नियामक एजेंसी सेबी को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 10 फीसद और शेयर जारी करने का मतलब हुआ कि बाजार में तकरीबन 3900 अरब रुपये के शेयर और जारी किए जा सकते हैं। यह आकलन मौजूदा सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार मूल्य के आधार पर किया गया है। पूंजी बाजार के अलावा वित्त मंत्री ने देश में एक सशक्त ऋण बाजार स्थापित करने के लिए भी कई उपायों का ऐलान किया है जिसके दूरगामी फायदे हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के साथ मिलकर केंद्र सरकार कॉरपोरेट ऋण बाजार को लेकर जल्द ही कुछ नए उपायों का एलान करेगी। इसका फायदा यह होगा कि कंपनियों को पूंजी जुटाने का एक और जरिया मिल जाएगा।

खास बातें

न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम के जरिए 35 फीसद शेयर बेच सकेंगी कंपनियां

तकरीबन एक चौथाई कंपनियों को जारी करने पड़ सकते हैं शेयर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, 'अब समय आ गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों में जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। मैंने सेबी को कहा है कि वह मौजूदा न्यूनतम हिस्सेदारी की सीमा 25 फीसद से बढ़ा कर 35 फीसद करने का फैसला करे।'

देश के पूंजी बाजार में तकरीबन 1,173 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। इनमें से एक-चौथाई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें प्रवर्तकों की हिस्सेदारी अभी 65 फीसद से ज्यादा है। यानी इन सभी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचकर नए नियम के मुताबिक 65 फीसद तक लानी होगी। सनद रहे कि जब सरकार ने 25 फीसद की सीमा जारी की थी तब भी उसके पालन करवाने में सेबी के पसीने छूट गए थे। जानकारों का कहना है कि अगर बजट की घोषणा लागू हो जाती है तो टीसीएस को 59,600 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर जारी करने पड़ सकते हैं जबकि अन्य आइटी कंपनी विप्रो को 15 हजार करोड़ रुपये के शेयर जारी करने पड़ेंगे।

सरकारी उपक्रमों को भी पूंजी बाजार से राशि जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का जो लक्ष्य रखा है उसका भी एक बड़ा हिस्सा पूंजी बाजार से जुटाया जाएगा। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों से ही सरकार तकरीबन 11,000 करोड़ रुपये से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है जो शेयर बाजार के जरिए ही होगा। इसी तरह से वित्त मंत्री ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आसान केवाइसी नियमों का ऐलान किया है। समाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को भी बाजार से पैसा जुटाने की छूट देने का एलान किया गया है। इसके लिए सेबी की निगरानी में सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस एक्सचेंज से संगठनों को पूंजी बाजार, ऋण बाजार या म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा जुटाने की इजाजत होगी। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होगी। लेकिन जिस तरह से देश के शेयर बाजार ने बजटीय प्रावधानों को लेकर निराशा जताई है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। बीएसई का सेंसेक्स बजट पेश करने की प्रक्रिया की शुरुआत में 40 हजार के स्तर को पार कर गया था लेकिन बाद में यह 395 अंकों की गिरावट के साथ 39,513 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।

मध्य वर्ग को इनकम टैक्स छूट के साथ राहत दी गई है और छोटे कारोबारियों को भी कई लाभ प्रदान किए गए हैं। घर-घर तक एलपीजी, पेयजल और बिजली पहुंचाने का फैसला सराहनीय है।
-जेपी नड्डा, भाजपा नेता

यह सहकारी संघवाद नहीं है। यह गैर-बराबरी वाली साझेदारी है, जो केंद्र ने राज्यों पर थोप डाली है। बजट में न तो आम नागरिक की सुनी गई है और न ही जानकार अर्थशास्त्रियों की।
-पी चिदंबरम, पूर्व वित्त मंत्री

पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी हुए महंगे

जागरण ब्यूरो ● नई दिल्ली

पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सिगरेट और आयातित कार और एयर कंडीशनर महंगे हो जाएंगे। सरकार ने आम बजट 2019-20 में 75 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी और पेट्रोल-डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी व सड़क एवं अवसंरचना सैस में एक रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वृद्धि की है, इससे इनकी कीमत बढ़ जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जे, मोबाइल फोन के चार्जर और सेट टॉप बॉक्स जैसी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि 'मेक इन इंडिया' हमारा लक्ष्य है। इसलिए घरेलू उद्योग को समान अवसर मुहैया कराने के लिए टाइल्स, मेटल फिटिंग, फर्नीचर माउंटिंग, ऑटो पार्ट्स सहित कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भारत में बनाए जा रहे हैं, उन पर मिल रही मौजूदा कस्टम ड्यूटी छूट को अब समाप्त किया जा रहा है। इसके अलावा घरेलू प्रकाशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयातित पुस्तकों पर पांच प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

2019-20
का बजट पेश करते हुए बोलीं वित्त मंत्री मेक इन इंडिया हमारा लक्ष्य

बनेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज, समाजिक संगठन जुटाएंगे पैसा

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आसान होंगे केवाइसी नियम

वित्त मंत्री ने कच्चे तेल के आयात पर एक रुपये प्रति टन के हिसाब से आयात शुल्क भी लगाने की घोषणा की। सरकार के इन कदमों से पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 2.5 रुपये और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 2.3 रुपये की वृद्धि हो जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा, 'सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर भी कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत की जा रही है।' वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एवं कस्टम ड्यूटी में वृद्धि से सरकारी खजाने में 25,000 करोड़ रुपये आएंगे। सीतारमण ने कहा कि कस्टम ड्यूटी में वृद्धि के बजट प्रस्ताव सरकार ने देश की सीमाओं की रक्षा के उद्देश्य से तैयार किए हैं। इनका मकसद 'मेक इन इंडिया' को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने, एमएसएमई क्षेत्र के संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन और गैर-जरूरी आयात को कम करना है।

वित्त मंत्री ने बीड़ी व सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर 10 पैसे से लेकर 10 रुपये प्रति हजार की दर से एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी है। क्योंकि तंबाकू उत्पादों पर नेशनल केलामिटी एंड कंटीजेंट ड्यूटी लगाने का विरोध यह कहकर किया जाता था कि इन पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी लागू नहीं है।

श्रम कानूनों का जाल तोड़ने की बड़ी कवायद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : श्रम क्षेत्र में काफी अर्से से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 44 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताएं बनाने का प्रस्ताव किया है। इनका मकसद पुराने श्रम कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर उन्हें नए समय के अनुरूप प्रासंगिक बनाना है। इनमें से वेतन व न्यूनतम वेतन से संबंधित चार कानूनों को एक संहिता में बदलने का फैसला सरकार पिछले हफ्ते कर चुकी है। इससे राज्यों में अलग मिलने वाली मजदूरी की प्रथा खत्म होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश बजट में इन घोषणाओं के साथ श्रम सुधारों को लेकर सरकार के रुख को साफ किया है। सरकार के इस कदम की झलक आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखने को मिली थी। जिसमें श्रमिकों से जुड़ी न्यूनतम मजदूरी की विसंगतियों को खत्म करने का सुझाव दिया गया था। इन सुधारों के पीछे मकसद न्यूनतम मजदूरी की विसंगतियों को दूर करना है तथा एक समान व तर्क संगत मजदूरी ढांचे को लागू करना है। यह सुधार इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि मौजूदा समय में केवल 18 राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है। उसमें भी हर राज्य में मजदूरी की दरें अलग-अलग है। जिसमें नगालैंड में सबसे कम मजदूरी है।

इसी तरह देश में कुल 44 पुराने श्रम कानून अस्तित्व में हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। इनमें कुछ कानून फैक्ट्रियों के पंजीकरण से संबंधित है तो कुछ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संबंधों तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हैं। ये सब अब अप्रासंगिक हो चुके हैं और औद्योगिक उत्पादन व प्रगति साथ कर्मचारियों की भलाई में बाधक साबित हो रहे हैं। इसीलिए सरकार इनमें संशोधन कर चार कानूनों में समेट रही है।

विशेषज्ञ टिप्पणी

राकेश भार्गव,
निदेशक, टैक्समैन

पूरी नहीं हुई आम आदमी की उम्मीदें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। राजग सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। हालांकि वित्त मंत्री ने उन करदाताओं को भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के लिए धन्यवाद दिया है जो अपने करों का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी निराश हैं क्योंकि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती नहीं दिख रही है। बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़ी कर रियायत की घोषणा नहीं की गई है। यह देखना होगा कि वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम में क्या प्रस्ताव किया है जिससे आम आदमी प्रभावित होगा।

आवास ऋण पर ब्याज पर अतिरिक्त कटौती : आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए कर्ज पर लगने वाले ब्याज को लेकर आयकर में 1.50 लाख रुपये तक की राहत देने के लिए एक नई धारा 80ईईए जोड़ी गई है। यह लाभ उन्हीं आवासीय संपत्तियों पर मिल सकेगा जिनका स्टांप शुल्क 45 लाख से ज्यादा नहीं होगा। इस छूट का उद्देश्य सरकार के 'सभी के लिए आवास' लक्ष्य को बल देना और घर खरीदारों को समर्थ बनाना है।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कर्ज के ब्याज पर भी राहत : किसी भी वित्तीय संस्थान से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के वास्ते लिए गए कर्ज के ब्याज पर भी आयकर में 1.5 लाख रुपये की राहत मुहैया कराने के लिए एक नई धारा 80ईईबी जोड़ी गई है। करदाता के पास कर्ज मंजूर होने की तारीख तक यदि कोई दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होगा तो उसे इस छूट का लाभ मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना समय की मांग है। अब ऐसे हालात हैं कि इससे बचना सही नहीं होगा। यह ठीक है कि सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने की योजना है।

आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य : ऐसे करदाता जिनके करेंट अकाउंट में एक करोड़ रुपये या इससे अधिक जमा हैं या विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये या इससे ज्यादा खर्च करते हैं या एक लाख रुपये या इससे ज्यादा का बिजली बिल भरते हैं तो उनके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है।

पैन लेने में राहत : सरकार ने आम आदमी को बहुउद्देश्यीय पहचान सुबूत हासिल करने में राहत दी है। इसके लिए पैन और आधार की अनुमति दी है। यदि किसी व्यक्ति को पैन आवंटित नहीं है तो अब वह आधार नंबर से आयकर रिटर्न भर सकेगा। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने अपने आधार नंबर को लिंक करा लिया है तो वह पैन की जगह आधार से आईटी रिटर्न भर सकता है।

अधिभार दरों में बदलाव : वित्त मंत्री ने उच्च आय वर्ग के लोगों पर लगने वाले अधिभार दरों में बदलाव किया है। एचयूएफ, एओपी, बीओआइ और एजेपी के लिए अधिभार दर 10 फीसद (50 लाख से ज्यादा एक करोड़ रुपये तक की आय के लिए) होगा। एक करोड़ से ज्यादा और दो करोड़ रुपये तक की आय के लिए 15 फीसद, दो करोड़ से ज्यादा और पांच करोड़ रुपये तक की आय पर 25 फीसद और पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर अधिभार 37 फीसद होगा।

सरकार ने आम आदमी को बहुउद्देश्यीय पहचान सुबूत हासिल करने में राहत दी है। यह वाकई सकारात्मक बात है...

'स्फूर्ति' से फूटेगी ग्रामीण रोजगार की धारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 'स्फूर्ति' योजना का एलान किया है। इस योजना से ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजी रोटी के साधन बढ़ेंगे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। यहां की जनता कृषि और पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश अपने बजट भाषण में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत बांस, शहद और खादी उद्योग के क्लस्टर बनाए जाएंगे।

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। इसी के तहत गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की योजना है। स्फूर्ति योजना के तहत वर्ष 2019-20 में कुल 100 क्लस्टर बनाने की योजना है, जिसमें 50 हजार ग्रामीण शिल्पकारों को इस आर्थिक वैल्यू चैन में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। इसके तहत उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम को चालू किया गया है। संसद में पेश बजट में कृषि व ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75 हजार कुशल उद्यमियों के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष 2019-20 में ही 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण उद्योगों के खत्म होने से रोजगार हालात और खराब हुए हैं। हालांकि, सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के मार्फत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना शुरु कर रखी है, लेकिन उसका प्रभाव फिलहाल संतोषजनक नहीं दिख रहा है। उसे रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी। ग्रामीण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित क्लस्टर बनाने की योजना है।

बातें बड़ी और काम छोटे : कैप्टन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : केंद्रीय बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इसमें समाज के किसी भी वर्ग को कुछ नहीं दिया गया। यहां तक कि रक्षा जैसे अहम क्षेत्र को भी अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें ऐतिहासिक प्रकाश पर्व संबंधी समारोहों के लिए भी फंड की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने इसे बड़ी बातें और छोटे काम वाला बजट बताया। बजट में जिक्र की गई प्राप्तियां पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यों का प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्रीय प्रगति में दिए गए कांग्रेस के किसी भी योगदान को मिटाने की कोशिश कर रही है। कैप्टन ने कहा कि 'जीरो बजट कृषि' का प्रस्ताव एक ढोंग है, जबकि किसानों की समस्याओं के हल के लिए इसमें कुछ नहीं है। किसान कर्ज माफी स्कीम के संबंध में एक बार फिर पूरी तरह असफल रहने के कारण उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की।

खजाने की खातिर

- सात लाख करोड़ रुपये उधारी से आएंगे
- एक लाख करोड़ रुपये विनिवेश के जरिए
- राजस्व प्राप्तियों में कमी से बढ़ेगा राजस्व घाटा

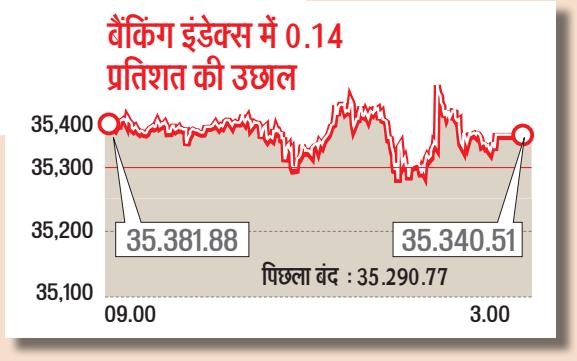

राजकोषीय घाटा काबू में, पर राजस्व घाटा बढ़ा

भारत पर जो बाहरी कर्ज है वो जीडीपी के अनुपात में पांच प्रतिशत से कम है, वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा बेहतर माना जाता है।

तय रोडमैप के हिसाब से चल रही सरकार

भले ही बीते वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 3.4 फीसद पर पहुंचा, लेकिन वह इसके लिए तय रोडमैप के हिसाब से चल रही है। रोडमैप के मुताबिक सरकार को 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के तीन फीसद के स्तर तक लाना है। हालांकि बीते वित्त वर्ष में जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के चलते सरकार का राजस्व संग्रह कुछ कम रहा। सरकार ने व्यय में कमी के जरिए राजकोषीय संतुलन को बनाने में सफलता हासिल भी की। देश की वित्तीय सेहत को बनाये रखने में ईंधन का खर्च काफी महत्वपूर्ण होता है। ईंधन भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। कच्चा तेल खरीदने के लिए सरकार को सबसे ज्यादा रकम चुकानी होती है। रणनीति के तहत ई-कार पर फोकस करके ईंधन की खपत को कम करके तेल पर होने वाले खर्च को कम करना है।

3.3
फीसद जीडीपी के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के लिए रखा गया है। फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में यह लक्ष्य 3.4 फीसद का था

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नए भारत के निर्माण की दिशा में अतिरिक्त व्यय की फिसलन के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को फिर से पटरी पर ले आई है। सरकार ने इस अवधि के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 फीसद लक्ष्य का एलान किया है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में सरकार ने 3.4 फीसद का लक्ष्य रखा था।

वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को 3.3 फीसद पर रखने की घोषणा की। सरकार ने इस अवधि में 7,03,760 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। बीते वित्त वर्ष (2018-19) के लिए घोषित संशोधित अनुमानों के मुताबिक देश का राजकोषीय घाटा 6,34,398 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। यह रकम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसद है।

सरकार ने बजट में स्पष्ट किया है कि वह सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसीलिए बीते वित्त वर्ष की तुलना में सरकार ने व्यय में 3,29,114 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। लिहाजा सरकार चालू वित्त वर्ष (2019-20) में कुल 27,86,349 करोड़ रुपये का व्यय करेगी। इसमें सरकार का होने वाला व्यय 24,47,780 करोड़ रुपये है। लेकिन इसकी तुलना में सरकार की राजस्व प्राप्तियां चालू वित्त वर्ष में 19,62,761 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस लिहाज से स्4,85,019 करोड़ रुपये का राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। यह जीडीपी का 2.3 फीसद है, जो बीते वित्त वर्ष के 2.2 फीसद की तुलना में अधिक है।

राजस्व प्राप्तियों के मद में सरकार को चालू वित्त वर्ष में 16,49,582 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त गैर-कर राजस्व (नॉन-टैक्स रेवेन्यू) के मद में 3,13,179 करोड़ रुपये आने का अनुमान लगाया गया है। इसी अवधि में सात लाख करोड़ रुपये उधारी से आएंगे और एक लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक की राशि विनिवेश से प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त सरकार के पास राजस्व का कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं है। जानकार मानते हैं कि राजकोषीय संतुलन बनाए रखने का दबाव रहेगा। सरकार के व्यय का प्रश्न है, तो उसमें ब्याज भुगतान की भी बड़ी हिस्सेदारी है। चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान में मद में सरकार ने 6,60,471 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए रखी है। साथ ही कैपिटल असेट्स के सृजन के लिए 2,07,333 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पूंजी खाते पर सरकार की तरफ से 3,38,569 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

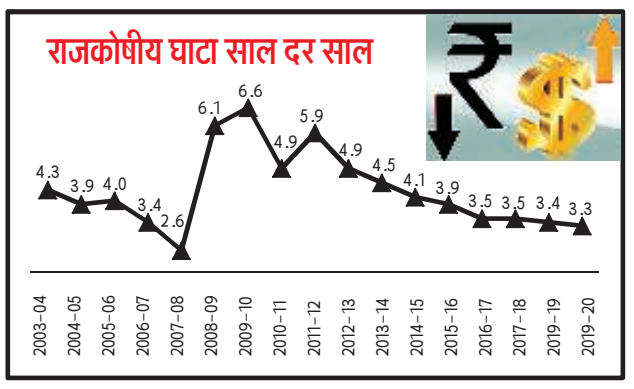

पहले से मानना था कि रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा पैसा नहीं आवंटित होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि राजकोषीय घाटा काबू में रहे।

400 करोड़ रुपये तक के राजस्व वाली सभी कंपनियों को 25 फीसद टैक्स के दायरे में लाने का कदम सराहनीय है। इससे कंपनियों को फायदा होगा और निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्थ मजबूत होगी।
विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर, प्रेसिडेंट, भारतीय उद्योग परिसंघ

बजट कैश आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस की तरफ ले जाने वाला है। सरकार और आरबीआइ की कोशिशों से भारत अगले पांच साल में डिजिटल पेमेंट का अंतरराष्ट्रीय हब बन सकता है।
दिलीप आस्वे, एमडी एवं सीईओ, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

बीज उद्योग को उम्मीद थी बजट में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के हमारे लक्ष्य के लिए कोई रोडमैप दिया जाएगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए इनोवेटिव बीज तकनीक का विकल्प मिलना चाहिए।
श्रीराम कौंडिन्य, डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए एफडीआइ नियम आसान करने की घोषणा से अंतरराष्ट्रीय सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनियों के लिए भारत आकर्षक बाजार बन जाएगा।
अनिल तलरेजा, पार्टनर, डेलॉय

खजाना भरने के लिए विनिवेश का होगा सहारा

105000
करोड़ का लक्ष्य लेकर रणनीतिक विनिवेश पर होगा सरकार का जोर

एयर इंडिया में सरकार विनिवेश की फिर करेगी कोशिश

बैंकों के विलय की तर्ज पर सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में इसी मॉडल पर हो सकता है विचार

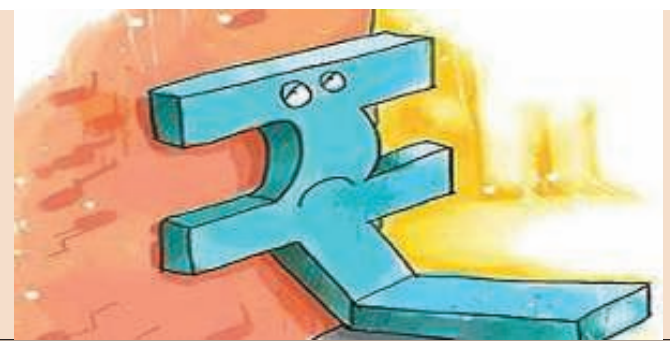

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तर्ज पर ईटीएफ में भी निवेश स्कीम की गुंजाइश

सरकारी उपक्रमों में 51 फीसद इक्विटी हिस्सेदारी बनाए रखने की अपनी नीति पर विचार करेगी सरकार

पिछले साल सरकार ने विनिवेश के जरिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के जरिए सरकारी हिस्सेदारी को कम करने की उसकी नीति पहले की तरह जारी रहेगी। इसके तहत सरकार का जोर रणनीतिक विनिवेश पर रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस नीति को बनाये रखने का ऐलान करते हुए कहा कि एयर इंडिया में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया फिर शुरू करेगी। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश से 105000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री ने कहा, 'सरकार पीएसयू की रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनायेगी।' बजट के जरिए सरकार ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वह गैर वित्तीय क्षेत्रों में भी पीएसयू को मजबूत तथा सुसंगठित बनाये रखने का काम जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए और लिस्टेड पीएसयू को और अधिक वाणिज्यिक व बाजारोन्मुखी बनाने के लिए सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी ि साथ ही सभी पीएसयू कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी को अधिकतम स्वीकृत सीमा तक बढ़ाया जा सके। विनिवेश के साथ साथ सरकार ईटीएफ के जरिए भी सार्वजनिक उपक्रमों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में गंभीरता पूर्वक कदम बढ़ा रही है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि इसे और बढ़ाने के लिए सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तर्ज पर ईटीएफ में निवेश का एक विकल्प प्रदान करेगी।

इससे सार्वजनिक उपक्रमों में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार गैर वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों में अपने निवेश को कम करने की नीति अपना रही है। हालांकि अभी सरकार की नीति ऐसे सभी उपक्रमों में अपनी 51 फीसद इक्विटी हिस्सेदारी बनाये रखने की है, लेकिन ऐसे उपक्रमों जिन्हें अभी सरकार के नियंत्रण में बनाये रखने की आवश्यकता है उनमें 51 फीसद से नीचे एक निश्चित सीमा तक इक्विटी घटाने के मामलों पर भी विचार कर सकती है। हालांकि सरकार ने तय किया है कि वह सरकारी उपक्रमों में 51 फीसद इक्विटी हिस्सेदारी बनाये रखने की अपनी नीति पर विचार करेगी।

सरकार ने पिछले साल भी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि विनिवेश के जरिए जुटाई थी, लेकिन मूलतः यह राशि एचपीसीएल को ओएनजीसी के साथ विलय करने की वजह से आयी। हालांकि सरकार ने इस दिशा में चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में किसी तरह का इरादा जाहिर नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह बैंकों के विलय पर विचार चल रहा है आगे चलते हुए सार्वजनिक उपक्रमों में भी इस मॉडल को जारी रखा जा सकता है।

संसाधन जुटाने के लिए अहम होगी उधार की रकम

448122
करोड़ रुपये बाजार उधारी से आएंगे

उधार की मद में सात लाख करोड़ से अधिक राशि जुटाने का लक्ष्य

अंतरराष्ट्रीय बाजार से विदेशी मुद्रा में सरकार जुटाएगी संसाधन

जाव्यू, नई दिल्ली : राजकोषीय संतुलन बनाने रखने की कवायद में सरकार के लिए चालू वित्त वर्ष में उधार से जुटाई जाने वाली राशि काफी अहम होगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में इस मद में सात लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसमें बाजार उधारियों की हिस्सेदारी चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार का जोर विभिन्न स्रोतों से राजस्व जुटाने पर रहेगा, लेकिन कर और गैर कर राजस्व से संसाधन जुटाने के बावजूद राजस्व और व्यय के बीच भारी अंतर रह जाता है। आमतौर पर सरकारें इसे उधारियों के जरिए पूरा करती हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने कुल 703760 करोड़ रुपये की राशि उधार और अन्य देयताओं के मद से जुटाने का फैसला किया है। इस मद में पिछले वित्त वर्ष में 634398 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई थी। इसके अलावा ऋणों की वसूली के मद में सरकार 14828 करोड़ रुपये जुटाएगी।उधार के मद में बाजार उधारियां अहम भूमिका निभाती हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार का इरादा 448122 करोड़ रुपये बाजार उधारी से जुटाने का है। पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 447737 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। सरकार यह राशि वित्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के जरिए बांड जारी करके जुटाती है। इसके तहत रिजर्व बैंक विभिन्न अवधि में परिपक्व होने वाले बांड जारी करता है जिन पर अलग अलग दरों से ब्याज मिलता है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उधारी जुटाने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय बाजारों से विदेशी मुद्रा में राशि जुटाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उधारी कार्यक्रम की शुरुआत विदेशी बाजारों से करेगी। जानकार बताते हैं कि विदेशी बाजारों से उधारी जुटाने की एक वजह यह भी है कि वहां से संसाधन जुटाने की लागत अभी कम है। ऐसे में भारतीय कंपनियों और सरकार दोनों के लिए लाभ की स्थिति हो सकती है।बाजार उधारियों को बहुत अधिक सकारात्मक नजरिए से नहीं देखा जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी अधिक उधारी सरकार बाजार से उठाती है उस पर ब्याज भुगतान का बोझ उतना ही बढ़ता है। इससे ब्याज दरें और मुद्रास्फीति की दर भी प्रभावित होती है।

राज्यों को कर राजस्व में आठ लाख करोड़ की हिस्सेदारी

2017-18
के मुकाबले 2019-20 में राज्यों की हिस्सेदारी 20 फीसद बढ़ी

2019-20
में केंद्र प्रायोजित स्कीमों के मद में मिलेंगे 292003 करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यों और विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों की कर राजस्व में हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है। साल 2017-18 के मुकाबले 2019-20 में बीस फीसद से अधिक की वृद्धि हुई है। साल 2019-20 के बजटीय प्रावधानों के मुताबिक इन राज्यों और संघशासित प्रदेशों को इस मद में 809133 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। जबकि 2017-18 में इन्हें 673006 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

वित्त वर्ष 2019-20 के बजट के मुताबिक केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों को 292003 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। बीते वित्त वर्ष यानी 2018-19 में इस मद में राज्यों व संघशासित प्रदेशों को 277414 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। जबकि उसके पहले के वित्त वर्ष यानी 2017-18 में 262043 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को मिली थी। विधानमंडल वाले राज्यों के मामले में जहां तक दिल्ली और पुदुचेरी को वित्त वर्ष 2019-20 में 10028 करोड़ रुपये की कर हिस्सेदारी मिलने का अनुमान बजट में लगाया गया है। इसमें केंद्र प्रायोजित स्कीम में 2026 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। बीते वित्त वर्ष यह राशि क्रमशः 8310 और 1336 करोड़ रुपये थी।

राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के मद में कर राजस्व की हिस्सेदारी में 15000 करोड़ रुपये की राशि मिलने की उम्मीद है। बीते वित्त वर्ष में इस मद में 13500 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। इसके विपरीत बाह्य सहायता वाली परियोजनाओं के मद में राज्यों को चालू वित्त वर्ष में 19723 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। बीते वित्त वर्ष में इस मद में राज्यों को 23801 करोड़ रुपये की राशि मिली थी।

राज्यों को कर में हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। फिलहाल 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्यों को कर राजस्व में हिस्सेदारी दी जा रही है। इसके तहत कुल कर राजस्व का 42 फीसद आवंटन होता है। वर्ष 2015 से पूर्व इस मद में राज्यों को कुल कर राजस्व का 32 फीसद आवंटन किया जाता था। सरकार पूर्व राजस्व सचिव एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन भी कर चुकी है। इसकी सिफारिशें इसी वर्ष आने की उम्मीद हैं जिन पर अमल 2020 से होने की उम्मीद है।

वित्तीय प्रबंधन के खास उपाय अपनाने की रणनीति

राजकोषीय नीति का आशय वित्त प्रबंधन के लिए खास उपायों के अपनाने से है। इसकी मदद से सरकार खर्चों के स्तर और टैक्स की दरों को एडजस्ट करती है। इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। यह वैसे ही होता है जैसे मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक सिस्टम में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इन दोनों ही नीतियों को मिलाजुला कर देश के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

किसी भी तरह का टैक्स लगाने से पहले सरकार को यह देख लेने की जरूरत है कि ईमानदार करदाताओं को बेवजह की परेशानी नहीं हो। टैक्स के संदर्भ में लिमिट और एक्जेम्पशन को उचित रखना चाहिए। यह देखते हुए कि पहले से करदाता कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर चुका रहे हैं।

2019-20
के आंकड़ों के अनुसार सरकार की राजस्व प्राप्ति 2019-20 के अप्रैल-मई में बजटीय अनुमान का 7.3 प्रतिशत रही। एक साल पहले इसी अवधि में राजस्व प्राप्ति इतनी ही थी।

3,66,157
करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार निरपेक्ष रूप से रहा।

55.3
प्रतिशत राजकोषीय घाटा इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी अवधि में बजटीय लक्ष्य का था

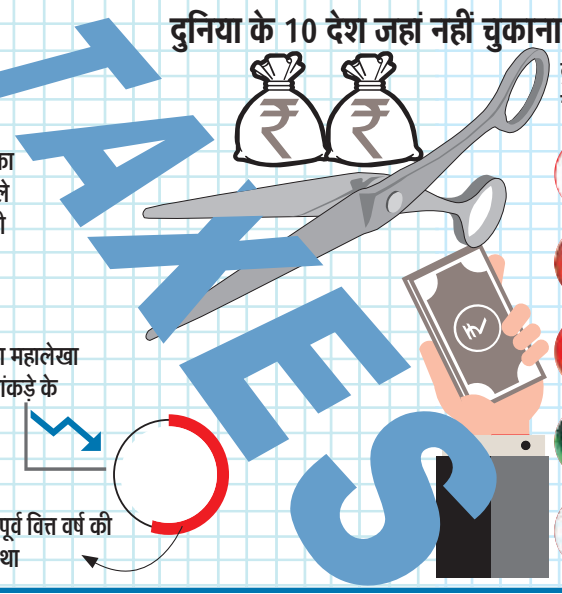

दुनिया के 10 देश जहां नहीं चुकाना पड़ता है आयकर

दुनिया के ऐसे देश जो तेल भंडारों के जरिए समृद्ध हो चुके हैं, वहां आयकर का अस्तित्व नहीं है।

- कतर
- कुवैत
- ओमान
- बरमूडा
- यूनाइटेड अरब अमीरात
- बहमास
- सऊदी अरब
- मोनैको
- बहरीन
- हॉन्ग-कॉन्ग

विशेषज्ञ टिप्पणी

राधिका पांडे
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

सुस्त अर्थव्यवस्था में जान डालने की कोशिश

सरकार का पहला आम बजट ऐसे समय में पेश किया गया है, जब अर्थव्यवस्था विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही है। सरकार पर यह लगातार दबाव बना हुआ था कि वह सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खर्च को बढ़ावा देने के उपाय करे। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने अर्थव्यवस्था के विकास को रफ्तार देने के लिए राजकोषीय कंसोलिडेशन के रोडमैप से हटते हुए बड़े पैमाने पर व्यय को अपनाने या राजकोषीय कंसोलिडेशन के रोडमैप पर बने रहने के विकल्प में से किसी एक का चुनाव करने की मुश्किल चुनौती थी। राजकोषीय रोडमैप से बड़े पैमाने पर विचलन से उधारी बढ़ जाती है, ब्याज दरों में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति होती है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अपने राजकोषीय कंसोलिडेशन रोडमैप को बनाए रखने के विकल्प का चुना है। बजट से पहले ही किसानों और छोटे कारोबारियों के फायदे के लिए सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं की घोषणा कर दी गई थी। इन योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाने का काम रह गया था। चालू वित्तवर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.4 फीसद से घटाकर 3.3 फीसद कर दिया गया है।

राजस्व के मोर्चे पर, कई सकारात्मक निर्णयों की घोषणा की गई है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हैं और व्यवसायी समुदाय लंबे समय से इसे कम करने की मांग कर रहा था। बजट में सालाना 400 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर को कम करने का फैसला किया गया है। सरकार ने अपने विनिवेश लक्ष्य को भी 80,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसके लिए कई सरकारी कंपनियों (सीपीएसई) में रणनीतिक बिक्री की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि एयर इंडिया में रणनीतिक बिक्री उनके रेडार पर है। सरकार को पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण हेतु संसाधन पैदा करने के लिए सरकारी कंपनियों (पीएसयू) में अपनी हिस्सेदारी कम करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेहत सुधारने के लिए 70,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में टैक्स चुकाने वाले लोगों की गाढ़ी कमाई लगाने की रणनीति पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। सरकारी बैंकों की दक्षता और शासन में सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि वे निवेश में घरेलू बचत के मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

सालाना पांच लाख से कम आय वाले लोगों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे भी खपत बढ़ने की उम्मीद है। सस्ते आवास, स्टार्ट-अप और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वहीं, अमीरों के लिए अधिभार बढ़ाया गया है। बजट की बड़ी खासियत यह है कि सरकार अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं से मिलने वाले लाभांश पर निर्भर है। रिजर्व बैंक से मिलने वाला लाभांश सरकार और आरबीआइ के बीच विवाद की जड़ रहा है। बजट में आरबीआइ, सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 1.06 लाख करोड़ लाभांश मिलने का अनुमान लगाया गया है।

बजट में सरकार के ऋण ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। बजट में प्रस्तावित किया गया है कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा में उधार लेगी। सरकारी ऋण में खुदरा निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। आरबीआइ और सेबी विनियमित जमाकर्ताओं के बीच अंतर-संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। इसमें तेजी लाई जानी चाहिए और सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए और कदम उठाए जाने चाहिए।

● लेखिका एनआइपीएफपी में वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं।

400 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर को कम करने के फैसले से अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में तेजी आएगी।

रक्षा मंत्री के बाद राजग सरकार-2 में वित्तमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाली निर्मला सीतारमण पर पूरे देश की निगाहें थीं। बजट पेश करने संसद भवन पहुंचने पर मीडिया के कैमरों से घिरी वित्तमंत्री के लिए सहयोगियों को रास्ता बनाना पड़ा ● जागरण

बढ़ेगी अंतरिक्ष में ताकत

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का होगा गठन

- वित्त मंत्री को उम्मीद, कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के व्यवसायीकरण की अगुआ बनेगी
- एनएसआईएल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) को पिछले कुछ वर्षों में मिली सफलता और भारत को दुनिया में अंतरिक्ष शक्ति के रूप में मिली नई पहचान के बाद अब मोदी सरकार इसरो की इस व्यावसायिक क्षमता का अच्छी तरह दोहन करने जा रही है। इसके लिए उसने इसरो की एक कमर्शियल यूनिट 'न्यू स्पेस इंडिया' लिमिटेड का गठन किया है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में अपना पहला बजट भाषण पेश करते हुए घोषणा की है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को अंतरिक्ष विभाग की एक नई वाणिज्यिक इकाई के रूप में शुरू किया गया है। यानी यह फैसला एक तरह से अंतरिक्ष में भारत की ताकत में इजाफा करने का एक बड़ा कारक साबित होगा।

सीतारमण ने कहा कि 'एनएसआईएल' का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी। इसमें लांच व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है। उन्होंने कहा, कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के व्यवसायीकरण का अगुआ बनेगी। इसरो के केंद्रों और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) की घटक इकाइयों के अनुसंधान और विकास कार्यों के व्यवसायिक दोहन के लिए एनएसआईएल को डीओएस के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत छह मार्च को निगमीकृत किया गया था।

इसरो ने स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में लांच करने के साथ साथ विदेशी उपग्रहों को लांच करने के वैश्विक बाजार पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, इसीलिए अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग हो।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पंहुच जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्र यान, गगन यान जैसे प्रमुख योजनाओं के बारे बताया।

गौरतलब है कि 15 जुलाई को चंद्र यान-2 लांच किया जाएगा। यह भारत का पहला मून लैंडर और रोवर मिशन है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले लैंडर मॉड्यूल का नाम जाने-माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया है जबकि रोवर मॉड्यूल का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसके अलावा इसरो के मानव मिशन गगन यान पर भी तेजी से काम चल रहा है। यह अति महत्वाकांक्षी योजना है

इसरो ने स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में लांच करने के साथ विदेशी उपग्रहों को लांच करने के वैश्विक बाजार पर भी अपनी पकड़ की हैमजबूत

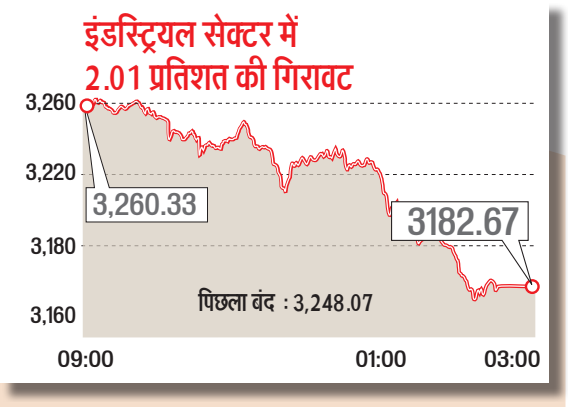

59 मिनट में मिलेगा छोटे कारोबारियों को ऋण। 01 करोड़ रुपये तक का लोन पोर्टल के माध्यम से मिलेगा

1.5 करोड़ तक अधिकतम टर्नओवर वाले खुदरा कारोबारियों को पेंशन पर विचार, बैंक खाते-आधार से मिलेगी पेंशन

03 करोड़ से अधिक दुकान मालिकों को इस योजना से मिलेगा लाभ।

पेट्रोल के दाम बढ़ने से डिलीवरी स्टार्टअप्स को लगाझटका

जोमैटो और स्विगी जैसे डिलीवरी स्टार्टअप्स की ऑपरेशनल लागत में इजाफा होगा क्योंकि सरकार ने सड़क और डीजल पर पेट्रोल और पेट्रोल पर बुनियादी ढांचे पर एक रुपये का विशेष अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है।

स्टार्टअप्स के लिए सीबीडीटी की ओर से की गई है खास व्यवस्था

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्टार्टअप्स से संबंधित लंबित समीक्षाओं और मामलों के लिए सीबीडीटी की ओर से खास व्यवस्था की जाएगी।

आम बजट में विदेशी हथियारों पर सीमा शुल्क में राहत

शिवांग माथुर • नई दिल्ली

1,12,079.57 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं सरकार ने बजट में रक्षा पेंशन के लिए।

431,010.79 करोड़ रुपये का है कुल रक्षा आवंटन

300 करोड़ रुपये की खरीदारी का अधिकार है अभी सेना के पास बिना इजाजत

सेनाओं के आधुनिकीकरण और रक्षा उपकरणों की खरीद को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में ऐसे रक्षा उपकरणों पर से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है जिनका निर्माण भारत में नहीं हुआ है। सरकार के इस फैसले से विदेशों से खरीदे जाने वाले रक्षा उपकरणों की भारत में पूर्ति करने में आसानी होगी।

वित्त मंत्री निर्मली सीतारमण ने शुक्रवार को पेश बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की लेकिन सीमा शुल्क में राहत देकर यह जरूर साफ कर दिया कि सरकार की मंशा भविष्य के रक्षा सौदों को लेकर सकारात्मक है। यह पहला मौका है जब किसी वित्त मंत्री के बजट भाषण में रक्षा से जुड़े खास आवंटन की घोषणा संसद में नहीं की गई है। हालांकि आम बजट से रक्षा क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन सरकार ने अंतरिम रक्षा बजट आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया है। जो राशि अंतरिम बजट में आवंटित की गई थी उसी को आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,12,079.57 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कुल रक्षा आवंटन लगभग 431,010.79 करोड़ रुपये का है जो आने वाले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के कुल खर्च का 15.47 फीसद है। बजट में रक्षा सेवाओं, पेंशन आदि के लिए तो पर्याप्त आवंटन है, क्योंकि यह वास्तविक व्यय के आधार पर ही है। लेकिन आधुनिकीकरण की राशि ज्यादा नहीं है। इसलिए इसका असर नई रक्षा खरीद पर पड़ सकता है। दरअसल, कई खरीद परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं, उनका भुगतान होना है। दूसरी तरफ एचएएल में बड़े पैमाने पर तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण होना है जिसका भुगतान रक्षा मंत्रालय को करना होगा। दूसरे रक्षा उपक्रमों को भी मंत्रालय ने कई कार्य दिए हैं। लेकिन बजट में आवंटन नहीं बढ़ने से उनके पूरा होने में विलंब हो सकता है। इससे पहले बीते फरवरी में पीयूष गोयल ने बतौर कार्यवाहक वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करते हुए वन रैंक, वन पेंशन के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे। सैनिकों की यह मांग 40 साल से लंबित पड़ी थी। इस बजट में सरकार ने रक्षा क्षेत्र लिए तीन लाख करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया था। भारतीय इतिहास में पहली बार रक्षा सेक्टर के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ। रक्षा क्षेत्र के चार अहम पहलू रक्षा पेंशन, पूंजी परिव्यय, राजस्व और सिविल रक्षा सेवाएं के लिए राशि का आवंटन किया गया है।

यदि बीते छह वर्षों के बजट को देखें तो हर बार के रक्षा बजट में वृद्धि हुई है मगर इस बार रक्षा मंत्री ने इसमें कुछ वृद्धि नहीं की। रक्षा मामलों से जुड़े लोगों ने इस पर हैरानी भी जताई है। उनका कहना है कि निर्मला सीतारमण पहले रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, इस वजह से उनसे तो यही उम्मीद थी, वहीं दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि चूंकि वह रक्षा मंत्री रह चुकी हैं इस वजह से उनको यह बेहतर पता है कि सेना को बिना इजाजत 300 करोड़ की खरीदारी का अधिकार है, इसी वजह से इसमें और वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे तरह की है इस वजह से यहां बाकी सेक्टरों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है न की रक्षा बजट में और अधिक वृद्धि की।

'नारी तू नारायणी' पर जहां वित्तमंत्री को खूब वाहवाही मिली तो लोक सृजन कला को प्रोत्साहित करने की हिन्दी में घोषणा कर उन्होंने बटोरी ताली

टेक्नोलॉजी के उपयोग और जिम्मेदारी में बढ़ोतरी से देश में पारदर्शिता बढ़ेगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम सबका सपना है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आए, मोदी सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
– **किरण बेदी**, राज्यपाल, पुदुच्चेरी

बजट में किस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है यह स्पष्ट नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि विकास को तेज करने वाले उपाय किए जाएंगे। यह बजट विकास को धीमा करने वाला है।
– **जयंत पाटिल**, प्रमुख, महाराष्ट्र एनसीपी

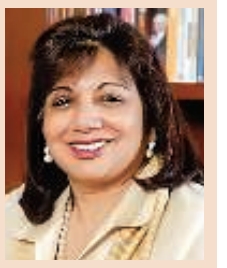

एक कारोबारी महिला होने के नाते एक महिला वित्त मंत्री को भरोसा बढ़ाने वाला बजट पेश करते देखकर अत्यधिक गौरव हो रहा है। उम्मीद है कि यह बजट महिलाओं को नई ताकत देगा।
– **किरण मजूमदार शॉ**
चेयरपर्सन, बायोकॉन

बजट विकास में तेजी लाने वाला नहीं है। शेयर बाजार में भी अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। यानी बाजार का सेंटीमेंट इसकी पुष्टि कर रहा है।
– **आदि गोदरेज**, चेयरमैन, गोदरेज समूह

गहरे डूबे एनबीएफसी को निकालने की बड़ी कोशिश

- बड़ी राहत : फंसे एनबीएफसी की परिसंपत्तियों को खरीदेंगे बैंक
- एनबीएफसी पर आरबीआइ के अधिकारों में होगी बढ़ोतरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश के वित्तीय ढांचे में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) फिलहाल सबसे कमजोर कड़ी बने हुए हैं और यह उम्मीद थी कि आम बजट इस बारे में गंभीरता से कदम उठाएगा। वित्त मंत्री ने एनबीएफसी को लेकर दो अहम घोषणाएं की हैं जिसका निश्चित तौर पर दूरगामी व सकारात्मक असर होगा। इसमें एक कदम है संकटग्रस्त एनबीएफसी की अच्छी परिसंपत्तियों को खरीदने की व्यवस्था की गई है। यह खरीद सरकारी बैंक करेंगे और इसके लिए केंद्र की तरफ से उन्हें ऋण देने की गारंटी दी गई है। दूसरा उपाय एनबीएफसी के नियमन का है। अभी भी इनके नियमन का अधिकार आरबीआइ के पास है लेकिन अब केंद्रीय बैंक के अधिकार को और मजबूत बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में देश की अर्थव्यवस्था में एनबीएफसी के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि, देश में मांग बढ़ाने के साथ ही छोटे व मझोले उद्योगों को कर्ज देने में इस सेक्टर का योगदान काफी अहम है। मजबूत एनबीएफसी को बैंक व म्यूचुअल फंड से अतिरिक्त संशाधन मिलना जारी रहना चाहिए। इसके आगे उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी सरकारी बैंकों को देने का ऐलान किया। यह गारंटी इसी वर्ष दी जाएगी और इसका इस्तेमाल सरकारी बैंक फंसे एनबीएफसी की परिसंपत्तियों को खरीदने में कर सकेंगे। इन घोषणाओं के साथ ही आम बजट में एनबीएफसी के लिए पूंजी बाजार से राशि जुटाने की राह आसान करने का भी ऐलान किया गया है। अभी एनबीएफसी के लिए पूंजी बाजार से राशि जुटाने पर एक खास डिबेंचर रिडेंपशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की बाध्यता है जिसे खत्म किया जाएगा। इस रिजर्व का इस्तेमाल आपातकाल में डिबेंचर्स निवेशकों की राशि लौटाने के लिए होता है। हाल के महीनों में एनबीएफसी को सबसे ज्यादा समस्या तरलता को लेकर हुई है और उक्त दोनों उपाय इसे संकट को दूर करने में मदद करेंगे। सनद रहे कि कुछ महीने पहले देश की एक बड़ी एनबीएफसी आइएलएंडएफएस का संकट सामने आया था। अभी कुछ हफ्ते पहले एक दूसरे एनबीएफसी डीएचएफएल का संकट भी सामने आ गया है। उक्त दोनों वित्तीय कंपनियों में तमाम बैंकों व निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।

एनबीएफसी सेक्टर को जिस उपाय से सबसे ज्यादा फायदा होगा वह है आरबीआइ की नियमन शक्तियों को बढ़ाना। सरकार की मंशा है कि आरबीआइ को एनबीएफसी पर नियमन को लेकर वैसे ही अधिकार दिए जाए जैसे वाणिज्यिक बैंकों को लेकर है। यह अधिकार मिल जाने पर आरबीआइ समय रहते ही आइएलएंडएफएस जैसी घटना को दोबारा होने से रोक सकेगा।

बेरोक-टोक दौड़ी निर्मला की पहली बजट एक्सप्रेस

संजय मिश्र • नई दिल्ली

- चुनाव नतीजे की छाया का दिखा असर, शांति ऐसी रही कि स्पीकर को एक बार भी टोकने का नहीं मिला मौका
- बजट भाषण के दौरान कई दिलचस्प नजारों से रूबरू हुआ सदन

चुनाव नतीजों की सियासी छाया का असर नई सरकार के पहले बजट में पूरा नजर आया। दशकों बाद संभवतः यह पहला मौका था कि वित्तमंत्री के सबसे लंबा बजट भाषण के दौरान लोकसभा में सियासी नोंक-झोंक तो दूर मामूली शोर तक नहीं हुआ। करीब सवा दो घंटे तक लोकसभा में पक्ष और विपक्ष लगभग खामोशी के साथ वित्तमंत्री के बजट भाषण को सुनते रहे। संसद में बजट पेश होने ल्६६ हमेशा ही राजनीतिक खींचतान और नुक्ताचीनी का केंद्र बिंदु रहा है मगर लोकसभा में अबकी बार दिखी में खामोशी चुनाव नतीजों से बदली फिंजा का असर रहा।

नई सरकार का पहला बजट इस लिहाज से भी ऐतिहासिक रहा कि निर्मला सीतारमण ने देश की पहली पूर्णकालिक वित्तमंत्री के तौर पर यह बजट पेश किया। स्पीकर ओम बिडला ने बजट पेश होने के बाद यह गौरव हासिल करने के लिए निर्मला को सदन में बधाई भी दी। वैसे यह उपलब्धि हासिल करने के लिए वित्तमंत्री को गर्मजोशी के साथ बधाई व शुभकामनाएं देने का सिलसिला बजट पेश करने से पहले ही शुरू हो गया। सुबह ग्यारह बजे बजट भाषण शुरू होने से करीब पांच मिनट पहले सीतारमण जब लोकसभा में पहुंची तो भाजपा की करीब दर्जन भर महिला सांसदों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए शुभकामनाएं दी। सुनहरे बार्डर वाली मैरून रंग की साड़ी पहन सदन में आयीं निर्मला ने बजट भाषण शुरू करने से पूर्व स्पीकर दर्शक दीर्घा में बैठे अपने माता-पिता का अभिवादन किया। वित्तमंत्री की बेटी वानमयी भी नाना-नानी के साथ दर्शक दीर्घा में अपनी मां की उपलब्धियों पर गौरव के अंदाज में लगातार मुस्कुरातीं दिखीं।

वैसे तो वित्तमंत्री के भाषण में तमिल भाषा की चर्चित सारगर्भित पंक्तियों का बोलबाला रहा मगर उन्होंने हिन्दी, संस्कृत और उर्दू की ऐसी पंक्तियों का भी उपयोग किया। महिलाओं की बराबर की भागीदारी के बिना देश का विकास अधूरा रहने के लिए 'नारी तू नारायणी' की पंक्ति पर जहां वित्तमंत्री को खूब वाहवाही मिली तो लोक सृजन कला को प्रोत्साहित करने की हिन्दी में घोषणा कर उन्होंने सबसे ज्यादा ताली बटोरी।

लोकसभा में विपक्ष की खामोशी का आलम कैसा रहा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे सवा दो घंटे के बजट भाषण के दौरान स्पीकर ओम बिडला को एक बार भी किसी सदस्य को टोकने के लिए मुंह नहीं खोलना पड़ा।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए

उत्तम होगा उद्यम

ऑनलाइन पोर्टल बनेगा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे विल भुगतान में लेट लतीफी की दिक्कत दूर करने के लिए। एमएसएमई को पोर्टल से निवेश में बड़ा फायदा होगा।

02% की छूट मिलेगी व्याज सवर्वेशन स्कीम के तहत सभी नए और पहले से चल रहे लोन पर चालू वर्ष में

350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं एमएसएमई के लिए।

एसएसई

सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएसई बनेगा सामाजिक उद्यम वाली कंपनियों और स्वयंसेवी संगठनों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए

मेक इन इंडिया

- मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है।
- सीमा शुल्क में बढ़ोतरी का असर यह होगा कि विदेश से आने वाले सामान महंगे होंगे।

स्टार्टअप प्रमोशन

एक्सक्लूसिव टीवी चैनल- उद्योग में सूचनाओं के प्रसार के लिए स्टार्टअप्स को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन के तहत स्टार्टअप्स के लिए एक एक्सक्लूसिव टीवी चैनल होगा।

ई-वेरीफिकेशन

अपेक्षित घोषणाएं दाखिल करने वाले स्टार्टअप और निवेशक, शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की छानबीन के अधीन नहीं होंगे। ई-सत्यापन सिस्टम से होगा यह मुमकिन।

एनआरआई को तत्काल मिलेगा आधार कार्ड, खत्म होगी छह महीने की प्रतीक्षा

भारत के सॉफ्ट पावर में होगी और बढ़ोतरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की बढ़ती धमक में और इजाफा करने के लिए सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को स्वदेश आने पर तत्काल आधार कार्ड जारी करने का फैसला किया है। साथ ही वैश्विक कूटनीति में भारत की अहम भूमिका के लिए इस साल चार देशों में भारत का दूतावास खोलने का भी ऐलान किया गया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए विश्व पटल पर नये भारत के सॉफ्ट पावर की हो रही चर्चा का जिक्र करते हुए ये दोनों अहम घोषणाएं की। भारत के साफ्ट पावर को दुनिया भर में फैलाने में एनआरआई समुदाय के योगदान के मद्देनजर सरकार ने उन्हें स्वदेश आते ही आधार कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। वित्तमंत्री ने कहा कि अभी अनिवासी भारतीयों को स्वदेश लौटने के 180 दिन बाद ही आधार कार्ड दिया जा सकता है। मगर अब छह महीने के इंतजार की यह अवधि खत्म कर तत्काल आधार कार्ड जारी किया जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को ज्यादा गति देने के लिए सरकार ने उन देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है जहां अभी तक हमारा कोई राजनयिक मिशन नहीं हैं। सरकार ने इसीलिए 2019-20 में चार नये दूतावास खोलने का प्रावधान किया है। इससे पूर्व बीते वित्त वर्ष में भारत ने पांच नये दूतावास रवांडा, जिबूती, भूमध्य गिनी, रिपलिब्क आफ गिनी और बुर्किना फासो में खोले हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि इससे न केवल विदेशों में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी बल्कि उन देशों में विशेष रुप से स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर तथा सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकेगी।

वित्तमंत्री ने बीते तीन सालों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए 192 देशों में योग का अभ्यास किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि भारत के साफ्ट पावर की अलग-अलग तरीके से सराहना की जाती है। महात्मा गांधी का प्रिय भजन 'वैष्णव जन तेने कहिए' 40 देशों के नाम-गिरामी कलाकारों द्वारा गया जाना भी इसका एक उदाहरण है।

भारत के दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की जिम्मेदारी के साथ दूसरे देशों को विकास में मदद देने की पुरानी परंपरा के अनुरूप विकासशील देशों की सहायता के मॉडल को मजबूत बनाया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय विकास सहयोग स्कीम (आइडीइएएस) जो विकासशील देशों को रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराती है उसकी स्कीम में चालू वित्त वर्ष के दौरान बदलावों पर गौर करेंगी।

180 दिन का नहीं करना होगा इंतजार अब अनिवासी भारतीयों को

04 नये देशों में खोले जाएंगे भारतीय दूतावास इस साल

विशेषज्ञ टिप्पणी

आर्थिक मजबूती देने वाला बजट

संदीप सोमानी
प्रेसिडेंट, फिक्की

केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट ऐसे कठिन समय में पेश किया गया है जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि में हाल की तिमाहियों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। सरकार के लिए सबसे कठिन कार्य इस संबंध में समुचित कदम उठाने से जुड़ा था ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके।

बुनियादी ढांचा, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से जुड़ी परियोजनाओं में पहले से जारी नीति को बरकरार रखना भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी न आने का कारण रहा है। सरकार की उपलब्धि को गिनाने का एक बड़ा आंकड़ा यह भी है कि अपनी गतिविधियों के जरिये सरकार मुद्रा स्फीति को 3.3 प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रही है। बजट में व्यापक रूप से तमाम क्षेत्रों को शामिल करते हुए सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2024-25 तक भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है।

सरकार ने संकेत दिया है कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आगामी पांच वर्षों में वह 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो इस क्षेत्र में एक बड़ा सकारात्मक कदम है। इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त मुहैया कराते हुए उन्हें तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की गतिविधियों को नया आयाम मिल सकता है। बुनियादी ढांचों के निर्माण कार्य में तेजी आने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और निवेश चक्र को मजबूती मिलेगी। इससे सीमेंट, स्टील और वाणिज्यिक वाहनों जैसे निर्माण गतिविधियों से जुड़े सेक्टर में मांग में बढ़ोतरी होगी। साथ ही अन्य संबंधित क्षेत्रों पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा। इससे नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दशा को सुधारने के लिए तरलता स्थिति को आसान बनाने के उपायों की कवायद करते हुए 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने की घोषणा की गई है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी सुधार की राह पर अग्रसर करने के लिए मदद दी जाएगी। इससे उधार लेने और खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग और छोटे उद्यमों को इससे फायदा होगा।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर भी बजट में पूरा फोकस किया गया है जो अर्थव्यवस्था में इसकी महत्ता को दर्शाता है। शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ गांवों में मकान निर्माण की दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार ने खेती से जुड़े बुनियादी ढांचों की अनेक योजनाओं की घोषणा की है। मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य पारंपरिक उद्योगों को भी क्लस्टर- आधारित विकास मॉडल के जरिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

बुनियादी ढांचों के निर्माण कार्य में तेजी आने से नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे जो अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती है

Downloaded from: www.iascgl.com

दैनिक जागरण
संकल्प से ही लक्ष्य संभव होता है

देश का बही-खाता

बही-खाते के रूप में आया आम बजट अगर इस अनुमान के अनुकूल नहीं कि प्रबल बहुमत से सत्ता में लौटी मोदी सरकार बड़े आर्थिक सुधारों की राह पर अवश्य आगे बढ़ेगी तो इसके पीछे ऐसे ठोस कारण हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। सबसे बड़ा कारण देश-दुनिया के आर्थिक हालात हैं। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है तो विश्व अर्थव्यवस्था उथल-पुथल से ग्रस्त होने के साथ ही संरक्षणवाद से भी दो-चार है। चूंकि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य मोदी सरकार को जोखिम लेने की इजाजत नहीं दे रहा था इसलिए उसने उससे बचते हुए आर्थिक सुधारों के साथ ही जरूरी सामाजिक सुधारों को गति देने की भरसक कोशिश की है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आम बजट के प्रावधान यह रेखांकित कर रहे हैं कि मोदी सरकार इस वित्तीय वर्ष के साथ-साथ अपने शेष कार्यकाल के लिए भी एक खाका पेश करना चाह रही थी। शायद इसीलिए बुनियादी ढांचे में अगले पांच साल में सौ लाख करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा प्रकट किया गया है। यह एक बड़ी राशि है। इससे यह पता चलता है कि सरकार छलांग भी लगाना चाहती है और साथ ही अगले पांच वर्षों में देश को पांच लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था भी बनाना चाहती है। यह एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन देश की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए यह समय की मांग थी कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ बड़े लक्ष्य तय किए जाएं।

देश को पांच लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सालाना आठ प्रतिशत विकास दर की दरकार होगी। यह समय बताएगा कि मोदी सरकार विकास दर के इस आंकड़े को हासिल कर पाएगी या नहीं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि आम बजट के जरिये देश के समग्र विकास की चिंता करते हुए कुछ बुनियादी समस्याओं के समाधान का भी संकल्प लिया गया है। यह अच्छा है कि हर घर को बिजली पहुंचाने और हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ जल संकट को दूर करने की चिंता सरकार की प्राथमिकता में है। चूंकि जल संकट दूर करने के अभियान को सफल बनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि इसमें जितनी जरूरत जन भागीदारी की है उतनी ही सरकारी तंत्र के सहयोग की भी। इसी क्रम में सरकार और साथ ही उसकी मशीनरी को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित खर्च के लिए वांछित धन की प्राप्ति वास्तव में हो। यह राहतकारी है कि आम बजट के माध्यम से सरकार ने यह प्रदर्शित किया कि उसे अपने इस लक्ष्य का स्मरण है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने का समय करीब आ रहा है। आम बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने भी यह उम्मीद जताई कि बजटीय प्रावधान उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ कारोबार जगत को गति प्रदान करेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वास्तव में ऐसा हो। निःसंदेह ऐसा तभी होगा जब कारोबार जगत के अनुकूल माहौल का निर्माण भी हो सकेगा।

बंगाल बिजनेस समिट

पिछले आठ वर्षों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवेशकों को बंगाल की ओर आकर्षित करने का प्रयास करती आ रही हैं। विदेशों में निवेशकों से मिलने के साथ-साथ बंगाल में भी कई बार उद्योग सम्मेलन आयोजित कर चुकी हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। 2015 से ममता सरकार राज्य में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित करती आ रही हैं। बड़े पैमाने पर हर वर्ष इस उद्योग सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि आगे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हर दो साल पर होगा। बिजनेस समिट का पांचवां संस्करण इस साल फरवरी में हुआ था। ममता ने विधानसभा में कहा-'हर साल राज्य सरकार बड़े निवेश प्रस्तावों का एलान करती है। महत्वपूर्ण यह है कि नए प्रस्तावों की दिशा में कदम उठाने से पहले इन प्रस्तावों पर आगे बढ़ा जाए और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अब से हम बिजनेस समिट को हर दो साल में आयोजित करेंगे।' उन्होंने बाद में कहा कि अगला बीजीबीएस 2021 में आयोजित होगा। यहां बताना आवश्यक है कि 2021 में आगामी विधानसभा चुनाव भी होना है। पिछले तीन बिजनेस समिट में केंद्र सरकार की ओर से एक भी मंत्री नहीं पहुंचा। हालांकि देश-विदेश के बड़े उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधिदल जुटते थे। हर वर्ष दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आने का दावा किया जाता रहा, लेकिन देखा जा रहा है कि बड़े उद्योग बंगाल में अब तक नहीं लग पाए हैं। ऐसे में इस उद्योग सम्मेलन को लेकर विपक्षी पार्टियां-माकपा, कांग्रेस से लेकर भाजपा तक यह सवाल करने लगी हैं कि करोड़ों रुपये खर्च कर इतने तामझाम के साथ उद्योग सम्मेलन करने का नतीजा क्या निकल रहा है? वहीं ममता बनर्जी भी शायद मानने लगी हैं कि हर वर्ष सम्मेलन करने से उद्योगपतियों के बीच भी आकर्षण कम हो जाता है। जितने निवेश प्रस्ताव आए हैं, वे सभी क्रियान्वित हो जाएं तो भी स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुई हैं। वहीं भाजपा भी बंगाल में 18 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दे चुकी है।

सतत विकास के लिए प्रयास

धर्मकीर्ति जोशी

मौजूदा मुश्किलों का हल निकालने के लिए बजट में कुछ कदम उठाने की कोशिश हुई है ताकि वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। इसके लिए ज्यादा जोखिम नहीं लिया गया

पूरी दुनिया के साथ भारत भी इस वक्त आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट इसी अनिश्चितता के दौर में पेश हुआ। पांच महीने पहले पेश अंतरिम बजट से लेकर मौजूदा माहौल में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। इसकी वजह भी स्पष्ट है। हालात इतनी जल्दी नहीं बदलते। जुलाई 2014 के पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में मंदी के बाद भी संप्रग सरकार के अंतरिम बजट के राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल किया था। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद 2014 की तरह इस बार भी इस मोर्चे पर कामयाब रही। हालांकि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की जरूरत फरवरी में आए अंतरिम बजट की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ गई है। वित्त मंत्री के समक्ष प्रश्न यह नहीं था कि क्या वृद्धि को तेजी देने के लिए राजकोषीय अनुशासन से समझौता किया जाए, बल्कि यह था कि वृद्धि में आ रही गिरावट को देखते हुए क्या राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी एफआरबीएम एक्ट में जताई गई प्रतिबद्धता के लिहाज से कोई छूट ली जा सकती है या नहीं? सरकार ने वित्त वर्ष 2019 में वित्त वर्ष 2020 के लिए राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य तय किया था उसे अंतरिम बजट में 20 आधार अंक बढ़ा दिया। बहरहाल केंद्र और राज्यों का जीडीपी के अनुपात में कर्ज का मिश्रित आंकड़ा भारत के बराबर रेटिंग वाले देशों में काफी ऊंचा है। ऐसे में राजकोषीय घाटे में जरा भी कटौती की कोई गुंजाइश नहीं थी।

सरकार ने समझदारी के साथ इस मोह को छोड़ते हुए राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूती से जाहिर किया। इसके तहत चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 3.3 प्रतिशत कर दिया जो पहले 3.4 प्रतिशत तय किया था। निवेश, निजी उपभोग और निर्यात में सुस्ती स्पष्ट है। इसके चलते वित्त वर्ष 2019 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर सिकुड़कर 6.8 प्रतिशत रह गई जो वृद्धि का पांच साल में सबसे न्यूनतम स्तर है। जीडीपी के अनुपात में घरेलू बचत घटी है। इससे सरकारी घाटे की भरपाई और निजी निवेश के लिए उपलब्ध बचत कोष का आकार भी घटा है। वहीं कर्ज की सूखी धारा में नई जान डालने के लिए सरकारी बैंकों के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वे एनपीए के बढ़ते बोझ से त्रस्त हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी में उनके काफी संसाधन फंसे हुए हैं।

इस लिहाज से मौजूदा मुश्किलों का हल निकालने के लिए बजट में कुछ समाधान निकालने का प्रयास हुआ है जिनसे वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा जोखिम नहीं लिया गया और मध्यम अवधि की रणनीतिक चुनौतियों की अनदेखी नहीं की गई। रियल एस्टेट और एनबीएफसी को मिलने वाली मदद से कुछ मुश्किलें जरूर हल होंगी। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से भी कर्ज देने की उनकी क्षमता में सुधार होगा। यदि वृद्धि की रफ्तार सुस्त होती है तब चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का 3.3 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने कर संग्रह में 9.5 प्रतिशत का मामूली वृद्धि का ही अनुमान व्यक्त किया है जो कि बजट में 12 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि की दर से कम है। ऐसे में विनिवेश से लेकर सरकारी परिसंपत्तियों को सही तरह से भुनाने की दरकार होगी। ऐसा करते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूंजीगत व्यय से कोई समझौता न किया जाए।

बजट में राजकोषीय संयम का पहला संदेश तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए है कि वह मौद्रिक नीति में कुछ नरमी कर सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि राजकोषीय नीति ही मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णायक आधार होती है। वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में अभी तक 75 आधार अंकों की कटौती की है और हम अगली समीक्षा में एक और कटौती की उम्मीद कर सकते हैं। कमतर राजकोषीय घाटा सरकारी बांडों के लिए भी शुभ संकेत हैं जो पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों की नरम नीतियों से दबाव का सामना कर रहे हैं।

बजट और मौद्रिक नीति से निजी उपभोग को कुछ सहारा मिलेगा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से वृद्धि की रफ्तार जोर पकड़ेगी, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती तब अपना असर दिखाएगी। न्यूनतम आय समर्थन से किसानों और कर रियायतों से मध्य वर्ग के हाथ में जो पैसा पहुंचेगा उससे उपभोग मांग में इजाफा होगा, क्योंकि इस तबके में उच्च वर्ग की तुलना में मांग को प्रभावित करने की क्षमता कहीं अधिक है। बहरहाल चालू वित्त वर्ष में वृद्धि की चाल कुछ हद तक बजट के नियंत्रण से बाहर है। वास्तव में मानसून और कच्चे तेल की कीमतों का रुख भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

अगर इस बार लगातार चौथे साल मानसून सामान्य के बराबर रहता है और कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा दरों के दायरे में रहती हैं तो भारत की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। वहीं अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य और अपर्याप्त वर्षा के चलते वृद्धि में गिरावट की आशंका बढ़ सकती है। जून में वर्षा सामान्य से 36 प्रतिशत कम रही, लेकिन फसल उत्पादन के लिए जुलाई-अगस्त की वर्षा और उसका समान वितरण कहीं अधिक मायने रखता है। यदि ऐसा हुआ और खाद्य उत्पादों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी किसानों की जेब में पहुंचती है तब ग्रामीण मांग में सुधार समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत की वृद्धि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो विनिर्माण में 50 प्रतिशत और सेवा में एक चौथाई हिस्से को प्रभावित करती है।

इसके अलावा कुछ नीतिगत कदम भी निवेशकों के भरोसे को बढ़ा सकते हैं जिससे वृद्धि को सहारा मिलेगा। इसके लिए बजट में बुनियादी ढांचे पर एकदम सही तरह से ध्यान दिया गया है। विनिर्माण में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की गई है और इसके लिए आवंटन का दायरा बढ़ाने के बजाय कर प्रोत्साहन के जरिये आकर्षक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की कवायद की गई है। इससे विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी और वे उत्पादन इकाइयां भी भारत का रुख कर सकती हैं जो अमेरिका-चीन की तनातनी के बाद चीन से बाहर निकलने की जुगत कर रही हैं।

राजस्व जुटाने के लिए सरकार ने करों पर ज्यादा दांव नहीं लगाया है। वह विनिवेश और अपनी अन्य परिसंपत्तियों पर अधिक भरोसा कर रही है। सरकार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल को भी नए सिरे से पेश करने की दरकार है जिसमें दोनों पक्षों के लिए जोखिम साझेदारी संतुलित हो। अर्थव्यवस्था की तेज और सतत वृद्धि के लिए निजी निवेश को पटरी पर लाना बेहद आवश्यक है।

(लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

कम कमाई और ज्यादा खर्च का संकट

देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए जो लेखा-जोखा सामने रखा उसके अनुसार सरकार 2019-20 में 27.86 लाख करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है, लेकिन इस साल सरकार की कुल कमाई 20.82 लाख करोड़ रुपये रहने की ही उम्मीद है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 7.04 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रहेगा। सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर ही राजकोषीय घाटा है। ऊपरी तौर पर देखें तो 3.3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा सीमित दिखाई देता है, लेकिन जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, द डेविल इज इन द डिटेल तो इस वर्ष सरकार जितना टैक्स जुटाना चाहती है उससे यही लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही आशान्वित है। इस साल सरकार आयकर से 5.69 लाख करोड़ रुपये जुटाने की आशा रखती है। यह पिछले वित्त वर्ष से 23.3 प्रतिशत अधिक है। सरकार इस साल तीन लाख करोड़ रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुटाने की उम्मीद कर रही है। यह भी पिछले साल से करीब 30 फीसद अधिक है। सीमा शुल्क से 1,55,904 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद की गई है, लेकिन यह बीते बरस से करीब 32.2 फीसद ज्यादा है। सरकार को कंपनी कर और जीएसटी में करीब 15 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। इस उम्मीद के बीच इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि इस वित्त वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रही है। अगर कारों, दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री जैसे संकेतकों को देखें तो लगता है कि अर्थव्यवस्था पिछले साल से और भी ज्यादा कमजोर पड़ गई है। ऐसे में इन करों में सरकार के मन मुताबिक वृद्धि काफी मुश्किल लगती है।

सरकार इस साल विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ जुटाएगी। यह पिछले साल से करीब 31.3 फीसद अधिक है। देखना यह है कि सरकार असल विनिवेश करती है या फिर एक सरकारी कंपनी को दूसरी सरकारी कंपनी को बेचती है? जनवरी 2018 में ओएनजीसी ने एचपीसीएल को 36,915 करोड़ रुपये देकर खरीदा। इसके लिए कंपनी को करीब 25,000 करोड़ रुपये उधार लेना पड़ा था। ऐसे विनिवेश का कोई अर्थ नहीं। असली विनिवेश तब होगा जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी कंपनियों को बेचेगी, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा होता नहीं दिखता। इसके बावजूद विनिवेश की प्रक्रिया में एक अच्छी चीज यह हुई है कि सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष बनाने की बात की है। विनिवेश से जो पैसा आएगा वह इस कोष में जाएगा और उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर खर्च करने के अलावा रेलवे में पूंजीगत व्यय के निवेश के लिए किया जाएगा।

विवेक कौल

असली विनिवेश तो तब होगा जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी कंपनियों को बेचेगी

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में 51 फीसद हिस्सेदारी की मौजूदा नीति को बदला जाएगा। अगर सरकार सही मायने में अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचती है तो यह एक अच्छा कदम होगा, लेकिन यदि इस बदलाव का इस्तेमाल भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए करती है तो यह इस बदलाव का गलत इस्तेमाल होगा। जो भी हो, यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री ने श्रम कानून में सुधार की पहल की। यह जरूरी था। अपने यहां केंद्रीय सरकार के स्तर पर करीब 44 श्रम कानून हैं। अगर राज्यों के स्तर के श्रम कानूनों को गिना जाए तो करीब 200 श्रम कानून और हैं। इतने सारे श्रम कानून होने से कारोबारी एक स्तर के बाद और बड़े होने की कोशिश छोड़ देते है। यही वजह है कि विनिर्माण कंपनियों में या तो 50 से कम लोग होते हैं या फिर 200 से अधिक। मोदी सरकार यह चाह रही है कि केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम कोड के एक सेट में डाल दिया जाए। यह एक अच्छा प्रस्ताव है, पर देखना यही है कि ऐसा हो पाता है या नहीं? ध्यान रहे कि 2015 में भी मोदी सरकार ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजदूर संगठनों के दबाव में आगे नहीं बढ़ पाई। देश में रोजगार पैदा करने के लिए श्रम सुधार जरूरी हैं। किसी भी देश में रोजगार तब पैदा होते हैं जब लघु उद्योग बड़े होते हैं।

सरकार ने इस साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया है। पिछले दो सालों में सरकार इन बैंकों में करीब 2.06 लाख करोड़ रुपये डाल चुकी है। आखिर सरकार कब तक इन बैंकों में करदाताओं की कमाई डालती रहेगी? जरूरत तो यह है कि इन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 50 फीसद से कम करने को तैयार हो। इससे बैंक बाजार से पैसा उठा सकेंगे और करदाताओं का पैसा अधिक अहम कार्यों में लगाया जा सकेगा। वित्तमंत्री के पास अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाने का अच्छा मौका था जो उन्होंने लगभग गंवा दिया।

(इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक अर्थशास्त्री एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

देश का विदेशी मुद्रा भंडार

(अरब डॉलर में)

(मार्च अंत तक)

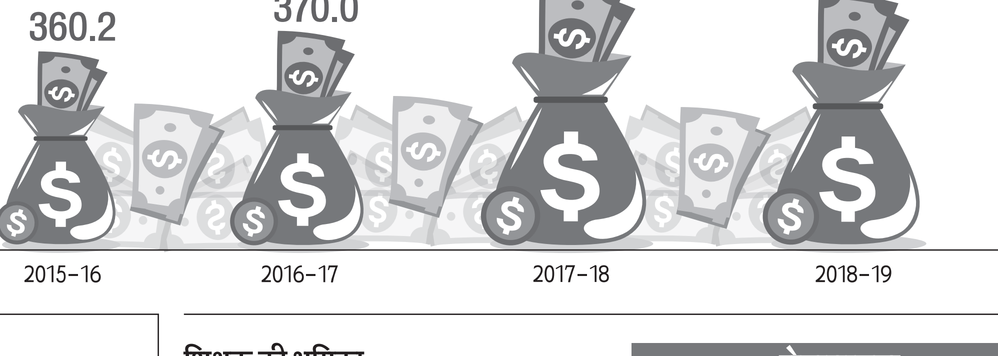

ऊर्जा

मौनव्रत

मनुष्य के ज्ञान, स्वभाव का स्तर उसकी वाणी से पता चलता है। वाणी अपनी मिठास, तर्क, क्षमता एवं भाव संवेदना से दूसरों को प्रभावित नहीं करती, अपितु प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बना लेती है। कुशल वक्ता जनमानस को बदलते हैं और उसे अपने विचारों के अनुकूल धारा में बहा ले जाते हैं। लोक व्यवहार में सफलता-असफलता का बहुत कुछ आधार उसके भाषण-संभाषण स्तर के साथ जुड़ा रहता है। अध्यात्म में वाक् सिद्धि का प्रयोजन मौन व्रत का अभ्यास करने से बनता है। निरंतर बोलने से वाणी की क्षमता क्षीण होती है। अतएव विद्वतजन निरर्थक नहीं बोलते। सोच समझकर सीमित और अर्थपूर्ण शब्द कहते हैं। उनका थोड़ा सा भी बोलना घंटों बकवास करने की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। मौन के विश्रामकाल में इतना अवसर मिल जाता है कि पिछली गंदी आदतों को सुधारा-विचारा जा सके। मौन व्रत के द्वारा भावी कार्यकाल को सुगम बनाया जा सकता है।

मौनकाल में विचारों की शक्ति सीमाबद्ध होती है। इसे इधर-उधर बिखेरने की अपेक्षा यदि वाक् शक्ति पर धार धरने में लगाया जा सके तो वह तीखी तलवार से भी अधिक सशक्त बनती है। मौन की पृष्ठभूमि में जप साधन ठीक प्रकार बन पड़ता है। ध्यान के लिए मौन व्रत अनिवार्य है। किसी दशा-विशेष में प्राणशक्ति को नियोजित करने का अभ्यास करना हो तो उसका प्रथम चरण मौनव्रत ही हो सकता है। बांध खोलने पर जल का प्रचंड प्रवाह उछाल मारता है, यदि उसे सामान्य गति से बहने दिया जाए तो जल धारा सामान्य स्तर की ही बनकर रह जाती है।

विचार के उपरांत वाणी का स्थान है। विचार सूक्ष्म हैं। मौन व्रत से उपासना की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है और उस आधार पर निग्रहित की गई जिह्वा (जीभ) जो कुछ कहती है, वह शुभ सत्य होकर रहता है। जिह्वा के कार्यक्षेत्र लौकिक भी हैं और पारलौकिक भी। लोक व्यवहार में यह सबसे बड़ी क्षमता है। अध्यात्म में सत्संग, विचार-विनिमय जिह्वा से ही संपन्न होते हैं। वाणी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मौन व्रत का ही अवलंबन लेना चाहिए। सप्ताह में एक दिन या दिन में दो-तीन घंटे का मौन व्रत रखना जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।

श्रीमती रमन त्रिपाठी

लाल कपड़े में लिपटा 'स्वदेशी बजट'!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब दो घंटे का बजट भाषण दिया, लेकिन यह आम बजट संसद में पेश होने से पहले ही चर्चा में आ गया। वजह- उस ब्रीफकेस का नदारद रहना जिसे वर्षों से सभी सरकारों के वित्त मंत्री बजट के दिन दिखाते नजर आते थे। जब कभी बात बजट की होती है तो दिमाग में एक लाल रंग का ब्रीफकेस घूमने लगता है। यह वही ब्रीफकेस होता है, जो बजट वाले दिन वित्त मंत्री के हाथों में होता है और जिसमें बजट होता है, लेकिन इस बार उसकी जगह ले ली लाल मखमली कपड़े में लिपटे बजट पेपर्स ने। इसे 'बही खाता' नाम दिया गया है। आजादी के बाद आज तक हमेशा बजट ब्रीफकेस में ही दिखा, लेकिन इस बार बजट को स्वदेशी बनाते हुए उसे पारंपरिक तरीके से लाया गया है। ठीक वैसे, जैसे बेहद पूज्यनीय ग्रंथों को लाया जाता है।

वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा-यह भारतीय परंपरा है और यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है। यह बजट नहीं, बहीखाता है। मोदी सरकार हमेशा से ही स्वदेशी होने की बात कहती है और अब उसे बजट में भी लागू कर दिया गया है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई बदलाव किए गए, जिससे अंग्रेजी तरीके से बजट पेश करने के तरीके बदले गए।

फिर से

सत्ता में आने के बाज आम बजट से जुड़े कई बदलाव मोदी सरकार कर चुकी है और अब बारी है वित्त वर्ष को बदलने की

बजट की तारीख को 28 फरवरी से बदल कर 2017 में 1 फरवरी कर दिया गया। 2000 तक बजट 5 बजे पेश होता था, लेकिन 2001 में वाजपेयी सरकार ने इस परंपरा को बदला। बजट पेश करने का वक्त शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किया। पहले रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इन दोनों को एक में जोड़ दिया गया। अब 2019 में बजट में दिखने वाला ब्रीफकेस भी बदल गया है और उसकी जगह लाल कपड़े में लिपटे बही खाते ने ले ली है। सीतारमण के हाथ में लाल कपड़े में लिपटा बजट देखकर हर कोई थोड़ा हैरान भी था। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह भारतीय परंपरा के अनुसार है। यह दिखाता है कि हम पश्चिमी गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। यह कोई बजट नहीं है, बल्कि बही खाता है। कुछ इसे अच्छा बदलाव बता रहे हैं। इसी बीच पत्रकार रशीद किदवई ने सवाल उठाया है कि वित्त मंत्री का ब्रीफकेस कहा हैं? वित्त मंत्रालय की एक और परंपरा खत्म हो गई? इस पर एक अन्य पत्रकार सुमित अवस्थी ने भी सवाल किया है कि आखिर आप ब्रीफकेस क्यों देखना चाहते हैं? बही खाते में गलत क्या है?

अब बारी वित्त वर्ष बदलने की : बजट से जुड़े कई बदलाव मोदी सरकार कर चुकी है और अब बारी है वित्त वर्ष को बदलने की। अभी तक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जबकि साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। अब मोदी सरकार धीरे-धीरे वित्त वर्ष की अवधि भी बदल कर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करेगी। वैसे भी मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल से ही इस पर विचार हो रहा है और उम्मीद है कि इस कार्यकाल में सरकार यह फैसला भी ले लेगी। वैसे भी, इतने तगड़े जनादेश वाली भाजपा के लिए यह बदलाव करने का इससे अच्छा मौका शायद ही कोई और होगा।

(साभार : आइचौक.इन में अनुज मौर्या)

शिक्षक की भूमिका

बेहतर शिक्षक ही कर सकेंगे कायाकल्प शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने भारत के भविष्य निर्माण में शिक्षक की भूमिका को अहम माना है। निःसंदेह आज देश यदि प्रगति के पथ पर है तो उसमें शिक्षकों के योगदान और समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा एक ऐसा मापदंड है जिससे किसी देश की प्रगति को मापा जा सकता है। शिक्षा को बेहतर करने की परिकल्पना बगैर शिक्षक के तो की ही नहीं जा सकती। शिक्षक को यदि गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए तो निश्चय ही शिक्षक अपना शत प्रतिशत योगदान शिक्षा के स्तर को उठाने में लगाएगा। प्रतिभावान छात्र को उसके छात्र जीवन से ही शिक्षक बनने की प्रेरणा दी जाए तो बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। नई शिक्षा नीति में 2022 तक पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी और शिक्षा मित्र को बंद करने का प्रस्ताव साहसिक जरूर हो सकता है, लेकिन मानवीय नहीं होगा। इसलिए उन्हें हटाने के बजाय शिक्षा का अंग बनाए रखना एवं उनके जीवकोपार्जन के लिए आर्थिक संरक्षण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सर्वजीत आर्या, प्रधानाचार्य, कन्नौज

शहरों में पानी की बर्बादी

जब भी हम अपने घरों में आरओ फिल्टर मशीन चलाते हैं, तो एक लीटर पानी प्राप्त करने के लिए 3 लीटर अच्छी गुणवत्ता वाला पानी बर्बाद करते हैं। 10 लोगों के एक परिवार को अगर 1 दिन में 100 लीटर शुद्ध पेयजल की आवश्यकता हो सकती है तो हर दिन फिल्टर की प्रक्रिया में ढाई सौ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार आरओ मशीन का उपयोग करते हैं। ऐसे में प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी बेकार हो जाता है। जहां एक तरफ आरओ मशीन पानी को स्वच्छ करने का साधन बना, तो दूसरी तरफ पानी को बर्बाद करने का जरिया भी बना। भूजल के घटते स्तर का दोष किसानों पर थोप दिया जा रहा है। ट्यूबवेल के चलने और धान के खेतों में पानी भरे होने के साथ अनुमान लगाया जाता है कि खेतों में उपलब्ध पानी का 70 फीसद खर्च होता है। एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक 8 मिनट में शावर में 65 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। एक आदमी औसतन 15 से 20 मिनट शावर का इस्तेमाल करता है। पानी बचाने के लिए ऐसी आदतें बदलने की आवश्यकता है।

durgesh040796@gmail.com

मेलबाक्स

सभी धर्मों का सम्मान

पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं। नुसरत जहां अपनी बेबाकी व सटीक बोलने के लिए चर्चित हैं। आज हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वह है सभी धर्मों का सम्मान करने की, लेकिन हम आज भी एक दूसरे के धर्म का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नुसरत जहां जैसी सांसद को एक आदर्श मार्गदर्शिका बनकर लोगों में अलख जगाना होगा कि हम सब धर्म व जाति से बाद में हैं, सबसे पहले मानव हैं व मानव बनकर एक दूसरे का सम्मान करें। यही इंसानियत है व इसी में हम सब का कल्याण है।

hemahariupadhyay@gmail.com

मुंबई की बारिश

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसके साथ ही मुंबई नगर निगम देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। इसका सालाना बजट लगभग 800 करोड़ का है। देश में जितना भी टैक्स आता है, उसमें से 32 प्रतिशत मुंबई के लोग ही देते हैं, लेकिन पहली बरसात ने ही मुंबई की गति को रोक दिया है। बीएमसी और वहां की स्थानीय सरकार पूरी तरह फेल नजर आती है। मुंबई में हर साल इस तरह की बारिश होती है और यही नजारा रहता है। जनता इसे झेलने को विवश रहती है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

हम भी रहें सतर्क

दुर्घटना लापरवाही के कारण ही होती है। इसके बावजूद हम अपनी गलती ना मानते हुए दूसरे पर ही आरोप लगाते रहते हैं। सरकार को कोसते हैं, प्रशासन को नकारा बताते हैं। परंतु हकीकत यह है कि हम आपराधिक घटनाओं के बाद भी सतर्क नहीं रहते और हमारी यही लापरवाही दुर्घटनाओं और अपराधों को बढ़ावा देती है। सरकार और प्रशासन तो अपना काम करता है और करेगा भी। परंतु हमें भी सतर्क और जागरूक रहकर अपने देश शहर, घर और परिवार को सुरक्षित रखना होगा।

एकता, डा. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विवि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

300 करोड़ रुपये मिले हैं केंद्रीय बजट में चंद्रावल में नए जल शोधन संयंत्र के लिए। इसका निर्माण जापान की एजेंसी जिका (जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन) की मदद से शुरू किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण होने पर दिल्ली के 22 लाख लोगों को फायदा होगा।

दिल्ली को मिले सिर्फ 325 करोड़ : सिसोदिया

मायूसी ▶ उप मुख्यमंत्री ने कहा– केंद्रीय करों में नहीं बढ़ी हिस्सेदारी, छह हजार करोड़ की मांग की गई थी

पिछले 18 वर्षों से आवंटित हो रही है इतनी ही राशि

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी बढ़ाने की आप सरकार की मांग शुक्रवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में पूरी नहीं हुई। राष्ट्रीय राजधानी को फिर से केवल 325 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले 18 वर्षों से यह राशि इतनी ही आवंटित हो रही है। बजट में दिल्ली सरकार की मांग की अनदेखी की गई है।

सिसोदिया ने कहा कि बजट पूर्व बैठक में दिल्ली के लिए छह हजार करोड़ रुपये की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिल्ली का बजट 2001-02 में 8739 करोड़ रुपये था, जो अब बढकर 60 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के लिए किसी भी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार अपने कर प्राप्ति की राशि में से 12.5 फीसद तीनों निगमों को देती है। अन्य राज्यों के निगमों को फंड दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के निगमों को कोई राशि नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता राशि के रूप में बजट 2019-20 में मात्र 472 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने इस मद में 1500 करोड़ रुपये की मांग की थी। आइजीएसटी मद में दिल्ली सरकार ने 3202 करोड़ की राशि मांगी थी, लेकिन बजट में इस मद में कोई राशि नहीं मिली है।

इस वर्ष दिल्ली को दी जाने वाली राशि 2018-19 के 867.49 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1,112 करोड़ रुपये की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले महीने बुलाई गई बजट पूर्व बैठक में उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के लिए 6,000 करोड़ रुपये की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस शहर को पिछले 18 साल से सिर्फ 325 करोड़ रुपये ही मिलते हैं।

लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आप नेताओं ने यह मुद्दा उठाया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली केंद्र के खजाने में आयकर राजस्व के तौर पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का योगदान करती है। इसके बदले में उसे महज 325 करोड़ ही मिलते हैं। गृह मंत्रालय से दिल्ली को अंतरिम राशि में सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए बढ़ाई गई मुआवजे की राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपये और चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

निराश करने वाला है बजट : केजरीवाल

नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। यह रुटीन बजट है। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि आम बजट से दिल्ली की जनता को निराशा हाथ लगी है। पार्टी से राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता ने कहा कि दिल्ली से हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। आज भी वही हुआ है। उधर आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ट्वीट किया कि वृद्ध महिलाओं और वेतनभोगी वर्ग को मौजूदा बजट से घोर निराशा हुई है।

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, दिखावे से भरा है

नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने ट्वीट कर केंद्र के बजट को निराशाजनक बताया है। दीक्षित ने कहा कि बजट दिखावे से भरा हुआ है और इसमें जनता के लिए कुछ भी नहीं है। यह कोई तथ्यपरक बजट नहीं है। दिल्ली इस देश की राजधानी है, लेकिन लगातार कई बजट से दिल्ली को कुछ नहीं मिल रहा है। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि सरकार जब बजट पेश करती है तो आम जनता को लगना चाहिए कि सरकार ने हमारी तरफ देखा। बजट में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को रोजी व रोजगार मिले।

मनोज तिवारी बोले, हर वर्ग के सपने होंगे साकार

नई दिल्ली : केंद्रीय बजट को प्रदेश भाजपा ने हर वर्ग के सपने को साकार करने वाला बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा की किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सपनों को साकार करने वाले बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं। यह बजट दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। वहीं दिल्ली मेट्रो को गति मिलेगी।

फीकी हुई ज्वेलरी बाजार की चमक

जासं, नई दिल्ली : बजट में आयात शुल्क बढ़ाए जाने से दिल्ली के ज्वेलरी बाजार में निराशा का माहौल है। बजट में आयात शुल्क 10 फीसद से बढ़ाकर 12.5 फीसद कर दिया गया है। इससे सोने के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में कम मांग से जूझ रहे ज्वेलरी उद्योग को और झटका लगा है। ज्वेलर्स के मुताबिक उन्हें बजट से आयात शुल्क में कटौती के साथ ही बाजार को गति देने के लिए कुछ सहूलियत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसका उल्टा हुआ है।

दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण गुप्ता ने कहा कि चुनाव से पहले काफी घोषणाएं की गई थीं, लेकिन बजट उनके विपरित है। ऐसे में ज्वेलर्स में नाराजगी है। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन राम अवतार वर्मा ने कहा कि ज्वेलरी उद्योग पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ऐसे में सरकार से सहारे की जरूरत थी, लेकिन बजट के प्रावधानों से बड़े ज्वैलरों के साथ छोटे ज्वैलर्स की परेशानी बढ़ेगी। दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अंकुर गुप्ता ने कहा कि आयात शुल्क बढ़ने से सोने की तस्करी बढ़ेगी।

एसआइटी जांच की मांग खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मंदिर में तोड़फोड़ मामला

- **हाई कोर्ट ने कहा, मामले को लेकर पुलिस और सरकार गंभीर**
- **याचिका दायर कर एसआइटी से जांच कराने की मांग की गई थी**

चांदनी चौक के लाल कुआं स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ मामले की विशेष जांच दल (एसआइटी) से जांच की मांग को ठुकराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि मामले में तीन एफआइआर दर्ज की जा चुकी हैं और जांच जारी है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि घटना में शामिल होने वाले जिन लोगों की पहचान हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसलर अनिल सोनी और गृह मंत्रालय व पुलिस की तरफ से पेश हुए अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि छह किशोरों को भी पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने के बाद अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पीठ ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र, दिल्ली सरकार व पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में इस मामले में एसआइटी जांच की जरूरत नहीं लगती।

पीठ ने कहा कि जांच की निगरानी की जरूरत नहीं है। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता अलाख आलोक श्रीवास्तव की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि धार्मिक स्थल पर हमले की एसआइटी से जांच कराकर दोषी पर कठोर कारवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। याचिका में कहा गया कि मंदिर पर हमला करने से देशभर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

गौरतलब है कि 29 जून की रात चांदनी चौक के लाल कुंआ में पार्किंग के विवाद के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद एक मंदिर पर लगभग दो सौ लोगों ने पथराव किया था।

पुलिस आयुक्त ने हौज काजी का दौरा कर लिया जायजा

दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने शुक्रवार दोपहर हौज काजी का दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने लालकुआं स्थित उस दुर्गा मंदिर का भी मुआयना किया, जहां बीते दिनों उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। आयुक्त ने करीब एक घंटे तक वहां रहकर आसपास के लोगों और तैनात सुरक्षाकर्मियों से बातचीत की। जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद इलाके में अब भले ही शांति कायम हो गई है लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी इलाके में दिल्ली पुलिस व पैरा मिलिट्री के करीब 500 जवान तैनात हैं।

गुरुग्राम हत्याकांड

मौसी के घर गए बेटे को बुलाने के लिए रोज फोन करते थे श्रीप्रकाश

महावीर यादव, बादशाहपुर (गुरुग्राम) : अपने परिवार को मौत के घाट उतारकर आत्महत्या करने वाले डॉ. श्रीप्रकाश मौसी के घर गए बेटे आदित्य को रोजाना फोन कर घर आने के लिए कहते थे। आदित्य गर्मी की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर दिल्ली गया हुआ था। पापा के बार-बार कहने के बाद वह घटना से एक दिन पहले ही घर आया था। डॉ. श्रीप्रकाश की साली सीमा दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती हैं। दोनों परिवारों का आपस में काफी आना-जाना था। सोमवार को घटना की सूचना मिलने के बाद रिश्तेदारों में सीमा सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची थीं। दोनों परिवारों की फोन पर भी काफी बातें होती थीं। सीमा ने बताया था कि घटना वाली रात करीब 11:20 तक अदिति से उनकी फोन पर चेटिंग हो रही थी। उसके बाद नींद आने पर अदिति ने सोने के लिए कहा था।

आदित्य सेक्टर-49 में डीएवी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता था। गर्मी की छुट्टियों में वह करीब 10 दिन पहले अपनी मौसी के घर चला गया था। डॉ. श्रीप्रकाश सिंह भी रोजाना फोन कर बेटे आदित्य से बातचीत करते थे। वह उसको घर आने के लिए कहते थे। एक जुलाई से स्कूल खुलने थे, इसलिए वह एक दिन पहले ही आदित्य मौसी के घर से लौट आया था।

घटना की रात परिवार ने नहीं खाया था खाना : घटना वाली रात परिवार के किसी भी सदस्य ने खाना नहीं खाया था। करीब 7 बजे एक होटल से खाना मंगवाया गया था। वह खाना भी सुबह वैसा ही पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी के पेट खाली थे। किसी ने भी खाना नहीं खाया हुआ था।

पुलिस ने वैज्ञानिक डॉ. श्रीप्रकाश सिंह के परिवार के दुखद अंत की गुत्थी सुलझाने के लिए शुक्रवार को फिर से उनके घर की तलाशी ली। इस दौरान डॉ. श्रीप्रकाश के कई रिश्तेदार भी मौजूद थे। शुक्रवार दोपहर दो बजे के करीब उप्पल साउथएंड के मकान नंबर एस-299 पर एसीपी सदर अमन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची। पुलिस के साथ श्रीप्रकाश की साली सीमा, उनके पति, दो बहनों और बहनोई के अलावा कुछ पारिवारिक मित्र भी थे। एसीपी सदर अमन यादव के साथ सेक्टर-50 थाना के प्रभारी शाहिद हसन, एएसआइ बलजीत सिंह, एएसआइ चंदगीराम व पुलिस टीम थी। पुलिस ने मकान में प्रवेश करने के दौरान पूरी वीडियोग्राफी कराई। घर के अंदर सभी कमरों की तलाशी ली गई। अंदर रखी अलमारी के ताले आदि तोड़कर उसमें रखे दस्तावेज आदि चेक किए।पुलिस ने डॉ. श्रीप्रकाश के घर से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अभी सभी मोबाइल बंद हैं। पुलिस उन मोबाइल फोन को चालू कर उनका डाटा भी खंगालेगी।

आपके बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

दिल्ली सचिवालय में उच्च शिक्षा के लिए फीस सहायता योजना के अंतर्गत आयोजित समारोह में एक छात्रा को चेक देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ध्रुव कुमार

सर, मेरे पापा हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं। मम्मी जैसे-तैसे कर परिवार चलाकर हमें पढ़ाती हैं। घर में पैसे नहीं थे। मम्मी ने 50 हजार रुपये जुटाए और 50 हजार रुपये नाना से उधार लिए और बीटेक में मेरा दाखिला कराया। मुझे लग रहा था कि पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन इसी बीच मेरे टीचर ने बताया कि सरकार ने स्कॉलरशिप निकाली है, बेटा तुम अप्लाई कर दो। मैंने आवेदन किया, मुझे स्कॉलरशिप का मैसेज आया तो मम्मी बहुत खुश हुईं। रिया ने जब रुंधे गले से दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भावुक हो गए। छात्रा की बात सुनकर केजरीवाल ने कहा कि अब ऐसा किसी के साथ नहीं होने दूंगा। दिल्ली में हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि दिल्ली में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से अच्छी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। दिल्ली के हर माता-पिता को भरोसा दिलाता हूं कि आपके बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। आप पैसे की बिल्कुल चिंता न करें।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के लिए दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम में कई बच्चों ने आर्थिक तंगी की समस्याएं बताईं। केजरीवाल ने उनसे कहा कि हमें आप सब से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। उच्च शिक्षा के लिए आपकी हिम्मत बनी रहनी चाहिए। दिल्ली सरकार आपके साथ है। पैसे के अभाव में दिल्ली में जन्मे एक भी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकने दी जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली का कोई बच्चा पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। केजरीवाल सरकार भविष्य में जरूरत पड़ने पर उच्च शिक्षा की स्कॉलरशिप 100 करोड़ रुपये तक भी करेगी। उच्च शिक्षा की दिशा में हमने काफी काम किए हैं। पिछले साढ़े चार साल के भीतर हमने कई कॉलेजों में सीटें बढ़ाई हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि 12वीं में 60 फीसद अंक पाने वाले बच्चों को भी कॉलेज में एडमिशन मिले। ये हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। आइआइटी और डीटीयू में सीटों की संख्या दोगुनी हो चुकी हैं। डीटीयू का नया कैंपस पूर्वी दिल्ली में खुला है। आंबेडकर यूनिवर्सिटी के दो नए कैंपस खुले हैं। नया बीएड कॉलेज और दो नए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। अब तक दिल्ली सरकार ने 16 नए कॉलेज खोले हैं।

पूरे होंगे सपने : स्कॉलरशिप पाने वाली शीतल ने कहा कि आर्थिक अभाव में उच्च शिक्षा पाने का सपना टूट चुका था, लेकिन स्कॉलरशिप की मदद से मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। एमसीए की पढ़ाई कर रहीं आकांक्षा ने कहा कि दिल्ली सरकार से मिली स्कॉलरशिप की वजह मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाऊंगी। मेरे पिता जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पढ़ाई के लिए फीस दे पाते।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब

सिख विरोधी दंगा मामला

- **पांच-पांच साल की सजा पाए 33 दोषियों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील**

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में 33 दोषियों की याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 23 जुलाई तक जवाब मांगा है। दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर 2018 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें पांच-पांच साल के कारावास की सजा दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की थी। दोषियों को 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दंगा करने, मकानों को जलाने और कर्फ्यू को तोड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा दी है। अधिवक्ता विष्णु जैन के जरिये दायर याचिका में दोषियों ने कई वजहों से खुद को बरी किए जाने की प्रार्थना की है। इस सिलसिले में 30 अप्रैल को सुबूत के अभाव में छोड़े गए सात सह अभियुक्तों का उदाहरण दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अभियोजन पक्ष के आरोपों और उनकी जांच पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनके खिलाफ भी आरोपों की बाबत कोई सुबूत नहीं है। इसलिए उन्हें भी बरी किया जाए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दंगा, आगजनी करने और कर्फ्यू तोड़ने के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 89 लोगों में से 70 की पांच-पांच साल के कारावास की सजा बनाए रखी थी। बाकी 19 में से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी, जबकि हाई कोर्ट ने तीन दोषियों की अपील इस आधार पर खारिज कर दी थी क्योंकि वे लापता थे। 1984 में हुए दंगों में देश भर में करीब तीन हजार सिख मारे गए थे जिनमें से 2,100 की संख्या केवल दिल्ली के लोगों की थी।

प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने बेटी को मारी गोली, मौत

संवाद सहयोगी, जेवर

- **युवती के पति ने दस लोगों पर लगाया षड्यंत्र के तहत हत्या करने का आरोप**
- **मामला दर्ज, पुलिस की मौजूदगी में ससुराल में हुआ अंतिम संस्कार**

जेवर कोतवाली क्षेत्र के दस्तमपुर गांव में गुरुवार रात झूठी शान की खातिर बेटी की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज परिजन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। युवती के पति ने ससुराल पक्ष के आठ लोगों पर षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए जेवर कोतवाली में शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की मौजूदगी में युवती का अंतिम संस्कार उसकी ससुराल में किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जेवर कोतवाली प्रभारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि दस्तमपुर गांव निवासी देवीचरण की 28 वर्षीय बेटी निशा ने पिछले वर्ष 18 जून को परिजन को बिना बताए पड़ोस के गांव धनसिया निवासी सजातीय युवक से प्रेम विवाह किया था। इसकी भनक युवती के परिजन को नहीं लगी। शादी के बाद से निशा मायके में रह रही थी। कुछ समय पहले निशा ने अपनी शादी के बारे में परिजन को बता दिया। इसके बाद से मां-बाप और भाई उससे नाराज चल रहे थे। आरोप है कि परिजन ने कुछ माह बाद उसकी शादी सामाजिक तौर पर प्रेमी से कराने का भरोसा देकर अपने विश्वास में ले लिया। इसी बीच मायके वालों ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। आरोप है कि षड्यंत्र के तहत गुरुवार रात जब निशा घर की छत पर सो रही थी, तभी उसके भाई संदीप, सुशील, चाचा राजेश, मां ऊषा देवी, जीजा ऋषि व चाची पुष्पा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

निशा के पति की शिकायत पर उपरोक्त सभी आरोपितों के खिलाफ हत्या और देवीचरण, चाचा सत्यप्रकाश, चाची सरोज व पड़ोसी रतनपाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया है। जेवर के पुलिस क्षेत्राधिकारी शरद चंद शर्मा का कहना है कि घटना के बाद से सभी आरोपित फरार हो गए। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

परिवार वालों को वाट्सएप मैसेज भेज युवक ने की आत्महत्या

जासं, नई दिल्ली : आइटीओ पुल से कूदकर 26 वर्षीय डिलीवरी ब्वॉय ने जान दे दी। उसकी पहचान हर्ष खंडेवाल के रूप में हुई है। मरने से पूर्व उसने अपने परिजनों को वाट्सएप मैसेज से घटना की जानकारी दी थी। उसने मैसेज में लिखा था कि मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना। मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी स्कूटी, मोबाइल व पर्स आइटीओ पुल पर मिलेंगे। मेरा शव पुल के नीचे यमुना से बरामद हो जाएगा। सूचना के बाद परिवार वाले बदहवास मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। हालांकि उसने आत्महत्या क्यों की, इसका स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हर्ष के परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का शक जताया है।

पुलिस के मुताबिक हर्ष परिवार के साथ पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में रहता था। वह ऑनलाइन सामान बेचने वाली एक कंपनी में डिलीवरी ब्वॉय था। 30 जून की शाम हर्ष परिजनों से दोस्त की पत्नी के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए मुरथल जाने की बात कहकर निकला था। उसने कहा था कि दूसरे दिन सुबह घर आ जाएगा। इस बीच एक जुलाई की सुबह माता-पिता के मोबाइल पर हर्ष के आत्महत्या संबंधी वाट्सएप मैसेज आया। मैसेज के बाद परिजन आइटीओ पुल के पास पहुंचे तो उन्हें हर्ष की स्कूटी, पर्स व मोबाइल इत्यादि बरामद बरामद हो गए।

गाजियाबाद में तीन बेटियों समेत पत्नी की हत्या कर युवक ने की खुदकशी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

प्रदीप की तीनों बेटियां।

पत्नी संगीता।

प्रदीप कुमार (फाइल फोटो)

मौके से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। सुसाइड नोट में बच्चों को जहर देने की बात सामने आई है। फेरू की ओर से प्रदीप के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आत्महत्या करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। **–सुधीर कुमार सिंह, एसएसपी**

गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति ने पत्नी व तीन बेटियों की हत्या कर खुदकशी कर ली। पत्नी के सिर पर हथौड़े से कई वार किए और बेटियों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। उल्टी होने से कहीं बच न जाएं, इस आशंका के चलते चार इंच वाला काला टेप तीनों बेटियों के और अपने चेहरे पर लपेट लिया। मौके पर पहुंची पुलिस गेट तोड़कर अंदर घुसी तो पत्नी की सांसें चल रही थीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से छह पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया है।

गाजियाबाद के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रदीप कुमार पत्नी संगीता और तीन बेटियों मनस्वी, यशस्वी व ओजस्वी के साथ न्यू शताब्दीपुरम रह रहा था। पिता फेरू, मां शीला व बहन रीना भी साथ रह रहे थे। संगीता कमला नेहरूनगर स्थित एम्स के एनडीडीटीसी (नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर) में स्टाफ नर्स थीं। प्रदीप के पिता फेरू वाल्मीकि मूलरूप से मेरठ के मोहिउद्दीनपुर के अगैहड़ा गांव के रहने वाले हैं और नेवी में मास्टर चीफ पेटी अफसर के पद से सेवानिवृत हैं। बताया जा रहा है कि प्रदीप डेढ़ साल से बेरोजगार था। रीना ने बताया कि शुक्रवार पांच बजे वह उठी तो प्रदीप कमरे के बाहर सोफे पर बैठा हुआ था।

उन्होंने प्रदीप से पूछा कि कैसे बैठा है? तो उसने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वह चली गई। कुछ ही देर बाद संगीता के कमरे से चीखने-चिल्लाने की आवाज आने पर परिजन वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। लोगों ने वेंटिलेशन वाली जगह से झांक कर देखा तो संगीता जमीन पर पड़ी हुई थी, जबकि प्रदीप व तीनों बेटियां बेड पर थे। पिता फेरू के मुताबिक, प्रदीप नौकरी छूट जाने के बाद नशे का आदी हो गया था। वह संगीता से शराब के लिए पैसे मांगता था। इसको लेकर दोनों में झगड़ा होता था। प्रदीप की पैंट की जेब से पुलिस को छोटी कॉपी मिली, जिसके छह पन्नों पर उसने सुसाइड नोट लिखा था।

डीयू में दाखिला

दूसरे कटऑफ के तहत दाखिले का आज आखिरी दिन

कई कॉलेजों में विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश, तीसरे कटऑफ में नौ से 11 जुलाई तक दाखिले होंगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में दाखिला लेने पहुंची छात्र-छात्राएं। ध्रुव कुमार

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉर्थ कैंपस व साउथ कैंपस के कई कॉलेजों में विद्यार्थियों ने दूसरे कटऑफ के तहत स्नातक में दाखिला लिया। विद्यार्थी इस बात से खुश नजर आए कि वे मनपसंद कॉलेज से पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने पहले कटऑफ के आधार पर लिए गए दाखिले को रद कराया और दूसरे कटऑफ में किरोड़ीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज, दौलत राम, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमेन में दाखिला लिया।

किरोड़ीमल कॉलेज में दूसरे कटऑफ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कई विद्यार्थी दाखिला लेने पहुंचे। इसमें दूसरा कटऑफ 98 फीसद निर्धारित हुआ है। हंसराज कॉलेज में भी कई छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। कैंपस के बाहर के कॉलेजों में विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं। दूसरे कटऑफ के तहत दूसरे दिन करीब तीन हजार छात्रों ने दाखिला लिया। इस कटऑफ के आधार पर शनिवार तक ही दाखिले लिए जाएंगे। इसके बाद डीयू तीसरा कटऑफ जारी करेगा, जिसके तहत नौ से 11 जुलाई तक दाखिले होंगे।

डीयू के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन एवं दाखिला समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने शुक्रवार को दूसरे कटऑफ के दूसरे दिन तक हुए दाखिले की सूची देर रात जारी की। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 31,750 छात्रों ने डीयू के सभी कॉलेजों में स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले लिए हैं। डीयू में स्नातक में 62 हजार सीटें हैं। शुक्रवार तक 2,693 छात्रों ने विभिन्न कॉलेजों में अपने दाखिले रद कराए। दूसरे शिक्षण संस्थान में दाखिला हो जाने पर 580 छात्रों ने अपना दाखिला वापस ले लिया है।

ईसीए कोटे के ट्रायल का अंतिम राउंड नौ जुलाई से

जासं, नई दिल्ली : डीयू ने स्नातक में दाखिले के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी (ईसीए) कोटे के तहत होने वाले ट्रायल के अंतिम राउंड की सूची दाखिला पोर्टल पर अपलोड कर दी है। रचनात्मक लेखन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य समेत कई गतिविधियों के अंतिम राउंड के ट्रायल नौ जुलाई से शुरू होंगे। ट्रायल 13 जुलाई तक चलेंगे। पहले दिए गए ट्रायल की जानकारी छात्र दाखिला पोर्टल से ले सकते हैं।

डीयू की शिकायत निवारण समिति के सदस्य एसोसिएट प्रोफेसर विजय वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 600 से ज्यादा छात्र दाखिले से जुड़ी समस्या को लेकर कांफ्रेंस सेंटर में समिति के रूम में पहुंचे। फोन पर भी छात्रों ने सवाल पूछे। कई छात्र यह चाहते थे कि उन्हें दाखिला रद कराने के अधिक अवसर मिलें, लेकिन यह नियम इस वर्ष नहीं है। इस वर्ष हर कटऑफ में छात्र सिर्फ एक बार ही दाखिला रद करा सकता है। डीयू में पढ़ा रहे शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ के लिए तीन-तीन सीटें सभी कॉलेजों में निर्धारित की गई हैं। इसे वार्ड कोटा कहते हैं।

हाई कोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज प्रशासन से मांगा जवाब

जासं, नई दिल्ली : डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ईसाई छात्रों की आरक्षित श्रेणियों के कटऑफ में विसंगतियां होने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा है। गैर ईसाई छात्रों की आरक्षित श्रेणियों के कटऑफ में भी विसंगति का आरोप है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कॉलेज प्रशासन से 11 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

प्रोफेसर नंदिता नारायण ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कॉलेज ने 26 जून को अनुसूचित जनजाति के ईसाई छात्र व अन्य धर्म के आरक्षित वर्ग सहित दिव्यांग छात्रों का स्नातक में दाखिले के लिए कटऑफ गलत तरीके से ज्यादा रखा है। डीयू ने कुछ पाठ्यक्रमों के कटऑफ को घटाते हुए दो जुलाई को शुद्धिपत्र जारी किया, लेकिन इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं की गई। यह जानकारी नामांकन कराने वाले कई छात्रों को नहीं मिली। ऐसे में कॉलेज को नए सिरे से कटऑफ तैयार कर इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि डीयू कटऑफ की विसंगतियों को दूर करे और सही संख्या में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के ईसाई व गैर ईसाई छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा लेने के निर्देश कॉलेज प्रशासन को दे।

छात्रसंघ अध्यक्ष को जेएनयू प्रशासन ने किया निलंबित

जासं, नई दिल्ली : जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष एन साईं बालाजी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ कई अन्य छात्रों को भी निलंबित किया गया है। बालाजी जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से एमफिल कर रहे हैं।

प्रशासन ने उन्हें विश्वविद्यालय की मूल्यांकन ब्रांच से संपर्क करने के लिए कहा है और यह भी जानकारी दी है कि वह इस वर्ष के सेमेस्टर में खुद को रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। उन्हें जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर कार्यालय की तरफ से अकादमिक स्तर पर निलंबित किया गया है। बालाजी ने कहा कि मैंने और अन्य छात्रों ने जेएनयू की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा पर सवाल उठाए। कई अन्य मामलों पर प्रशासन से सवाल पूछे इसलिए प्रशासन की ओर से सजा दी जा रही है। जेएनयू प्रशासन ने छात्रसंघ अध्यक्ष के आरोपों को सही नहीं बताया है। प्रशासन के मुताबिक बालाजी को निलंबित किया गया है, लेकिन यह अकादमिक स्तर पर लिया गया फैसला है।

1.31 अरब रुपये का घोटाला किया गया है बिहार के बोधगया में होटल निर्माण के नाम पर। सीबीआइ ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कुल 13 आरोपितों को नामजद किया है। प्रारंभिक जांच में पहले पटना के बोरिंग रोड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी करने का मामला उजागर हुआ है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 6 जुलाई 2019

गर्मी से मिली निजात ▶ करीब एक हफ्ते की देरी देश की राजधानी में पहुंचा मानसून

मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली में दी राहत, उत्तराखंड में अतिवृष्टि की चेतावनी

जेएनएन, नई दिल्ली

शुक्रवार को दिल्ली के कई हिस्सों मानसून की पहली बारिश हुई। कई जगह अच्छी बारिश हुई। इस बारिश से मौसम भी सुहाना रहा और दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 34.2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मानसून राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंच गया। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार मानसून आने में देरी हो चुकी है। निजी मौसम वेबसाइट स्काईमेट के मुताबिक शनिवार को गरज बढ़ने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्से, उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों के अलावा उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों के साथ ही कुछ अन्य हिस्सों में आगे बढ़ा है। बता दें कि सामान्य तौर पर मानसून 29 जून को दिल्ली पहुंचता है, मगर इस बार इसमें एक सप्ताह की देरी हुई है।

बारिश के कारण दक्षिण दिल्ली की कई सड़कों में पानी भर गया। एएनआइ

हिमाचल: हिमाचल के सभी क्षेत्रों में मानसून पहुंचने के साथ तापमान लुढ़क गया। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के चार जिलों मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। रविवार को भी कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा व मंडी में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट गया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई स्थानों में वर्षा हुई।

उत्तराखंड : उत्तराखंड में शुक्रवार से अगले तीन दिनों तक मानसून की भारी बारिश परीक्षा लेगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के आठ जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक बारिश सुबह के समय नैनीताल में हुई सुबह नैनीताल में 28.4 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। मूसलाधार बारिश के दौरान सैलानी होटल के कमरों में ही रहे। पिथौरागढ़-टनकपुर मार्ग सुबह के समय छह घंटे अवरुद्ध रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार से सोमवार तक करीब तीन दिन राज्य के विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, टिहरी पौड़ी, नैतीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ एवं उधमसिंह नगर जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना है।

पश्चिम बंगाल : कोलकाता में छिटपुट बारिश के बीच उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। शुक्रवार को कोलकाता में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

मध्य प्रदेश : मानसून शुक्रवार को पूरे मध्य प्रदेश में छा गया। अभी तक प्रदेश में सामान्य से सात प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। यहां अधिकांश स्थानों पर बरसात हुई। शनिवार को ग्वालियर, सागर संभाग में कहीं-कहीं भारी बरसात होने की भी संभावना है।

जम्मू कश्मीर : अब मानसून के जम्मू-कश्मीर में पहुंचने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गुरुवार को हुई बारिश के बाद शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में तापमान सामान्य स्तर पर पहुंच गया। कश्मीर में भी मौसम में सुधार हुआ है। अधिकतर क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहा।

झारखंड : झारखंड के कई जिलों में भी रिमझिम बारिश हुई। रांची का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा।

कश्मीर में हिज्ब का एक आतंकी ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी समीर अहमद को मार गिराया। जबकि उसके दो अन्य साथी बच निकले। मौके से हथियारों के अलावा अन्य साजो सामान भी बरामद किया गया है। इसी बीच, आतंकी समर्थक तत्वों और सुरक्षाबलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में चार लोग घायल हो गए। प्रशासन ने अफवाहों पर काबू पाने के लिए पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है।

शोपियां से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को अपने तंत्र से पता चला कि आतंकियों के दल ने इमाम साहब इलाके में ठिकाना बनाया हुआ है। पुलिस ने सेना की 44 आरआर के जवानों के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। सुबह चार बजे सुरक्षाबलों ने घेराबंदी करते हुए तलाशी शुरू की। जवान जब नारवनी में एक बाग के पास पहुंचे तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। बाग में आतंकी ठिकाना था। जानकारी के अनुसार एक आतंकी ने जवानों को मुठभेड़ में उलझाए रखा। जबकि इस दौरान उसके दो साथी मौके से भाग निकले। सुबह करीब सात बजे मुठभेड़ शुरू हुई मुठभेड़ करीब दो घंटे चली।

समीर छह माह पहले बना था आतंकी : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समीर पहले अल-बदर मुजाहिदीन का आतंकी था। करीब छह माह पहले ही वह हिज्ब में शामिल हुआ था। उसके पास से एक एसॉल्ट राइफल, एक मैगजीन, 13 कारतूस, एक मोबाइल फोन मिला है। उसके ठिकाने से कुछ डायरियां, बैटरी चार्जर, बर्तन, कंबल, खाने-पीने का सामान भी मिला है।

तोड़ दिया गया वह मकान, जिसके लिए मप्र में हुआ था बल्ला कांड

मध्य प्रदेश के इंदौर में वह मकान शुक्रवार को तोड़ दिया गया, जिसके लिए भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश ने निगम अधिकारियों की बल्ले से पिटाई की थी। नईदुनिया

नईदुनिया, इंदौर/भोपाल: मध्य प्रदेश के इंदौर में वह मकान तोड़ दिया गया है, जिसे बचाने के लिए भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश ने नगर निगम के अधिकारियों की पिटाई कर दी थी।

नगर निगम की रिमूवल टीम के 150 लोगों का अमला सुबह 10.15 बजे मौके पर पहुंचा। डेढ़ घंटे में मकान ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि 26 जून को इस मकान पर कार्रवाई के दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा क्रिकेट के बल्ले से निगम अफसरों को पीटने के बाद मामला गर्मा गया था। यह मामला इतना सुर्खियों में रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देनी पड़ी थी। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने पार्टी को सख्त संदेश देते हुए कहा था कि बेटा किसी का भी हो, उसकी मनमानी नहीं चलेगी।

माफीनामा से निपट सकता है बल्लाकांड : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद 'बल्ला कांड' में भाजपा ने आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया पर अब आगे की कार्रवाई के लिए हाईकमान के इशारे का इंतजार है। पार्टी नेताओं की मानें तो सारा मामला माफीनामा के साथ निपटाया जा सकता है। पार्टी नेताओं ने जो लाइन तैयार की है, उसके मुताबिक नया विधायक होने के साथ ही गलती स्वीकार कर माफी मांग लेने के बाद प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है।

अब निगम की कार्रवाई का भाजपा के पूर्व विधायक ने किया विरोध: भोपाल के एमपी नगर जोन वन में अवैध ठेले और गुमटियों को हटाने के दौरान भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने विरोध किया।

न्यूज गैलरी

उत्तर प्रदेश में पहले आइजी साइबर क्राइम की तैनाती

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने और इन मामलों की जांच की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन ने पहले आइजी क्राइम की तैनाती कर दी है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आये 1995 बैच के आइपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह को आइजी साइबर क्राइम बनाया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने मेरठ व लखनऊ जोन के अलावा अन्य सभी छह जोन में भी एक-एक साइबर थाना खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सूबे में साइबर क्राइम के लिए अलग तकनीकी कैडर गठित किये जाने पर भी मंथन चल रहा है। आइजी साइबर क्राइम लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय में बैठेंगे। साइबर क्राइम विंग को अब एसटीएफ से अलग कर दिया गया है। (राब्यू)

आधार अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब

नई दिल्ली : आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश-2019 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) से भी जवाब तलब किया है क्योंकि याचिका में आधार (आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का मूल्य निर्धारण) नियम, 2019 को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2019 का अध्यादेश और नियम संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिका के मुताबिक, उक्त अध्यादेश ने निजी पक्षों को आधार के पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) में पिछले दरवाजे से घुसपैठ करने की अनुमति दे दी है जिससे सरकार और निजी पक्ष नागरिकों की निगरानी में सक्षम हो गए हैं।

नरेश गोयल की याचिका पर सुनवाई से हटे जज

नई दिल्ली : विदेश यात्रा से रोकने के लिए जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के खिलाफ जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की ओर से दायर चुनौती याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने खुद को अलग कर लिया। अब इस पर कोई अन्य पीठ सुनवाई करेगी। इसे 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले गंभीर धोखाधड़ी जांच विभाग ने गोयल के खिलाफ एलओसी जारी किया था। (जासं)

बंगाल में एक लाख रुपये से अधिक हुआ मुख्यमंत्री का वेतन

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। वेतन में हुई नई बढ़ोतरी के बाद जहां मुख्यमंत्री का वेतन एक लाख रुपये के पार पहुंच गया है, वहीं मंत्री व विधायक भी अधिक पीछे नहीं हैं। दैनिक वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है।

अब सीएम का वेतन 90 हजार से बढ़कर 1,17,001 हो गया है तो वहीं, कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 90 हजार से बढ़ कर 1,12,000 हो गया है। राज्य मंत्रियों व विधायकों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में शामिल मंत्रियों का दैनिक वेतन प्रति दिन दो हजार से बढ़ा कर तीन हजार कर दिया गया है, जबकि विधायकों का दैनिक वेतन 1500 से बढ़ा कर 2000 कर दिया गया है। बेसिक पे में भी परिवर्तन किया गया है। सीएम का बेसिक वेतन अब 27,001 रुपये किया गया है, जबकि कैबिनेट मंत्रियों का 22,000 और राज्य मंत्रियों का 21,900 जबकि विधायकों का बेसिक 21,870 रुपये कर दिया गया है।

मप्र में ओबीसी आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से संशोधन विधेयक लाने के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि अध्यादेश के जरिये इस प्रावधान को प्रदेश में लागू किया जा चुका है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि खुली भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले राजपत्रित / कार्यपालिक पदों के लिए आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 को 40 साल कर दिया है। प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, नगर सैनिक, निशक्तजन और महिलाओं को पांच साल की छूट मिलेगी। इस निर्णय पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

रामचरित मानस पढ़ने पर मुस्लिम को उसी संप्रदाय के लोगों ने पीटा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : रामचरित मानस पढ़ने पर मुस्लिम श्रद्धालु को पीटने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अलीगढ़ में गुरुवार को घर में रामचरित मानस पढ़ रहे मुस्लिम श्रद्धालु को उन्हीं के समुदाय के लोगों ने पीटा और हरमोनियम भी तोड़ दिया था। आरोपित धर्मग्रंथ (रामचरित मानस) भी उठा ले गए और जान से मारने की धमकी भी दी।

अलीगढ़ के महफूज नगर निवासी दिलशेर एक मीट फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं। वह गुरुवार सुबह घर में रामचरित मानस का पाठ कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान समीर व जाकिर समेत कुछ युवक घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। दिलशेर ने पुलिस से मामले की शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने समीर व जाकिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य हमलावरों की पुलिस तलाश कर रही है। दिलशेर रोज सुबह नहाने के बाद रामचरित मानस का पाठ करना नहीं भूलते। तमाम चौपाइयां उन्हें कंठस्थ हैं। वह गीता भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, '1979 से रामायण पाठ कर रहा हूं। इससे मेरे मन को सुकून मिलता है। पर कुछ लोग मुझे धमकाते रहते हैं। हर वक्त जान को खतरा बना रहता है।'

नागेश्वर राव की सीबीआइ से छुट्टी, डीजी फायर सर्विस बने

- ओडिशा कैडर के 1986 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं राव
- मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के जांच अधिकारी को बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र/आइएएनएस: एम नागेश्वर राव को सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक पद से हटाकर डीजी फायर सर्विस, नागरिक रक्षा और होम गार्ड नियुक्त किया गया है। पहले यह पद सीबीआइ के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को दिया गया था लेकिन उन्होंने चार्ज संभालने से इन्कार करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था।

ओडिशा कैडर के 1986 बैच के आइपीएस अधिकारी राव दो बार सीबीआइ के अंतरिम निदेशक का पद भी संभाल चुके थे। बाद में ऋषि कुमार शुक्ल को इस साल फरवरी में सीबीआइ का निदेशक नियुक्त किया गया था।

सरकार ने आपसी लड़ाई के बाद सीबीआइ के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था, इसके बाद नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया था।

आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीबीआइ ने अस्थाना के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। नागेश्वर राव ने भी सीबीआइ का अंतरिम निदेशक बनते ही 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इनमें 2जी घोटाले की जांच करने वाले अधिकारी विवेक प्रियदर्शी भी शामिल थे।

नागेश्वर राव ने बिहार के सनसनीखेज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले की जांच कर रहे एके शर्मा का भी तबादला कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा था कि जांच अधिकारी शर्मा का तबादला क्यों किया गया? शीर्ष अदालत ने नागेश्वर राव को तलब भी किया था और उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया था।

बाद में नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जानबूझ कर अदालत की अवमानना नहीं की थी। अब उन्हें सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक पद से हटाकर डीजी फायर सर्विस, नागरिक रक्षा और होम गार्ड नियुक्त किया गया है।

चुनाव में अधिक खर्च से बढ़ीं सनी देयोल की मुश्किलें

सुनील थानेवालिया, गुरदासपुर: लोकसभा चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च के मामले में अभिनेता व भाजपा सांसद सनी देयोल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला स्तरीय निगरान कमेटी की जांच में सामने आया है कि उन्होंने साढ़े आठ लाख अधिक खर्च किए। कमेटी ने रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी है।

लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए 70 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित है। बतौर भाजपा प्रत्याशी सनी देयोल ने चुनाव प्रचार में इससे आठ लाख 51 हजार रुपये अधिक खर्च किए हैं। प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आया था कि उन्होंने निर्धारित सीमा से 18 लाख रुपये अधिक खर्च किए हैं। सनी के वकील ने इस पर सवाल उठाए तो जिला स्तरीय जांच कमेटी ने दोबारा चुनाव खर्च का मिलान किया है। कमेटी ने सनी देयाल के साथ बैठक भी की थी। कमेटी ने जांच के बाद खर्च में शामिल नौ लाख 76 हजार रुपये खारिज कर दिए। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि चुनाव आयोग को सनी की सदस्यता रद कर नियमों की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. करुणा राजू ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है।

यमुना का 3.45 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल होगा संरक्षित

गंगा नदी की तर्ज पर शुरू किए जाएंगे यमुना व उसकी सहायक नदियों में संरक्षण संबंधी कार्य

जागरण संवाददाता, देहरादून

- एफआरआइ को मिला डीपीआर बनाने का जिम्मा, सुझाव को जुटे तमाम विभागों के प्रतिनिधि

उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी के बाद अब यमुना के संरक्षण की दिशा में भी वृहद स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए यमुना नदी के संरक्षण को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की जिम्मेदारी मिली है। एफआरआइ ने भी इस दिशा में प्रयास तेज करते हुए पहली एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। तमाम विशेषज्ञ संस्थानों ने इसका हिस्सा बनकर डीपीआर तैयार करने को लेकर सुझाव दिए।

शुक्रवार को संस्थान सभागार में आयोजित बैठक में एफआरआइ के निदेशक एएस रावत ने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यमुना नदी की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। मार्च 2020 तक डीपीआर तैयार कर संस्थान के मुख्यालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) को सौंपी जानी है। यहां से डीपीआर को केंद्र सरकार के सुपुर्द किया जाएगा। यमुना नदी बेसिन के कुल 3.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए यह डीपीआर तैयार की जा रही है। खासकर संरक्षण को लेकर वानिकी के माध्यम से उपाय तैयार किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा नदी के संरक्षण की डीपीआर भी एफआरआइ ने तैयार की थी और इसके आधार पर काम भी शुरू किए जा चुके हैं। वहीं, परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि संरक्षण का कार्य यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में भी किया जाएगा। इसके तहत सात राज्यों में काम किया जाना है और सभी जगह इस तरह की परामर्श बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि यमुना व उसकी सहायक नदियों में किस तरह दबाव बढ़ने से क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। बैठक में उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक मोनीष मलिक, आइसीएफआरई के उप महानिदेशक एसडी शर्मा आदि मौजूद थे।

उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर है यमुना का उद्गम

यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। हिमालयी घाटियों में करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना नदी प्रयागराज (इलाहाबाद) में गंगा में मिल जाती है। यहां तक इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है।

यमुना नदी बेसिन क्षेत्र की स्थिति (वर्ग किलोमीटर में)

राज्य	क्षेत्रफल	फीसद में
उत्तराखंड	3771	1.1
हिमाचल प्रदेश	5799	1.7
उत्तर प्रदेश	70437	20.4
हरियाणा	21265	6.1
राजस्थान	102883	29.7
मध्य प्रदेश	140208	40.6
दिल्ली	1485	0.4

यमुना नदी बेसिन में इस तरह बढ़ा दबाव (आजादी के बाद)

- आबादी का दबाव 3.5 गुना हुआ।
- सिंचाई की मांग दो गुनी हुई।
- नदी बेसिन क्षेत्र में भूजल दोहन तिगुना हुआ।
- आजादी के समय सतह वाले जल का दोहन 60 फीसद व भूजल दोहन 20 फीसद था।
- वर्तमान में भूजल दोहन 57 फीसद हो गया, जबकि सतह वाले जल का दोहन 37 फीसद तक किया जा रहा।
- यमुना व उसकी सहायक नदियों में जल प्रदूषण, खनन, गंदे पानी को उड़ेलने, इंडस्ट्री के गंदे पानी का दबाव आदि समस्याएं बढ़ रही हैं।

हिमालयी क्षेत्र में यह सहायक नदियां

ऋषि गंगा	हनुमान गंगा	टौंस व गिरी।

मैदानी क्षेत्र में यह सहायक नदियां

हिंडन	चंबल	सिंद	बेतवा	केन

स्वच्छ भारत का संकल्प दिला रही अमरनाथ यात्रा

बाबा अमरनाथ यात्रा के मार्गों पर जगह-जगह कूड़ेदान, सोकपिट्स, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था की गई है। जागरण

कूड़े के निस्ताकरण के लिए इस तरह के सेटेबल पिट्स बनाए गए हैं। जागरण

जागरण विशेष

दिनेश महाजन, जम्मू

- पवित्र गुफा के आसपास भी रखा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान
- कूड़े के निस्तारण के लिए लगाए गए हैं बायो सेटेबल पिट्स

बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान उम्दा स्वच्छता प्रबंधन बाबा बर्फानी के हजारों भक्तों को स्वच्छता का संकल्प भी दिला रहा है। यात्रा के पांचवें दिन (शुक्रवार को) यात्रियों की संख्या ने 60 हजार का आंकड़ा पार कर लिया।

पवित्र गुफा के आसपास भी पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा मार्ग और पड़ावों पर जगह-जगह कूड़ेदान, सोकपिट्स, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था की गई है। कूड़े के निस्तारण के लिए बायो सेटेबल पिट्स बनाए गए हैं। यात्रा के दौरान एकत्रित होने वाले कूड़े को जैविक तरीके से नष्ट किया जा रहा है। मानव मल को भी नष्ट करने के लिए विशेष तकनीक अपनाई जा रही है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

हर वर्ष लाखों श्रद्धालु समुद्र तल से करीब चौदह हजार फुट ऊंचाई पर बनी पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आसपास तीन सौ टेंट, जिनमें दुकानें बनाई गई हैं, के अलावा दो सौ टेंटों को श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इस वर्ष अमरनाथ गुफा के आसपास 90 शौचालय ब्लॉक के अलावा नहाने के लिए 240 ब्लॉक बनाए गए हैं। यात्रा के दोनों रूट बालटाल और पहलगाम में पांच हजार शौचालय ब्लॉक बनाए गए हैं।

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा के आसपास 50 सफाई कर्मियों को कूड़ा एकत्र करने के लिए लगाया है। कचरा निस्तारण के लिए 40 बायो सेटेबल पिट्स बनाए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के इंजीनियर मानिक कपूर ने बताया कि गुफा के आसपास एकत्रित होने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए ये बायो सेटेबल पिट्स कारगर हैं।

इन पिट्स (गड्ढों) की दीवारों को पत्थरों से बनाया जाता है, जो करीब तीस फीट गहरा होता है। पिट्स के भर जाने के बाद लकड़ियों का ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसके ऊपर टीन की चादर लगा कर उसे मलबे और बर्फ से ढक दिया जाएगा। पिट्स के भरने के साथ उसमें जीवाणुयुक्त घोल (माइक्रोबियल कांस्टीग) डाला जाएगा। यह जैविक घोल कूड़े को जैविक अवशेष में बदल देता है।

बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को पूरा कर पवित्र गुफा के आसपास ढांचा तैयार करने का काम 25 मई से शुरू हुआ था। उस समय गुफा के आसपास 15 से 35 फुट तक बर्फ पड़ी थी। इतनी अधिक मात्रा में बर्फ को पिघलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसके लिए यूरिया पोटाश का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन उससे भी बर्फ नहीं पिघली, तब पानी की बौछार की गई। इससे कुछ हद तक सफलता मिली और टेंट लगाने के लिए मैदान तैयार हो पाया। वर्तमान में गुफा के आसपास सात से 15 फुट तक बर्फ है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

धरोहर

बदरीनाथ से आठ किमी आगे लगभग 150 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से गिरती है यह जलधारा, स्कंद पुराण के वैष्णवखंड बद्रिकाश्रम माहात्म्य में बताई गई है इस जल प्रपात की महत्ता

शांति तलाशने 3000 श्रद्धालु पहुंच चुके वसुधारा

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्रतल से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर बदरीनाथ धाम से आठ किमी दूर स्थित वसुधारा जलप्रपात का धार्मिक महत्व तो है ही, यात्री यहां शांति एवं सुकून तलाशने भी पहुंचते हैं। इस बार बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां तीन हजार से अधिक यात्री और देशी-विदेशी पर्यटक पहुंच चुके हैं।

बदरीनाथ से तीन किमी आगे देश के अंतिम गांव माणा तक मोटर मार्ग है। यहां से शुरू होता है वसुधारा जल प्रपात तक का थका देने वाला सफर। लेकिन, यहां पहुंचकर ऐसी अनुभूति होने लगती है, मानो हम किसी अलौकिक स्थान पर आ गए हैं। लगभग 150 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से गिर रही जलधारा के छींटे तन पर पड़ते ही रास्ते की थकान पलभर में उड़नछू हो जाती है। इतनी ऊंचाई पर वायु और जल के मिश्रण से उत्पन्न सुमधुर संगीत हृदय के तारों को झंकृत कर देता है।

इन दिनों भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक वसुधारा पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) से आए पर्यटक राजेश, यामिनी और आयुषी कहते हैं कि वसुधारा आकर उन्हें जो खुशी मिली है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जीवन में प्रकृति का इतने खूबसूरत नजारे उन्होंने कभी नहीं देखे। श्री बदरीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल के अनुसार स्कंद पुराण के वैष्णवखंड बद्रिकाश्रम माहात्म्य में इस जल प्रपात की महत्ता बताई गई है। कहा गया है कि इस जल प्रपात का छींटा भी पड़ने से मनुष्य के समस्त विकार मिट जाते हैं। इसलिए बदरीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में यहां आने की इच्छा जरूर रहती है।

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित वसुधारा जल प्रपात पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है। बदरीनाथ धाम से आठ किमी दूर स्थित इस जलप्रपात में पर्यटक शांति की तलाश में पहुंच रहे हैं। जागरण

दो घंटे में तय होती पांच किमी की दूरी

वसुधारा के लिए फुट ट्रेक माणा गांव से शुरू होता है। सरस्वती मंदिर से गुजरने के बाद पांच किमी लंबा यह ट्रेक कठिन हो जाता है, क्योंकि यहां जमीन बेहद कठोर और पथरीली है, इसलिए माणा से वसुधारा तक की ट्रेकिंग में दो घंटे लग जाते हैं। मार्ग पर भोजन और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है।

अष्ट वसु ने किया था तप

मान्यता है कि यहां अष्ट वसु (आप यानी अयज, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष व प्रभाष) ने कठोर तप किया था, इसलिए इस जल प्रपात का नाम वसुधारा पड़ा। यह जल प्रपात इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से शिखर तक एक नजर में नहीं देखा जा सकता। यहां पहुंचने के लिए माणा गांव से घोड़ा-खच्चर और डंडी-कंडी की सुविधा भी उपलब्ध है।

सहदेव ने त्यागे थे प्राण

भारत-चीन सीमा से लगे इस क्षेत्र के किसी गांव में जब भी देवरा यात्र आयोजित होती है तो श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए वसुधारा जरूर पहुंचते हैं। मान्यता है कि राजपाट से विरक्त होकर पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग गए थे। कहते हैं कि वसुधारा में ही सहदेव ने अपने प्राण और अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव त्यागा था।

ये भी जानिए

1992 के बाद पहली बार विश्व कप में पाकिस्तान के दो बल्लेबाजों (बाबर और इमाम) ने एक ही विश्व कप में शतक लगाए हैं। इससे पहले रमीज राजा और आमिर सोहेल ने ऐसा किया था।

क्रिकेट करियर में साथ देने वाले लोगों को विशेष तरह से शुक्रिया दे रहे हैं माही, धौनी का यह आखिरी विश्व कप, जल्द अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ले सकते हैं संन्यास

आखिरी पड़ाव पर सबको 'तोहफा' दे रहे हैं पूर्व कप्तान धौनी

अभिषेक त्रिपाठी • लीड्स

महेंद्र सिंह धौनी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और इस लंबे सफर में जिसने भी उनका साथ दिया वह उनको किसी ना किसी अंदाज में तोहफा दे रहे हैं। वह अभ्यास के दौरान मैदान में पत्रकारों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं तो प्रशंसकों को जमकर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। यही नहीं, इस विश्व कप में उन्होंने हर उस कंपनी के लोगो का फ्री में इस्तेमाल किया, जिसने उनको अभी तक खेल का सामान उपलब्ध कराया।

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर धौनी अपने बल्ले और दस्ताने में किसी कंपनी का लोगो लगाकर प्रचार करने के लिए अमूमन सात से आठ करोड़ रुपये प्रति वर्ष लेते हैं, लेकिन इस विश्व कप में उन्होंने किसी भी कंपनी से करार नहीं किया, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि अब तक जितने भी लोगों ने उनकी मदद की है उनको वह अपनी तरफ से तोहफा देंगे। धौनी इस टूर्नामेंट में कभी पैरा मिलेट्री फोर्स के लोगो 'बलिदान' के साथ उतरे तो कभी उन्होंने एसजी, एसएस और बीएएस कंपनियों के लोगो लगाकर बल्लेबाजी व विकेटकीपिंग की। बलिदान लोगो लगाकर वह उस सेना को सम्मान देना चाहते थे जिसने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया है। हालांकि, इसके कारण उन्हें विवाद का सामना भी करना पड़ा और आइसीसी ने उन्हें अपने विकेटकीपिंग दस्ताने में इसका प्रयोग करने से मना कर दिया।

धौनी के दोस्त अरुण पांडेय ने दैनिक जागरण से कहा कि एक खिलाड़ी की खेल के सामान के साथ जो साझेदारी होती है वह बेहद अहम है। यह दिल की साझेदारी होती है। क्रिकेटर के लिए यह मनोवैज्ञानिक तौर पर भी महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी 100 के करीब होता है या जीत के लिए जा रहा होता है तो वह विशेष बल्ला मंगाता है। ऐसा ही कुछ धौनी के साथ रहा है। जहां तक अलग-अलग लोगो के इस्तेमाल की बात है तो उनका करार काफी समय से स्पार्टन के साथ था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। हम लोग सोच रहे थे कि यह मामला सुलझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पार्टन के हटने के बाद कूकाबुरा सहित कई कंपनियों के प्रस्ताव हमारे पास आए, लेकिन बाद में माही ने तय किया कि वह इस विश्व कप में कुछ अलग करेंगे। आज भले ही खेलों का सामान बनाने वाली कंपनी कह दे कि वह माही को 50 सा 100 बल्ले भेज देगी, लेकिन शुरुआती दौर में जिसने मदद की वह काफी अहम है। उस समय कोई एक बल्ला भी बड़ी मुश्किल से देता था, इसलिए माही ने तय किया कि वह उन सबको तोहफा देंगे जिन्होंने उनको शुरुआती दौर में मदद की।

उनके इस कदम का एक मंतव्य और भी है। माही चाहते हैं कि खेलों का सामान बनाने वाली कंपनियां आगे भी इसी तरह नई प्रतिभाओं का समर्थन करती रहे हैं। कल को क्या पता कि किसी किसी सुदूर क्षेत्र से एक और धौनी व विराट मिल जाए। खिलाड़ी के लिए एक बल्ला, 50 करोड़ से ज्यादा मायने रखता है। माही ऐसे ही हैं। अगर आप 50 करोड़ दे दो तो वह यह ना करें और कभी वह फ्री में भी ऐसा कर सकते हैं।

माही के एक और करीबी से जब बलिदान बैच के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस लोगो के जरिये वह सेना का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि वह अपनी तरफ से सेना को शुक्रिया अदा कर रहे थे। खेलों का सामान बनाने वाली कंपनी एसजी के मार्केटिंग डायरेक्टर पारस आनंद से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विश्व कप से पहले हमारी उनसे बात हुई थी। हम इस विश्व कप के लिए उनके साथ करार करना चाहते थे, लेकिन वह लंबे समय का करार चाह रहे थे। हालांकि, बाद में उनकी तरफ से हमें संदेश आया कि वह इस विश्व कप में किसी के साथ करार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह अपनी मर्जी से संबंधित कंपनियों के लोगो लगाकर सबको तोहफा देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। वह कई बार एसजी के बल्ले व दस्ताने के साथ मैदान में उतरे।

पारस ने कहा कि खासतौर पर पिछले चार साल में धौनी सहित कई भारतीय खिलाड़ियों को हमने बल्ले दिए जो उन्हें काफी पसंद भी आए। धौनी की तरफ से यह तोहफा मिलने पर हम काफी खुश हैं। वहीं, एसएस कंपनी के मालिक जतिन सरीन ने कहा कि धौनी ने काफी समय तक हमारे बल्ले का इस्तेमाल किया है। 2011 विश्व कप के फाइनल में उन्होंने हमारे बल्ले से ही छक्का मारा था। हम खुश है कि उनके क्रिकेट के सफर में हम उनके साथी बने।

कल है धौनी का जन्मदिन

लीड्स : रांची में जन्मे धौनी रविवार को 38 साल के हो जाएंगे। वह अब तक 90 टेस्ट के अलावा 348 वनडे और 98 टी-20 खेल चुके हैं। अब देखना है कि टीम इंडिया उनका यह जन्मदिन किस खास अंदाज में मनाती है।

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी • एएफपी

'प्लान-ए' पूरा अब 'प्लान बी' का समय

श्रीलंका के खिलाफ मैच आज, अंक तालिका में नंबर वन पर पहुंचने का मौका आखिरी लीग मुकाबले में मध्य क्रम को खुद को स्थापित करना होगा

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी • लीड्स

चारों तरफ से ठेठ अंग्रेजी स्टाइल के मकानों से घिरे यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के हेडिंग्ले क्रिकेट मैदान में शनिवार को भारतीय टीम अपने आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह यह मैच जीतती है और ऑस्ट्रेलिया मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना मैच हारती है तो भारत को न्यूजीलैंड से पहला सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलेगा। भारतीय टीम भी ऐसा चाहेगी क्योंकि अंक तालिका में नंबर दो पर रहने पर उसे तीसरे नंबर की खतरनाक मेजबान टीम इंग्लैंड का सामना करना होगा। हालांकि, इसके लिए भारतीय टीम को शीर्ष क्रम की जगह मध्य क्रम पर भी मेहनत करनी होगी। प्लान-ए के तहत शीर्ष क्रम ने अब तक अपना काम पूरा किया है और अब प्लान-बी के तहत कमजोर मध्य क्रम को मैदान पर जौहर दिखाने होंगे।

भारत ने बर्मिंघम में बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था और जब हमारे पास यह संदेश आया कि टीम शनिवार को वैकल्पिक अभ्यास करेगी तो लग रहा था कि कुछ खिलाड़ी ही मैदान में आएंगे, लेकिन दोपहर होते-होते कप्तान विराट कोहली, रिषभ पंत, केएल राहुल, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी और केदार जाधव मैदान में पहुंच गए। युजवेंद्रा सिंह चहल, हार्दिक पांड्या और मुहम्मद शमी के आराम करने के कारण अभ्यास कराने आए गेंदबाज नवदीप सैनी और धौनी ने टीम को बल्लेबाजी का काफी अभ्यास कराया। धौनी बीच वाले नेट पर काफी देर तक विराट और रिषभ को गेंदबाजी कराते रहे। इस विश्व कप में चार शतक लगाने वाले ओपनर रोहित शर्मा ने भी आराम करना ही मुनासिब समझा और वह भी अभ्यास में नहीं आए। भारतीय टीम तीसरी विश्व कप ट्रॉफी से दो कदम दूर है। उसे बस सेमीफाइनल और फाइनल जीतना है।

प्लान बी पर जोर : भारतीय टीम सेमीफाइनल में भले ही पहुंच गई हो, लेकिन उसका मध्य क्रम पुख्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच में उसे अपने संयोजन को स्थापित करने का आखिरी मौका मिला है। इस मैच के जरिये टीम यह तो तय कर ही सकती है कि वह सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी, साथ ही वह यह भी तय कर सकती है कि सेमीफाइनल और फाइनल में उसे किस संयोजन के साथ जाना है। भारत के ओपनर और उप कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक चार शतक के साथ 544 रन बनाए हैं, वहीं तीसरे नंबर के बल्लेबाज व कप्तान विराट कोहली ने पांच अर्धशतक के साथ 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा एक और ओपनर शिखर धवन ने चोटिल होने से पहले एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था। केएल राहुल ने भी पिछले मैच में ओपनिंग करते हुए अर्धशतक लगाया था। कुल मिलाकर जब-जब भारत का शीर्ष क्रम चला है तब-तब उसे जीत मिली है, लेकिन अब भारतीय प्रबंधन प्लान-बी यानी मध्य क्रम पर जोर दे रहा है। शुक्रवार के अभ्यास में साफ दिखाई दिया कि प्रबंधन चाहता है कि महेंद्र सिंह धौनी, दिनेश कार्तिक और रिषभ पंत मध्य क्रम में टीम को ठोस आधार दें, जबकि हार्दिक पांड्या 300 के पार जाने में मदद दें, क्योंकि सबको पता है कि श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने में खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल जैसे दबाव वाले मैचों में मध्य क्रम ही बचाएगा। केदार जाधव के क्लिक नहीं कर पाने के कारण बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में दिनेश कार्तिक को उतारा गया था। उन्होंने शुक्रवार को बल्लेबाजी का अभ्यास किया। ऐसे में टीम उनको एक और मौका देकर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए तैयार कर सकती है। अभी तक धौनी स्पिनरों के खिलाफ 81 गेंद में केवल 47 रन ही बना पाएं हैं जिससे बीच के ओवरों में धीमे गेंदबाजों के खिलाफ कमजोरी दिख रही है।

मयंक की खेलने की संभावना नहीं : चोटिल विजय शंकर की जगह मयंक आ चुके हैं और उनके परम मित्र लोकेश राहुल दो अर्धशतक जड़कर रोहित के साथ शीर्ष क्रम में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। रोहित तो गजब की फॉर्म में हैं। ऐसे में अब मयंक को मौका मिलने की संभावना काफी कम है। रवींद्र जडेजा को अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है। पिछले मैच में भारतीय टीम तीन तेज गेंदबाजों मुहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और एक स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल के साथ उतरी थी। ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया यहां पर किस संयोजन के साथ उतरती है। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के मुकाबले में यहां की पिच पर स्पिन दिखाई दी थी। ऐसे में टीम कुलदीप और चहल को वापसी करा सकती है। ऐसे में बुमराह, शमी और भुवी में से किसी एक को आराम दिया जा सकता है। बुमराह ने अब तक सभी मैच खेले हैं, ऐसे में उनको आराम मिलने की संभावना है। श्रीलंकाई टीम में बायें हाथ के बल्लेबाजों की संख्या को देखते हुए जडेजा को मौका मिलना मुश्किल है।

श्रीलंका के पास आखिरी मौका : आठ मैचों में तीन जीत और तीन हार के साथ श्रीलंका टीम का सफर कुछ खास नहीं रहा है। वह इकलौती टीम है जिसके दो मैच बारिश के कारण पूरे नहीं हुए। वह पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन दुनिया की नंबर वन टीम को हराकर वह खुद के लिए कुछ सम्मान कमाना चाहेगी। उसने इसी मैदान पर उस समय की नंबर वन इंग्लिश टीम को यहां हराया था। उसके बाद इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए थे। दिमुथ करुणारत्ने की कप्तानी वाली इस टीम के मुख्य हथियार लसित मलिंगा हैं जो अपनी धीमी गेंदों में वैरिएशन के लिए जाने जाते हैं। इस टूर्नामेंट में श्रीलंकाई ऑफ स्पिनर धनंजय डिसिल्वा काफी किफायती रहे हैं। करुणारत्ने अपने बायें हाथ के स्पिनर मिलिंदा सिरीवर्धना का भी इस मैच में इस्तेमाल करना चाहेंगे। बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो ने इस विश्व कप में भले ही तीन मैच खेले हों, लेकिन इसमें 183 रन बनाए हैं। श्रीलंका लाहिरु थिरिमाने की जगह परेरा को शामिल कर सकता है।

अभ्यास सत्र के दौरान कप्तान विराट कोहली से मिलने दो नन्हे प्रशंसक पहुंचे • एएफपी

2011 विश्व कप का फाइनल दोनों देशों के बीच विश्व कप में पिछला मुकाबला था। यह मुकाबला भारतीय सरजमीं पर मुंबई में खेला गया। इसे जीतकर भारत ने खिताब पर कब्जा जमाया था

टीम भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, युजवेंद्रा सिंह चहल, मुहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, मयंक अग्रवाल, रवींद्र जडेजा और केदार जाधव।

टीम श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, लाहिरु थिरिमाने, एंजेलो मैथ्यूज, लसिथ मलिंगा, जीवन मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, कासुन राजिता, इसुरु उदाना, सुरंगा लकमल, मिलिंदा सिरीवर्धना, जेफ्री वांर्डेसे, तिसारा परेरा और अविष्का फर्नांडो।

पिच रिपोर्ट : अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार को जिस पिच पर मुकाबला हुआ था शनिवार को वहीं पर भारत और श्रीलंका की भिड़ंत होगी। पिच सपाट और धीमी रह सकती है। इसमें स्पिनर को कुछ मदद मिल सकती है।

श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने अभ्यास के दौरान • एएफपी

मौसम रिपोर्ट : शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। सूरज निकला रहेगा और हवाएं चलती रहेंगी। ऐसे में तेज गेंदबाजों को कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी।

12 वनडे में छह बार तिसारा परेरा ने धौनी को आउट किया है। इस दौरान उन्होंने उनको 142 गेंदों पर 144 रन दिए हैं

158 वनडे अब तक भारत और श्रीलंका के बीच हुए हैं। भारत 90 और श्रीलंका 56 जीता, एक मैच टाई और 11 बेनतीजा रहे

04 शतक रोहित इस विश्व कप में लगाकर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा की बराबरी कर चुके हैं। उनके पास श्रीलंका के खिलाफ ही इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है

08 मैच अब तक भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप में हुए। भारत तीन, श्रीलंका चार जीता, एक मैच परिणाम रहित रहा

46 मैच अब तक तटस्थ स्थान पर भारत और श्रीलंका के बीच हुए। भारत 26 और श्रीलंका 17 जीतने में कामयाब रहा, एक मैच टाई और दो बेनतीजा रहे

विराट ने फुटबॉलर हैरी केन के साथ क्रिकेट खेला

हैरी कैन और विराट कोहली • रायटर

विशेष संवाददाता, लीड्स : फीफा विश्व कप के गोल्डन बूट विजेता इंग्लिश फुटबॉलर हैरी केन ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को शुभकामनाएं दीं, जो क्रिकेट विश्व कप में मेजबान टीम के पहले खिताब की उम्मीद में इंग्लैंड की सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। फुटबॉल विश्व कप में केन छह गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे थे, जिससे उन्होंने गोल्डन बूट जीता था और टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर चौथे स्थान पर रही थी।

इंग्लैंड की मेजबानी में खेले जा रहे मौजूदा आइसीसी विश्व कप के दौरान केन और कोहली की मुलाकात हुई। इस दौरान केन ने कोहली के खिलाफ बल्लेबाजी की और फिर भारतीय कप्तान को गेंदबाजी भी की। केन ने ट्वीट किया, 'हाल में लॉर्ड्स में विराट कोहली के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताया। अगर वह इंग्लैंड के खिलाफ (सेमीफाइनल में) खेलते हैं तो इस मैच को छोड़कर उन्हें विश्व कप के बचे हुए मैचों के लिए शुभकामनाएं।' टॉटनहम के इस स्ट्राइकर ने कहा, 'विराट शानदार खिलाड़ी हैं। दबाव वाली परिस्थितियों में आप किस तरह के खिलाड़ी हो, इसमें खेल से पता चल जाता है। वह बार-बार ऐसी स्थिति से गुजरते हैं।' उन्होंने अपनी मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया। कोहली ने इसमें केन के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'मुझे फुटबॉल पसंद है। हम एक दिन इसके बारे में ही बात कर रहे थे। हर क्रिकेट टीम अपने वॉर्म अप के लिए फुटबॉल खेलती है। शर्तिया कह सकता हूं कोई भी फुटबॉल टीम इसके लिए क्रिकेट नहीं खेलती है। केन क्रिकेट में काफी बेहतर हैं, इतना मैं फुटबॉल में नहीं हूं।'

पंत को नंबर-चार के लिए भरोसा जीतना होगा

सुनील गावस्कर

कलम से

विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें अब तय हो चुकी हैं, लेकिन अंक तालिका में पहले नंबर पर कौन रहेगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस समय जैसी फॉर्म में है, उसे देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसे जीतना चाहिए। इस जीत के साथ वह भारत को एक अंक से पछाड़कर शीर्ष स्थान पर बना रहेगा। न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के हाथों हारने तक भी श्रीलंका दौड़ में बना हुआ था। मगर इंग्लैंड ने यह मैच जीतकर 12 अंक हासिल कर लिए। इसके बावजूद श्रीलंका भी दक्षिण अफ्रीका की तरह अपने अभियान का समापन जीत के साथ करना चाहेगा। दोनों टीमों में कई योग्य खिलाड़ी हैं, लेकिन वे एक टीम के रूप में अपनी टीम के लिए ज्यादा जीत हासिल करने में विफल रहे।

श्रीलंकाई टीम अपनी क्षमता के अनुसार खेल नहीं दिखा पाई और गेंदबाजी के दम पर वे कई मौकों पर मुश्किल स्थिति से बाहर निकलते रहे। अनुभवी लसित मलिंगा ने कुछ शानदार ओवर फेंककर लंका टीम को मैच जिताए। श्रीलंका की बल्लेबाजी में जयवर्धने और संगकारा जैसी निरंतरता नहीं है। ना ही उनके पास जयसूर्या, कालूवितर्णा और दिलशान जैसी तूफानी शुरुआत दिलाने वाले खिलाड़ी हैं। कुशल परेरा बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन कुशल मेंडिस की तरह वह भी निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से श्रीलंकाई टीम को संघर्ष करना पड़ा है। अविष्का फर्नांडो ने पिछले मैच में शानदार शतक बनाया था और श्रीलंका को इस बार भी उनसे ऐसी ही उम्मीद होगी, ताकि भारतीय टीम पर दबाव बना सकें।

भारत का मध्य क्रम बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। धवन की चोट की वजह से नंबर चार की समस्या फिर से खड़ी हो गई है क्योंकि राहुल को ओपनिंग करनी पड़ रही है। विजय शंकर कभी भी इस स्थान के लिए उपयुक्त नहीं लगे और पंत को भी भरोसा जीतना होगा कि वह सिर्फ कुछ आकर्षक शॉट मारने वाले बल्लेबाज से ज्यादा योग्य हैं। उनके बायें हाथ का होना भारत के लिए एक अच्छी बात है और अगर यह युवा खिलाड़ी 30-40 रनों की पारी को प्रभावी पारी में बदलता है, तो नंबर चार की समस्या लंबे समय तक फिर नहीं उभरेगी।

विश्व कप अंतिम लीग मैच में आज होगा दक्षिण अफ्रीका से सामना

शीर्ष पर रहना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया

मैनचेस्टर, एएफपी : ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर का मानना है कि जब उनकी टीम शनिवार को यहां विश्व कप के मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो गेंद से छेड़छाड़ के लिए 12 महीने का प्रतिबंध झेल चुके स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं होगा। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन यह मैच निर्धारित करेगा कि वह तालिका में शीर्ष पर पहुंचती है या नहीं, ताकि अंतिम चार में मेजबान इंग्लैंड से भिड़ंत से बच सके।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के ये दोनों खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ के कारण प्रतिबंधित हुए थे, जिसमें उनके अलावा साथी कैमरन बेनक्राफ्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। ये दोनों प्रतिबंध से वापसी के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे।

इंग्लैंड में दर्शकों ने विश्व कप के मैचों के दौरान स्मिथ और वार्नर की काफी हूटिंग की, जिनका यह प्रतिबंध समाप्त होने के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। लैंगर ने कहा, 'इंग्लैंड में आने के बाद उन्हें जिस चीज की उम्मीद थी, वे उसे झेल चुके हैं। यह मैच हमारे कई खिलाड़ियों के लिए अहम है, लेकिन हमें भावनाओं को इससे दूर रखना होगा। हमें यहां से दो अंक लेने होंगे और जीत की लय जारी रखनी होगी और खिलाड़ियों के लिए यह विश्व कप का एक और रोमांचक मैच होगा।' विश्व कप के शीर्ष स्कोरर में शामिल वार्नर फिर से पिता बने हैं। लैंगर अपने दोनों स्टार बल्लेबाजों की फॉर्म से खुश हैं। उन्होंने कहा, 'वे ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं।' रिकॉर्ड पांच विश्व कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस चरण में प्रबल दावेदारों में शुमार नहीं थी और गेंद से छेड़छाड़ के प्रकरण के बाद बिखरी हुई दिख रही थी। लेकिन, वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी। लैंगर ने कहा, 'केपटाउन के प्रकरण के बाद यहां तक पहुंचने के लिए काफी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बड़ा संकट था।' दक्षिण अफ्रीका की टीम हालांकि अपने अभियान का अंत जीत से करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को देखकर नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, जिससे इस बार भी टीम निराशाजनक तरीके से टूर्नामेंट खत्म करेगी।

इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट	
ऑस्ट्रेलिया	
मिशेल स्टार्क	24
पैट कमिंस	12
बहरनडॉर्फ	08
दक्षिण अफ्रीका	
क्रिस मॉरिस	12
इमरान ताहिर	10
फेलुकवायो	09

द. अफ्रीकी कप्तान डुप्लेसिस • रायटर

इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन	
ऑस्ट्रेलिया	
डेविड वार्नर	516
आरोन फिंच	504
ख्वाजा	298
दक्षिण अफ्रीका	
डुप्लेसिस	287
डिकॉक	253
डेर डुसेन	216

100 वां वनडे मैच होगा यह ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के बीच। दोनों के बीच अब तक हुए 99 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 48 व दक्षिण अफ्रीका ने 47 जीते हैं। तीन मैच टाई रहे और एक बेनतीजा रहा

17 वनडे मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तटस्थ स्थल पर। इनमें ऑस्ट्रेलिया ने नौ और दक्षिण अफ्रीका ने छह मैच जीते। एक मैच टाई रहा, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा

05 वनडे मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व कप में। इनमें ऑस्ट्रेलिया ने तीन व दक्षिण अफ्रीका ने एक मैच जीता। एक मैच टाई रहा

300 पार जाकर भी पाक हुआ बाहर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पाकिस्तान की टीम एक असंभव मिशन के लिए शुक्रवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर विश्व कप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उतरी थी। बांग्लादेश की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती तो पाकिस्तान बिना कोई रन बनाए ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाती। टॉस ने हालांकि पाकिस्तान का साथ दिया और उसने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भरपूर कोशिश की। पाकिस्तानी टीम इमाम उल हक और बाबर आजम की बेहतरीन पारियों के दम पर 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 315 रन तक तो पहुंची, लेकिन यह स्कोर भी उसे सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं हुआ। जवाब में बांग्लादेश 44.1 ओवर में 221 रन पर ऑल आउट हो गई और 94 रन से मैच हार गई। हालांकि इसके बावजूद भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका और बाहर हो गया। उनकी ओर से शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 35 रन देकर छह विकेट लिए।

मुहम्मद सैफुद्दीन ने 23 रन के कुल स्कोर पर फखर जमां (13) का विकेट लेकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। फिर इमाम और बाबर ने विकेट पर टिकने में सफलता हासिल की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 157 रनों की साझेदारी की। सैफुद्दीन ने बाबर को शतक से चार रन पहले ही पवेलियन भेज दिया। इस बल्लेबाज ने 98 गेंदों का सामना कर 11 चौकों की मदद से 96 रन बनाए। बाबर के जाने के बाद इमाम ने शतक पूरा किया, लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से आउट हुए। मुस्तफिजुर रहमान की गेंद को बैकफुट पर खेलने गए इमाम हिट विकेट हो गए। 100 गेंदों पर 100 रन बनाने वाले इमाम ने अपनी पारी में सात चौके लगाए। मुहम्मद हफीज सिर्फ 26 रन ही बना सके। इमाद वसीम ने अंत में तेजी से 26 गेंदों पर 43 रन बनाए, लेकिन कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका। 255 के स्कोर पर कप्तान सरफराज अहमद गेंद लगने के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए। मुस्तफिजुर ने पांच विकेट लिए।

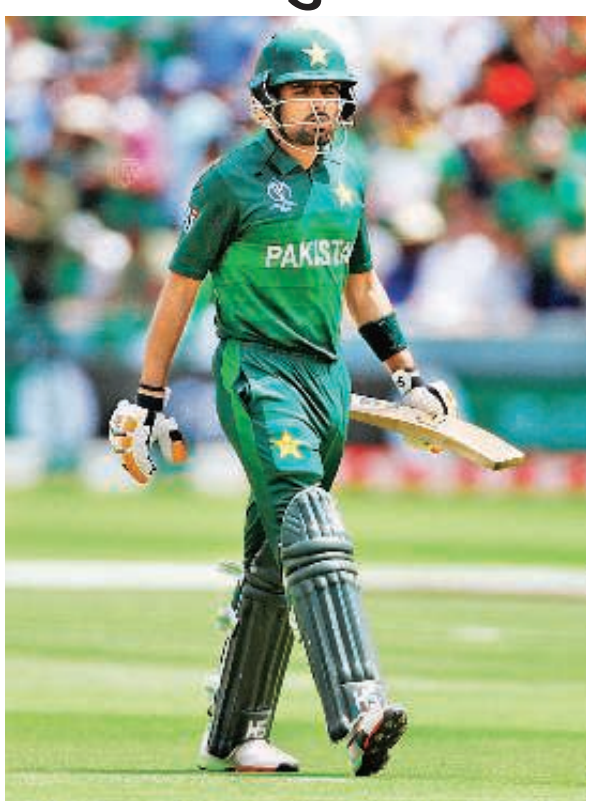

आउट होने के बाद पवेलियन लौटते बाबर आजम। एपी

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
शनिवार 6 जुलाई 2019
www.jagran.com

रेबीज की वैक्सीन का सफल परीक्षण किया

1885 में आज ही फ्रेंच रसायन शास्त्री लुई पास्चर ने जोसफ नामक लड़के (जिसे एक कुत्ते ने काट लिया था) पर रेबीज की वैक्सीन का सफल परीक्षण किया था। रेबीज एक वायरल रोग है, जो दिमाग में सूजन पैदा करते हुए पूरे शरीर को प्रभावित करता है।

एके-47 का उत्पादन शुरू हुआ

1947 में आज ही सोवियत संघ में एके-47 का उत्पादन शुरू हुआ था। एक-47 एक असॉल्ट राइफल है, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल मिखाइल कलाशनिकोव ने 1946 में बनाया था। यह राइफल एक मिनट में सौ गोलियां दाग सकती है।

कश्मीर की खातिर बलिदान हो गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी

शिक्षाविद्, बैरिस्टर, भारतीय राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में आज ही कोलकाता में हुआ था। वह कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। 1929 में बंगाल विधान परिषद में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। 21 अक्टूबर, 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वह जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। कश्मीर को विशेष दर्जा देने और अलग झंडा रखने का उन्होंने खुलकर विरोध किया।1953 में उन्हें कश्मीर में घुसने के प्रयास के कारण को गिरफ्तार किया गया। 23 जून 1953 को पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई।

शोध अनुसंधान

फ्लू से बचाव को कमजोर कर सकती हैं एंटीबायोटिक दवाएं

एक अध्ययन में पाया गया है कि फ्लू से बचाव करने वाली प्रारंभिक प्रणाली को एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर कर सकती हैं। इससे फेफड़े फ्लू वायरस की चपेट में आ सकते हैं और संक्रमण के गंभीर होने का खतरा हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, अध्ययन में यह पाया गया कि आंत (गट) में पाए जाने वाले बैक्टीरिया फेफड़ों के बचाव की पहली रक्षा पंक्ति को कायम रखने में मदद करते हैं। यह निष्कर्ष चूहों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। स्वस्थ्य गट बैक्टीरिया वाले चूहे जब फ्लू से संक्रमित हुए तो उनमें से करीब 80 फीसद बच गए, लेकिन संक्रमण से पहले एंटीबायोटिक दवाओं की खुराक पाने वाले चूहों में से सिर्फ एक तिहाई ही जीवित बचे। ब्रिटेन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता एंड्रियास वेक ने कहा, 'हमने पाया कि एंटीबायोटिक दवाएं प्रारंभिक फ्लू प्रतिरोधक को खत्म कर सकती हैं।' प्रेट्र

कीटनाशकों से किशोरों में डिप्रेशन का खतरा

किशोरों में डिप्रेशन (अवसाद) और कीटनाशकों के बीच जुड़ाव का पता चला है। एक अध्ययन में पाया गया है कि किशोरों में कीटनाशकों का स्तर बढ़ने से डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष कृषि वाले इलाकों के आसपास रहने वाले बच्चों पर अध्ययन के आधार पर निकाला है। 11 से 17 साल की उम्र के 529 बच्चों पर 2008 से नजर रखी गई। ऐसे बच्चों में रक्त में एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज (एसीएचई) के स्तर को मापने के लिए जांच की गई। कीटनाशकों के चलते एसीएचई की गतिविधि में रुकावट खड़ी होती है। जिन किशोरों में निम्न एसीएचई गतिविधि पाई गई, उनमें डिप्रेशन का लक्षण ज्यादा देखने को मिला। प्रेट्र

व्यायाम के बाद भी क्यों नहीं घटता है वजन

रहें सतर्क ▶ ज्यादा भोजन और दैनिक गतिविधियां कम करने से व्यर्थ हो जाते हैं सभी प्रयास

व्यायाम के साथ-साथ खानपान और अन्य क्रियाकलाप भी हैं जरूरी

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को सेहतमंद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्सर देखने में आता है खुद को फिट रखने के लिए लोग जिम में जमकर पसीना बहाते हैं और उसके बाद भी उनके वजन में फर्क नहीं पड़ता। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इसकी वजह बताई है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, वर्तमान जीनवशैली में वजन बढ़ना आम बात सी हो गई है, जिसे घटाने के लिए लोग अपने-अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। लेकिन जाने-अनजाने वे अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा बदलाव कर लेते हैं जो उल्टा उनका ही दुश्मन बन जाती है, जिसके चलते वजन घटाने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि लोग अक्सर व्यायाम के बहाने ज्यादा खाना खाने लगते हैं, या वे लोग अपने अन्य दैनिक क्रियाकलाप कम कर देते हैं, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका वजन अन्य की अपेक्षाकृत कुछ कम हुआ। शोधकर्ताओं ने कहा कि इन लोग की सफलता अन्य लोगों के लिए एक पाठ हो सकती है।

व्यायाम शरीर के लिए लाभदायक है।प्रतीकात्मक

कैसे किया अध्ययन: इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 18 से 61 वर्ष के 171 ऐसे लोगों को शामिल किया जो जिम जाकर व्यायाम नहीं करते थे। शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों को सामान्य जीवन जीने को कहा गया, जबकि कुछ लोगों को व्यायाम शुरू करवाया गया। व्यायाम करने वाले लोगों को भी दो समूहों में बाटा गया। एक समूह को व्यायाम के जरिये सप्ताह में करीब 700 कैलोरी घटानी थी, वहीं दूसरे समूह को 1,760 कैलोरी कम करनी थी।

दैनिक क्रियाकलाप हैं जरूरी: अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग व्यायाम नहीं कर रहे थे, उनमें कोई अंतर नहीं देखा गया। वहीं, जो लोग व्यायाम कर रहे थे उनका वजन बहुत कम घटा पाया गया क्योंकि उन्होंने व्यायाम करने के बाद ज्यादा आहार लेना शुरू कर दिया था और अपनी दिनचर्या भी उन्होंने बदल दी थी। इससे उनके शरीर में व्यायाम का कोई फायदा नहीं देखा गया। करसत करने से लोग पतले होते हैं यह तो सभी जानते हैं। लेकिन मनुष्य का मेटाबोलिजम (उपापचय) हमेशा इसे सिद्ध नहीं करता। कई पुराने अध्ययन बताते हैं कि जिन लोगों ने वजन घटने के लिए नए व्यायाम शुरू किया था, उनका वजन कम होने की बजाय कई गुना बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अपने दैनिक क्रियाकलापों 30 से 40 फीसद तक कम कर दिए थे।

कैसे हो सकता है फायदा : शोधकर्ताओं ने बताया कि यदि आप वास्तव में अपना शरीर फिट रखना चाहते हैं तो आपको कसरत के साथ-साथ अपने दैनिक क्रियाकलाप भी पूर्ववत ही रखने होंगे। साथ ही अपने भोजन से ऐसे आहारों को दूर रखना होगा जो वजन बढ़ाते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि आप ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य-पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपको यह भी तय करना होगा कि उस कैलोरी को कैसे बर्न (कम) करना है। तब जाकर आप अपने वजन पर कंट्रोल पा सकते हैं।

लोकगीतों का उत्सव : पूर्वी जर्मनी के बाउट्जेन में अंतरराष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव 'लुजिका, लुसिट्ज, लुसाटिया 2019' के मौके पर आयोजित भव्य परेड में पारंपरिक पोशाक में डांस करती पेरु की नर्तकी। कैथोलिक सोरब्स, जर्मन के स्लाव अल्पसंख्यक और अन्य जातीय समूह सामूहिक रूप से यह त्योहार मनाते हैं। इस दौरान प्रतिभागी लोकगीत प्रस्तुत करते हैं। एपी

बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है स्वचालित कार

▶ ब्रिटेन में न्यूकैसल यूनिवर्सिटी शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर किया दावा

▶ जीवन में लगाएंगी बड़ा बदलाव, दुर्घटना का खतरा भी होगा कम

लंदन, आइएएनएस : एक उम्र के बाद लोगों के लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि 60-65 वर्ष के बाद अक्सर स्वास्थ्य शरीर का साथ नहीं देता। ऐसे में ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि स्वचालित कारें बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी कम किया जा सकता है।

ब्रिटेन में न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से शुओ ली ने कहा कि आम कारों में जहां पूरी गाड़ी पर ड्राइवर का नियंत्रण रहता है वहीं, स्वचालित कारों में ड्राइवर को पूरी तरह से छुट्टी दी जा सकेगी। इन कारों से यात्रा करने वाले यात्री पिछली सीटों पर बैठकर फिल्म देखने के साथ-साथ खा-पी भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन कारों के ऑटोमेशन के शून्य से पांच तक के स्तर होते हैं, लेकिन अभी कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जहां कार चालक को नियंत्रण रखना पड़ सकता है और कुछ देर बाद कार फिर स्वचालित मोड पर आ जाएंगी।

यह अध्ययन 'ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च' जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 76 चालकों की ड्राइविंग का अध्ययन किया। इन चालकों को दो आयु समूहों (20-35 और 60-81) में विभाजित कर यह देखा गया है कि बुजुर्ग चालक स्वचालित कार का नियंत्रण वापस लेने में कितना समय ले रहे हैं। साथ ही यह भी जांच की गई कि विभिन्न स्थितियों में उनके ड्राइविंग की गुणवत्ता कैसी है। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि सभी चालकों की ड्राइविंग का स्तर अच्छा था। लेकिन युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग चालक स्वचालित कार का नियंत्रण वापस लेने में ज्यादा समय लिया।

ली ने कहा कि कार का नियंत्रण वापस लेने के लिए जहां बुजुर्गों को 8.3 सेकेंड का समय लगा वहीं कम उम्र के समूह ने 7 सेकेंड में अपना टास्क पूरा किया। हालांकि बुजुर्ग ड्राइवरों ने एक्सेलेरेटर और ब्रेक के संचालन के मामले में बहुत खराब प्रर्दशन किया, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि स्वचालित कारें बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इससे न सिर्फ वह दुर्घटना के जोखिम से बचेंगे बल्कि स्तरीय जीवन भी जी सकते हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह सुझाव भी दिया है कि स्वचालित कारों को खराब मौसम में चलाने से बचना चाहिए।

ब्रिटेन के शोधार्थियों का यह अध्ययन 'ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च' जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं डेयरी उत्पाद : अध्ययन

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क : दूध और डेयरी उत्पादों के पर्याप्त सेवन से कई पुरानी व गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन में में दावा किया गया है कि गर्भावस्था के दौरान दूध के सेवन और बच्चों के जन्म के समय के वजन, लंबाई के बीच एक सकारात्मक संबंध देखा जाता है, जबकि बुजुर्गों में डेयरी उत्पादों के प्रतिदिन सेवन से कमजोरी और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। स्पेन, यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह अध्ययन 'एडवांसेज इन न्यूट्रिशन' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा (यूजीआर) के प्रोफेसर एंजल गिल और कॉप्लुटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड के रोजा एम ओर्टेगा ने इसका समंवय किया है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लोगों के स्वास्थ्य और पुरानी व गंभीर बीमारियों (हृदय संबंधी, कैंसर, मधुमेह आदि) की रोकथाम में डेयरी उत्पादों के योगदान पर मौजूदा शोध सामग्रियों की समीक्षा भी की गई है। बता दें कि दूध और डेयरी उत्पादों में कई पोषक तत्व होते हैं और पोषण के लिए आवश्यक प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए आदि की कमी को पूरा करने में मदद करता है।

वैज्ञानिकों ने की सिजोफ्रेनिया से संबंधित नए जीन की पहचान

मेलबर्न, प्रेट्र : लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय वैज्ञानिकों ने सिजोफ्रेनिया से संबंधित एक नए जीन की पहचान की है।

ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों और भारतीय शोधकर्ताओं के एक दल ने 3,000 से अधिक व्यक्तियों के जीनोम की खोज कर पाया कि जो लोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे, उनमें एक विशेष आनुवंशिक विविधता देखने को मिली। भारतीय शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व चेन्नई स्थित सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन के सह-संस्थापक और निदेशक रंगस्वामी थारा ने किया। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के ब्रायन मावरी ने कहा कि इससे पहले भी यूरोपीय लोगों में इस तरह के अध्ययन हो चुके हैं, जिनमें 100 से अधिक सिजोफ्रेनिया पीड़ितों की पहचान की गई थी।

उन्होंने कहा कि इस अध्ययन में जिस जीन की पहचान की गई है उसे एनएपीआरटी-1 नाम दिया गया है। जो विटामिन बी3 मेटाबोलिजम में शामिल एक एंजाइम को एनकोड करने में सक्षम है। मावरी ने कहा कि हमने सिजोफ्रेनिया के पीड़ितों में इस जीन के जोनोम पाए हैं। उन्होंने कहा 'जब हमने जेब्राफिश में इस जीन को खोजा तो पाया कि मछली का मस्तिष्क विकास बिगड़ा हुआ था। हम गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जीन मस्तिष्क में कैसे कार्य करता है।

क्या है सिजोफ्रेनिया : सिजोफ्रेनिया के मरीज वास्तविक दुनिया से कट जाते हैं। इस बीमारी से ग्रसित दो मरीजों के लक्षण हर बार एक जैसे नहीं होते। ऐसे में इस बीमारी का पता लगाना कठिन हो जाता है।

सिजोफ्रेनिया के मरीज एकांत में रहना पसंद करते हैं। प्रतीकात्मक

सिजोफ्रेनिया के कारण

आनुवंशिक: सिजोफ्रेनिया का इतिहास रखने वाले परिवार में इस बीमारी से ग्रस्त होने का खतरा ज्यादा रहता है।

वायरल संक्रमण : कुछ अध्ययनों के अनुसार वायरल संक्रमण के कारण बच्चों में एक प्रकार का पागलपन के विकास होने की संभावना ज्यादा रहती है।

कुपोषण : अगर गर्भावस्था के दौरान भ्रूण कुपोषण से ग्रस्त है तो ऐसे में वहां एक प्रकार का पागलपन विकसित होने का अधिक खतरा है।

तनाव: प्रारंभिक जीवन में गंभीर तनाव के कारण एक प्रकार के पागलपन के विकास होने का खतरा रहता है।

अंतरराष्ट्रीय

न्यूज गैलरी

अगले हफ्ते तुर्की पहुंचेगी रूस की एस-400 रक्षा प्रणाली

इस्तांबुल : अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से पहली एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली अगले हफ्ते तुर्की पहुंच जाएगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस रक्षा प्रणाली को रूसी वायुसेना के एक ठिकाने पर रविवार को दो मालवाहक विमानों में लादा जाएगा। एस-400 की तैनाती के लिए रूस की विशेष टीम भी सोमवार तक तुर्की पहुंच जाएगी। रूस से यह रक्षा प्रणाली खरीदने के फैसले के बाद तुर्की और अमेरिका के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। अमेरिका ने नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) सहयोगी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकी दी है। अमेरिका का कहना है कि एस-400 से उसके एफ-35 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को एफ-35 विमान बनाने के समझौते से भी बाहर करने की धमकी दी है। (रायटर)

हेलीकॉप्टर हादसे में अरबपति अमेरिकी उद्यमी की मौत

वाशिंगटन : बहामा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अमेरिकी कारोबारी क्रिस्टोफर क्लाइन और उनकी बेटी समेत सात लोगों की मौत हो गई। कोयला क्षेत्र के बड़े कारोबारी क्लाइन को फोर्ब्स मैगजीन ने शीर्ष अरबपति उद्योगपतियों की सूची में जगह दी थी। उनकी संपत्ति 1.8 अरब डॉलर (करीब 12,300 करोड़ रुपये) आंकी गई थी। फ्लोरिडा के नॉर्थ पाम बीच इलाके में रहने वाले क्लाइन का हेलीकॉप्टर बहामा द्वीप से उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर अटलांटिक महासागर में समा गया। (रायटर)

मदीना पहुंचा भारतीय हज यात्रियों का पहला दल

मदीना : भारतीय हज यात्रियों का पहला दल गुरुवार को एक चार्टर्ड विमान से सऊदी अरब के मदीना शहर पहुंचा। 419 हज यात्रियों के साथ इस विमान ने बुधवार देर रात नई दिल्ली से उड़ान भरी थी। सऊदी अरब में भारत के राजदूत औसाफ सईद, वाणिज्यदूत नूर रहमान शेख ने यहां प्रिंस मुहम्मद बिन अब्दुलअजीज हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। अधिकारियों के अनुसार, हज यात्री कुछ दिन तक मदीना में रहने के बाद 12 जुलाई को मक्का के लिए रवाना होंगे। (आएएनएस)

तेल टैंकर नहीं छोड़ने पर ईरान ने दी पोत जब्त करने की धमकी

▶ अमेरिका के कहने पर जिब्राल्टर में तेल टैंकर पकड़ने का लगाया आरोप

तेहरान, एएफपी/रायटर : ईरान के विशेष बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहसिन रेजाई ने धमकी दी है कि अगर ब्रिटेन ने ईरानी तेल टैंकर नहीं छोड़ा तो उसके किसी पोत को जब्त कर लिया जाएगा। ईरान सरकार ने ब्रिटेन से जिब्राल्टर में पकड़े गए अपने तेल टैंकर को तुरंत छोड़ने की मांग भी की है। साथ ही आरोप लगाया कि अमेरिका के कहने पर तेल टैंकर पकड़ा गया। ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र वाले जिब्राल्टर द्वीप के पास गुरुवार को 330 मीटर लंबे ग्रेस-1 नामक तेल टैंकर को यूरोपीय यूनियन (ईयू) के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर कच्चा तेल सीरिया ले जाने के संदेह में पकड़ा गया था।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिटेन के राजदूत रॉब मैकेयर को तलब कर इस घटना पर विरोध दर्ज कराया गया है। उन्हें यह भी बताया गया कि ब्रिटेन का कदम अस्वीकार्य है। तेल टैंकर को तुरंत छोड़ा जाए। ईरानी तेल टैंकर को ऐसे समय पर पकड़ा गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है।

जिब्राल्टर में पकड़ा गया है टैंकर। प्रतीकात्मक

चालक दल के सदस्यों में ज्यादातर भारतीय

लंदन : जिब्राल्टर द्वीप में पकड़े गए ईरानी तेल टैंकर के चालक दल के सदस्यों में ज्यादातर भारतीय हैं। इनके अलावा कुछ पाकिस्तानी और यूक्रेनी नागरिक हैं। जिब्राल्टर के प्रवक्ता के अनुसार, तेल टैंकर के 28 सदस्यीय चालक दल से लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्हें तेल टैंकर पर ही रखा गया है।

छात्रों ने ठुकराया हांगकांग की नेता कैरी का वार्ता का प्रस्ताव

हांगकांग, एपी : चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र हांगकांग के छात्रों ने शहर की प्रमुख कैरी लाम का वार्ता प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लाम ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर बातचीत के लिए दो विश्वविद्यालयों के छात्रों को बंद दरवाजे के पीछे वार्ता का न्योता दिया था। छात्रों का कहना है कि बातचीत सार्वजनिक मंच पर होनी चाहिए और उसमें सभी तबकों को शामिल किया जाना चाहिए।

यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की छात्र यूनियन के सदस्य जार्डन पेंग ने कहा, 'बंद दरवाजे में की गई बात का कोई प्रमाण नहीं होता। जनता तक कोई बात नहीं पहुंच पाती।' नए प्रत्यर्पण कानून में संदिग्धों और अपराधियों को मुकदमे के लिए सीधे चीन में प्रत्यर्पित करने का प्रावधान है। लोग इसे हांगकांग की स्वायत्तता पर खतरा बता रहे हैं। इसके विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसी के दबाव में लाम ने विधायी परिषद में संबंधित बिल पर चर्चा टाल दी थी। प्रदर्शनकारी इस बिल को पूरी तरह रद करने के साथ लाम के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।

पर्यटकों को मुफ्त सिम कार्ड देगा संयुक्त अरब अमीरात

दुबई, प्रेट्र/आइएएनएस : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अपने यहां आने वाले सभी पर्यटकों को मुफ्त में मोबाइल फोन का सिम कार्ड देगा। एक माह के लिए वैध इस सिम कार्ड में मुफ्त 20 एमबी डाटा, इंटरनेशनल कॉल और मैसेज की सुविधा होगी। अगर कोई पर्यटक अपने वीजा की अवधि बढ़वाता है तो सिम कार्ड की अवधि भी अपने आप बढ़ जाएगी।

गल्फ न्यूज के अनुसार, यूएई के पहचान और नागरिकता मामले के संघीय प्राधिकरण ने यह घोषणा की है। यूएई आने वाले पर्यटकों को मुफ्त सिम कार्ड मुहैया कराने के लिए प्राधिकरण ने संचार कंपनी टेलीकॉमनाउ के साथ बीते मंगलवार को एक करार किया। टेलीकॉमनाउ के चेयरमैन और सीईओ कारबेल फवाज लितानी ने बताया कि यूएई पहुंचने पर पर्यटकों को पासपोर्ट कंट्रोल अधिकारियों से उपहार के तौर पर सिम कार्ड मिलेगा। जितने समय तक वीजा की वैधता रहेगी, उतने वक्त तक यह सिम कार्ड काम करता रहेगा।

पिछले साल 20 लाख भारतीय पहुंचे थे दुबई : दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 में 20 लाख से ज्यादा भारतीय दुबई पहुंचे थे।

यूएई में भारतीय महिला इंजीनियर ने जीती 22 करोड़ की लॉटरी

दुबई, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में बतौर इंजीनियर कार्यरत भारतीय महिला सपना नैयर ने 1.2 करोड़ दिरहम (करीब 22 करोड़ रुपये) की इनामी राशि वाली बिग टिकट अबूधाबी लॉटरी जीती है। यूएई की इस सबसे बड़ी और पुरानी लॉटरी का ड्रा हर माह अबूधाबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निकाला जाता है। मूल रूप से केरल की रहने वाली सपना ने कहा है कि वह इस रकम का एक हिस्सा वंचित तबके की महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च करेंगी। सपना अपने पति और पांच साल की बेटी के साथ अबूधाबी में रहती हैं। सपना ने कहा कि इतनी बड़ी लॉटरी लगने का उन्हें पहले यकीन नहीं हो रहा था।

अफ्रीका के मुस्लिम देश ट्यूनीसिया में नकाब पर प्रतिबंध

ट्यूनिस, एएफपी : अफ्रीका के मुस्लिम देश ट्यूनीसिया ने शुक्रवार को महिलाओं के चेहरे को ढंकने वाले नकाब के पहनने पर रोक लगा दी। ट्यूनीसिया ने यह कदम आतंकी हमलों से सुरक्षा के मद्देनजर उठाया है। 27 जून को ट्यूनिस में हुए दो आत्मघाती हमलों में दो लोग मारे गए थे और सात घायल हुए थे।

नकाब पर प्रतिबंध का सरकारी आदेश प्रधानमंत्री यूसेफ चाहेद के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। आदेश में सुरक्षा कारणों से देश के सभी स्त्री-पुरुषों के लिए चेहरा खुला रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। मानवाधिकारों से जुड़ी संस्था ट्यूनीसियन लीग ने सरकार से अनुरोध किया है कि यह प्रतिबंध अस्थायी होना चाहिए।

लीग के अध्यक्ष जामेल मुसल्लम ने कहा है कि हमें इच्छानुसार पोशाक पहनने की आजादी है लेकिन आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए यह निर्णय गया है। उल्लेखनीय है कि ट्यूनीसिया की 99 फीसद आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। देश की कुल आबादी 1.15 करोड़ है।

सैन्य परेड के साथ ट्रंप ने मनाया स्वतंत्रता दिवस

वाशिंगटन, प्रेट्र : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा से अलग हटकर गुरुवार को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस सैन्य परेड के साथ मनाया। परेड में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और टैंकों को प्रदर्शित किया गया। इस खास मौके पर उन्होंने भाषण भी दिया। वह पिछले 70 सालों में ऐसा करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप देश की आजादी का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अमेरिका को चार जुलाई, 1776 को ब्रिटेन से आजादी मिली थी।

राजधानी वाशिंगटन स्थित लिंकन मेमोरियल से अपने 47 मिनट के संबोधन में ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा देश आज जितना मजबूत है, उतना पहले कभी नहीं था। यह अमेरिकी सैनिकों और जनरलों को सलाम करने का अवसर है।' इस सैन्य परेड में बमवर्षक बी-2 और एफ-35 लड़ाकू विमानों ने वाशिंगटन के आसमान में उड़ान भरी। इसके अलावा नवीनतम अब्राम और शर्मन टैंक भी प्रदर्शित किए गए।

वाशिंगटन स्थित लिंकन मेमोरियल पर अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विमानों के करतब को निहारते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया, उपराष्ट्रपति माइक पेंस और अधिकारी। रायटर

सैन्य परेड की परंपरा नहीं

अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस पर सैन्य परेड की परंपरा नहीं है। ट्रंप के पूर्ववर्ती भी स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूर रहे। इस दिन आमतौर पर आतिशबाजी होती है। वाशिंगटन में एक बार सैन्य परेड खाड़ी युद्ध समाप्त होने के बाद जून, 1991 में हुई थी।

2017 में आया खयाल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सैन्य परेड का खयाल 2017 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्तील डे में शामिल होने के वक्त आया था। हालांकि तब उन्हें विरोध के चलते इस खयाल को छोड़ना पड़ा था।

सेना को सराहा

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मौके पर अमेरिकी सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम अपने इतिहास, हमारे लोगों और हमारे नायकों के सम्मान में जश्न मनाते हैं जो गर्व से हमारे झंडे की रक्षा करते हैं। उधर, विरोधियों ने ट्रंप पर फिर से चुनाव अभियान से पहले छुट्टी का राजनीतिकरण करने और करदाताओं के पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों ने जलाया अमेरिकी ध्वज

ट्रंप के संबोधन के दौरान ह्वाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी ध्वज जलाया। इस दौरान ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में खुफिया सेवा के दो अधिकारी घायल हो गए।

अमेरिका में भूकंप से फटी धरती

कैलिफोर्निया प्रांत की सियरलेस घाटी के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। कई स्थानों पर धरती में दरारें आ गईं। रेगिस्तानी इलाके रिगक्रेस्ट में फटी धरती को दिखाता स्थानीय निवासी। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, रियेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। रायटर